खण्ड-208, अंक-6
मंगलवार, 8 पौष, शक संवत् 1881
(29 दिसम्बर, 1959 ई0)

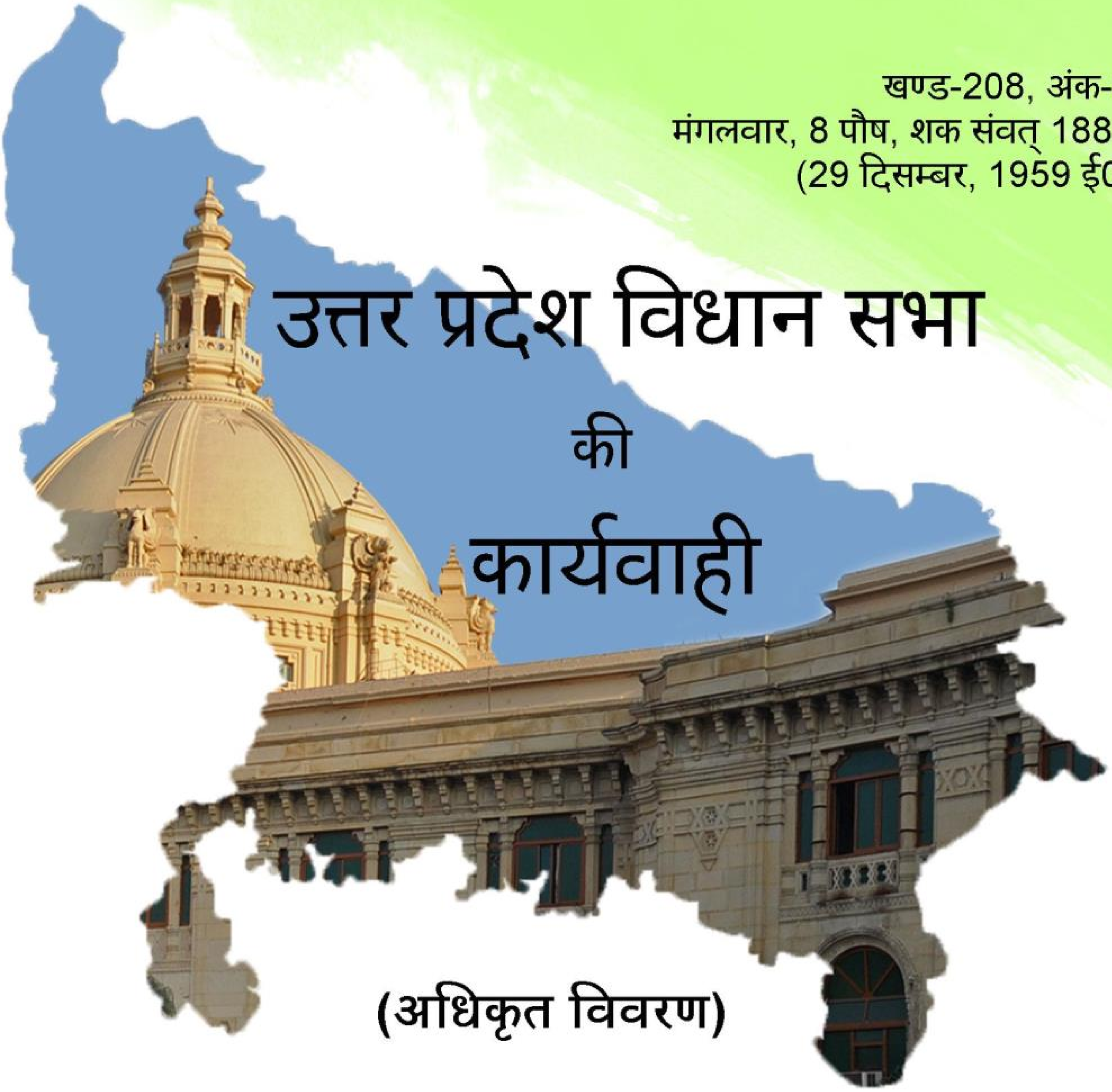

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

मंगलवार, २९ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपालो, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर, वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनसिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फ़र्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनन्दोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्री कृष्ण गोयल, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २९ दिसम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कुछ पर्वतीय स्थानों पर कथित विचित्र प्रकाश

**१--श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा व गढ़वाल में स्थित त्रिशूल, पंचचूली, नंदादेवी हिमालय पर्वतों के बीच पिछले १ महीने से एक अजीब रोशनी दिखायी देने लगी है और इस साल अप्रत्याशित रूप से इन स्थानों के करीब बर्फ़ पिघली है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इधर एक दम बोर्डर पर तिब्बत में जहां पर यह जगह पड़ती है वहां पर चीनी लोग जमाहैं और उसमें कैम्प लगे हैं और वह रोशनी फेंकने का प्रयोग कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कैम्प के संबंध में जो चाहे सूचना हो लेकिन बरफ पिघलने की बाबत और रोशनी की बाबत अगर इनमें कोई संबंध है, तो उसका मुझे पता नहीं है और ऐसी रोशनी का हमें पता नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मुख्य मंत्री जी ने वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की जांच कराने की कृपा की है कि ऐसा एटोमिक विस्फोट हो सकता है, जिससे काफी एरिया में बरफ़ पिघल सकती हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, अगर ऐसी कोई शक्ति किसी मनुष्य को प्राप्त हो गई हो जिससे कई सौ मील तक बरफ़ पिघल सकती हो तो उसका मुझे तथा सरकार को पता नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी ने १७ दिसम्बर का एक अखबार "साप्ताहिक पर्वतीय" देखा है जिसमें दिया हुआ है कि "ग्वालदम से दिखाई देने वाले हिमालय के नन्दा घुंगठी पर्वतमाला के मध्य से; नवीन मार्ग निर्माण की सी स्पष्ट रेखा दृष्टिगोचर हो रही है"। मैं इसको छोड़े देता हूं। इसमें आगे है-- "सम्भवतः चीनियों द्वारा पर्वत पर हिम गलाने के लिये कुछ वैज्ञानिक अणु भी रात्रि में फेंके जा रहे हैं"? यदि हां, तो इसकी कोई खोज सरकार की ओर से की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, समचार भी मिला है और इसकी खोज करने पर यह सूचना नराधार पाई गई और हम समझते हैं कि भारत के वैज्ञानिक चीनी वैज्ञानिकों से कहीं आगे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी इसको निराधार मान कर भी जनता में आतंक फैलने के कारण सत्य का पता लगाकर जनता को बताने की कोशिश करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सत्य का पता लगाकर ही मैंने निवेदन किया है; और मैं समझता हुं कि अखबारों के जरिये सब जगह यह चीज लोगों तक पहुंच जायगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केवल प्रश्न पूछ कर उनको सूचना दी गई या उन्होंने (श्री विष्ट ने) उन्हें पत्र भी लिखा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि लिखा हो तो मेरे पास वह अभी तक पहुंचा नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*१---**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---[स्थगित।]

*२-४---**श्री हिम्मत सिंह** (जिला बुलन्दशहर)---[स्थगित।]

पार्ट टाइम सब-रजिस्ट्रार

*५---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के रजिस्ट्रेशन विभाग में नियुक्त कितने पार्ट टाइम सब रजिस्ट्रारों को इस वर्ष स्थायी किया गया तथा कितने रजिस्ट्रेशन क्लर्क मुस्तकिल हुये और वहां कितने लिपिकों की नई नियुक्तियां हुई ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री महमूदअली खां)---इस वर्ष किसी पार्ट टाइम सब रजिस्ट्रार को स्थायी नहीं किया गया और न इस सिलसिले में कोई रजिस्ट्रेशन क्लर्क मुस्तकिल किया गया और न किसी लिपिक की मुस्तकिल तौर पर नई नियुक्ति की गई। गैर मुस्तकिल तौर पर किसी रजिस्ट्रेशन क्लर्क की नियुक्ति हुई या नहीं इसकी सूचना इस समय मौजूद नहीं है।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में कुल कितने सब रजिस्ट्रार तथा लिपिक अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)---मेरे खयाल में पार्ट टाइम सब-रजिस्ट्रार तकरीबन पचास के होंगे जो गैर मुस्तकिल हैं।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह लोग किन कारणों से स्थायी नहीं किये गये ?

श्री सैयद अली जहीर---हमारे यहां जो इकोनोमी कमेटी बैठी थी उसकी कुछ इस किस्म की सिफारिश थी कि कुछ दिनों के लिए नये सब रजिस्ट्रारों की भर्ती बन्द कर दी जाय और उसी पर अमल करके नये सब रजिस्ट्रार भरती नहीं किये गये बल्कि क्लार्क्स को पार्ट टाइम सब रजिस्ट्रार का काम दे दिया गया। इकानोमी के प्वाइंट आफ व्यू से वह अभी तक चलते रहे हैं। लेकिन सरकार अब विचार कर रही है कि कुछ फुल टाइम सब रजिस्ट्रार फिर भर्ती किये जायं और फिर मुस्तकिल किये जायंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---यह जो लोग मुस्तकिल नहीं किये गये हैं इनको कब तक मुस्तकिल कर देने का विचार है और कितने प्रतिशत इसमें मुस्तकिल किये जायेंगे ?

श्री सैयद अलीजहीर--इस वक्त तो यह विचार है कि आठ या नौ और फुल टाइम सब रजिस्ट्रार मुस्तकिल किये जायंगे। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे और भी लिये जायंगे।

श्री अमरनाथ--मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या गैर मुस्तकिल क्लर्कों की नियुक्ति की सूचना पुनः मंगा कर दी जायगी ?

श्री सैयद अलीजहीर--माननीय सदस्य अगर जानना चाहेंगे और फिर सवाल करेंगे तो मैं जरूर मंगा दूंगा ।

*६-७--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--[तीसरे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १२-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८-९--**श्री सजीवन लाल** (जिला उन्नाव)--[स्थगित ।]

*१०-१२--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--[स्थगित ।]

*१३-१५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[स्थगित ।]

*१६--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)--[तीसरे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१७--**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह** (जिला पीलीभीत)--[स्थगित ।]

*१८--**श्री जगवीर सिंह** (जिला बुलन्दशहर)--[स्थगित ।]

गरौठा में रजिस्ट्री दफ्तर खोलने की प्रार्थना

*१९--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार अतारांकित प्रश्न संख्या १, दिनांक १० फरवरी, १९५९ व तारांकित प्रश्न संख्या ८६, दिनांक २८ जुलाई, १९५९ के उत्तरों के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गरौठा में भी रजिस्ट्री की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री महमूदअली खां--सरकार ने हाल ही में कुछ स्थानों, जिनमें गरौठा भी सम्मिलित है, में नए रजिस्ट्री दफतरों के खोलने के प्रश्न पर विचार किया था । लेकिन यह देखा गया कि गरौठा तहसील से सम्बन्धित रजिस्ट्री का कार्य इतना नहीं है कि वहां एक अलग रजिस्ट्री दफतर खोला जा सके । इसलिए यह प्रश्न इस समय स्थगित किया गया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि गरौठा तहसील की जनता को ७० मील रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है और उसकी काश्तकारी का नुकसान होता है, गरौठा में अगले वर्ष रजिस्ट्रेशन आफिस खोलने के लिए विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयदअली जहीर--जी हां, हम विचार तो बराबर कर रहे हैं और अगर हम समझेंगे कि जरूरत है तो जरूर वहां सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर खोल देंगे लेकिन अभी तक वहां काम इतना काफी नहीं कि सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर खोल दिया जाय । इसलिए नहीं खोला गया ।

*२०-२१--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--[स्थगित ।]

अतारांकित प्रश्न

गढ़वाल जिले के उत्तरी भाग में अश्वमार्गों पर व्यय

१—**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल जिले के उत्तरी वृत्त के अन्दर विगत दो वर्षों के अन्दर विभाग की ओर से कितने नये अश्व मार्ग बनाये गये और कितने पुराने अश्व मार्गों की मरम्मत हुई और इन पर कुल कितना खर्चा लगा ?

श्री सैयद अलीजहीर—गत दो वर्षों में उत्तरी गढ़वाल डिवीजन में १७ नये अश्वमार्गों का निर्माण हुआ और ३४ पुराने अश्वमार्गों की मरम्मत की गई। नये मार्गों के निर्माण पर ९०,३२३ रु० तथा पुराने मार्गों की मरम्मत पर ३२,२५८ रु० खर्च हुआ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री ओंकारनाथ उपाध्याय ने शपथ ग्रहण की।

डाक्टर सीताराम के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में देवनारायण जी भारतीय ने प्रश्न भेजा है। मैंने उसको देखा। डा० सीताराम ने जो उत्तर दिये वह जिले से प्राप्त की जानकारी के आधार पर दिये हैं। कोई ऐसी बात का सबूत नहीं है कि जिला अधिकारियों की जानकारी भिन्न किस्म की आयी हो और उन्होंने उत्तर दूसरे किस्म का दिया हो, क्योंकि मंत्रीगण प्रश्नों के जो उत्तर दिया करते हैं वह जिलों से जानकारी हासिल करके देते हैं। इस बात को यहां पर बार-बार कहा भी गया है। ऐसी अवस्था में उनके ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जिले के जिलाधीश से पूछा और .....

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं देता हूं। आपका कहना सही हो सकता है और उनका कहना गलत भी हो सकता है लेकिन विशेषाधिकार की अवहेलना तो भी नहीं होती क्योंकि जान-बूझ कर असत्य बात नहीं कही गई थी।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा निवेदन यह है कि जिले के अधिकारियों ने उनको यह सूचना नहीं दी। मैंने जिलाधीश से और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से दोनों से अलहदा-अलहदा पूछा। उनका कहना है कि हमसे न कुछ पूछा गया और न हमने कोई सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—इसके लिए जब आपको कोई जानकारी नयी हासिल हुई हो कि उन्होंने जिले की बगैर जानकारी के उत्तर दिया है तो आप पहले प्रश्न सदन में पूछ लें और उनको कमिट करा लें कि वह सूचना उनको जिले से मिली या नहीं और आप जरूरी समझें तो प्रश्न उठावें। अभी तो उनका ही कहना माना जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करूंगा। हमेशा के लिए आप कोई व्यवस्था कर दें। जिले के अधिकारी लोग जो सरकार के पास सूचना देते हैं अगर निश्चित रूप में वह सूचना गलत होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जायगी ? सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सरकार जिम्मेदार है। जनतन्त्र में यही परम्परा मान्य है।

श्री अध्यक्ष—आप मंत्री जी से यह आशा अवश्य कर सकते हैं कि अगर जिले के अफ़सरान गलत इत्तिला देते हैं तो मंत्री उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे यानी अपने अधिकारी के विरुद्ध, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न मंत्री के खिलाफ़ नहीं उठ सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप भी कोई व्यवस्था करेंगे क्योंकि जैसा भारतीय जी ने कहा कि उन्होंने कोई खबर ही नहीं दी और वह कहते हैं कि हमारे पास खबर आई; जब इस प्रकार के दो परस्पर विरोधी समाचार पहुंच रहे हैं तो सदन कैसे ऐसी स्थिति में आयेगा...

श्री अध्यक्ष—हां, आ सकता है। वह यह प्रश्न पूछें कि मुझे यह जानकारी हासिल हुई है कि मंत्री जी को अमुक खबर नहीं दी गई फिर भी उन्होंने खुद अपनी ही ओर से गढ़ कर असत्य जवाब दे दिया क्या यह बात सही है? ऐसा प्रश्न वह सदस्य पूछ सकते हैं। फिर दूसरी दफ़ा जब तहकीकात के बाद यदि उनको भिन्न सही खबर मिली होगी तो वह बता देंगे और सदन से माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था, माननीय मंत्री जी ने कोई गलत बात कही थी और वह गलत बात जिन्होंने कही थी वे गृहमंत्री जी के ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने कही थी, बाद में उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि मैंने ऐसी बात अनजाने में गलत कह दी थी।

श्री देवनारायण भारतीय— मेरा निवेदन यह है कि जो एक्साइज विभाग के अधिकारी उस तस्कर व्यापारी से मिले हुए हैं और जब जब स्थानीय पुलिस ने.....

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा सवाल आप उठा रहे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं सूचना के ही सम्बन्ध में कह रहा हूं। जो सूचना प्राप्त हुई है वह एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने ही केवल अपने बचने के लिए माननीय मंत्री जी को गलत सूचना दी है और इस प्रकार माननीय मंत्री जी ने उनकी सूचना के आधार पर जो कुछ कहा है, वह कहा है। जिलाधीश ने और सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी थी। अब मेरा निवेदन यह है कि वह एक्साइज अधिकारी उधर तो गलत काम करते हैं...

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपा करके बैठें। बहस करने के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप अपने मुंह से कबूल इस बात को कर रहे हैं कि मंत्री निर्दोष हैं। एक्साइज वाले जो हैं उन्होंने उनको गलत खबर दी, धोखा दिया और जो कुछ किया, यह अफ़सरों के ऊपर चार्ज हो गया। तो वह अगर धोखा देते हैं तो मंत्री उनके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं और इस आदरणीय सदन को भी, मैं देखूंगा कि उन अफ़सरों के ऊपर क्या कार्यवाही करने का अधिकार है।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी ने सदन में यह कहा कि हमको जिलाधीश से यह सूचना मिली है। उनके स्टेटमेंट में यह है। मैंने उनको उस समय भी चैलेंज किया था।

श्री अध्यक्ष—तो वह आप प्रश्न कीजिए उस पर—शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर लें आप और नहीं तो अगली सिटिंग में आपका प्रश्न आ जायगा और उस वक्त उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है।

श्री राजनारायण द्वारा अपने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा शार्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—मैंने कल ही भेज दिया था और मैं समझता हूं कि सम्बन्धित मंत्री अगर कल सदन बैठता है तो उसके ऊपर विचार कर लेंगे।

इन्टरमीडियेट बोर्ड का समय से पहले चुनाव कराने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष— अब नियम ५२ के अनुसार एक विषय श्री राजनारायण और श्री देवी प्रसाद जी मिश्र का है। रामायण राय जी का भी है। देवी प्रसाद जी मिश्र का कल भी आया था, लेकिन चूंकि उसको नहीं लिया जा सका तो देवी प्रसाद जी मिश्र ने आज भी उसको रिपीट किया है। वह माननीय शिक्षा मंत्री से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में जो उनके पास सूचना मौजूद हो वह सदन को दे दें।

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—मान्यवर, इन्टरमीडियेट बोर्ड वैसे एक स्वयं आटोनोमस संस्था है और वैसे ही उसके चुनाव इत्यादि जो होते हैं उनके कराने का अधिकार बोर्ड और उसके चेयरमैन को है। उत्तर प्रदेश के इन्टरमीडियेट बोर्ड का पुनर्संगठन सन् १९६० के जून में होना चाहिये। वर्तमान बोर्ड की अवधि २६ जून तक समाप्त हो जाने वाली है। इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ३ (सी) (ई०) के अन्तर्गत गैर-सरकारी संस्थाओं, इन्टरमीडियेट कालेज के चार प्रिन्सिपल, हाई स्कूलों के दो प्रधान अध्यापकों का चुनाव बोर्ड की सदस्यता के लिये होता है। इसके नियमों के अनुसार यह चुनाव कराये जाते हैं। बोर्ड के चेयरमैन को यह अधिकार है कि तिथि निश्चित करें। इस बोर्ड के चुनाव के लिये चेयरमैन ने १५ दिसम्बर नामांकन की तिथि निश्चित की है, १ फरवरी चुनाव के लिये रखी है और इस सम्बन्ध में वह उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि चुनाव जून तक हो रहे हैं और नामांकन की तिथि के जांचने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है और यह भी कहा गया है कि उन पत्रों को देखने की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। बात यह है कि जो नियम इन्टरमीडियेट बोर्ड के हैं उनके अनुसार कोई डेट स्क्रूटनी के लिये तय नहीं होती बल्कि इन्टरमीडियेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी होते हैं, जो नामांकन पत्र होता है उसकी स्क्रूटनी करते हैं और जो उम्मीदवार सही पाया जाता है उसकी लिस्ट छापकर लटका देते हैं और चुनाव के १५ दिन पहले यह सूची निकल जानी चाहिये। वह लिस्ट उनकी तैयार हो रही है और १५ जनवरी तक आउट होनी चाहिये। १५ जनवरी तक उनकी यह लिस्ट निकल जाने वाली है, यह सूचना मुझे मिली है।

एक बात यह कही गयी कि जाड़ों में पर्वतीय स्कूल बन्द रहते हैं और स्कूल बन्द रहने से उसमें बाधा पड़ती है। बात यह है कि इसमें स्कूल भाग नहीं लेते हैं। प्रिन्सिपल और हेड मास्टर इसमें हिस्सा लेते हैं। वे लोग अपने वोट को डाक द्वारा भेज देते हैं। चाहे वह अपने घरों पर रहें लेकिन वह अपना वोट डाक से भेज देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती।

वोटरों की सूची सभी स्कूलों और संस्थाओं के पास मौजूद है। चुनाव पहली फरवरी को होने चाहिये तो १५ जनवरी या उसके पहले ही यह सारी लिस्ट तैयार हो जायगी और लोग इसमें भाग ले सकेंगे।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—माननीय मंत्री जी ने कहा कि वोटरों की सूची स्कूलों के पास मौजूद है तो क्या एक स्कूल का प्रिन्सिपल होने के नाते मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उनको यह समाचार कैसे मिला कि हम लोगों के पास वह सूची है? हम लोगों के पास कोई सूची नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन्टरमीडियेट बोर्ड के सेक्रेटरी से जो सूचना मेरे पास आई है उससे पता लगा कर मैं यह निवेदन कर रहा हूं। उसी में यह लिखा है कि जहां तक वोटरों की सूची का प्रश्न है वह बोर्ड और मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं के पास है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--अगर सेक्रेटरी बोर्ड का मतलब यह है कि इम्तहान के सेन्टरों की सूची हम लोगों के पास है तो वह तो है लेकिन हर साल १०० नये रिकग्नीशन होते हैं तो उन नये रिकग्नीशन की सूची हमारे पास दो साल बाद भेजी जाती है, और इसके बगैर सूची अपर्याप्त है। तो वह कैसे कहते हैं कि हमारे पास सूची है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया था कि यह आटोनामस बाडी है और अपने रूल्स के मुताबिक वह काम करती है और जिस प्रकार की अब तक परम्परा रही है, जो लोग वोटिंग में भाग लेने के अधिकारी हैं उनकी सूची संस्थाओं के पास मौजूद हैं। अगर उसमें कोई चीज मौजूद नहीं है तो आप हमको बता दें और हम उनको फिर लिखेंगे कि हमारे पास ऐसी शिकायत आयी है। यह क्या मामला है ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि इस साल जो यह चुनाव हो रहा है यह किस परिस्थिति विशेष वश समय के पहले हो रहा है ? जिस प्रकार से पहले जून में चुनाव होता था उस प्रकार से उस समय क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२६ जून को वहां का बोर्ड समाप्त हो जायगा और उसके पहले यह चुनाव करा लेने चाहिये और चेयरमैन को यह अधिकार है कि वह उसकी डेट फिक्स कर लें। आपकी आज्ञा हो तो मैं यह नियम पढ़ दूं :

"The election to fill any vacancy amonst Principals of the Board which is to be filled by election by Principals of Intermediate Colleges not maintainned by Government or by Head Masters of High Schools not maintained by Government shall be held on such dates as the Chairman shall appoint."

चेयरमैन ने उसकी डेट निश्चित कर दी है। चूंकि २६ जून को उसकी अवधि समाप्त हो रही है इसलिये फरवरी में वह चुनाव करा रहे हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या शिक्षा संचालक जी स्वयं इस एलेक्शन को कंडक्ट करा रहे हैं ? यदि ऐसा है तो क्या दिक्कत है मंत्री जी को जून में एलेक्शन कराने में जब कि पर्वतीय स्कूल भी खुल जाते ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बता दिया है कि चेयरमैन को इसका अधिकार है।

श्री रामायणराय--चेयरमैन तो एजूकेशन डाइरेक्टर ही है।

श्री अध्यक्ष--आप रेक्वेस्ट करें कि ऐसा करने में हर्ज क्या है, तो ठीक होगा।

श्री रामायणराय--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब इन सदस्यों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है तो पर्वतीय स्कूल खुलने के बाद ही यह चुनाव हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को कोई अधिकार इसमें हस्तक्षेप करने का नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--जैसा कि अभी स्पष्ट हुआ है कि वोटर लिस्ट अभी पूरी तरह से किसी के पास नहीं है और मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातें कहीं कि १५ जनवरी तक सब कागजात वोटर्स के पास पहुँच जायंगे और उससे ऐसा मालूम हुआ कि वोटर लिस्ट भी १५ जनवरी नक पहुँचेगी, तो इन कठिनाइयों को देखते हुए क्या मंत्री जी शिक्षा संचालक द्वारा इंटरमीडियेट बोर्ड के इस एलेक्शन में यह कोशिश करेंगे कि यह चुनाव ऐसे समय हों जब कि वोटर लिस्ट भी दुरुस्त हो जाय और सारे दोष ठीक हो जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि गौरी शंकर राय जी ने मेरे उत्तर को पूरी तरह से सुना नहीं अथवा मैं समझा नहीं सका। मैंने यह नहीं कहा कि कोई कागजात पहुंच जाने वाले हैं। मैंने कहा था कि १५ जनवरी तक जो नामांकन पत्र स्वीकृत हैं और जो उम्मीदवार होने वाले हैं उनकी लिस्ट निकल जायगी। उसके बाद उनकी लिस्ट वह टांग देंगे। जहां तक वोटर सूची का सवाल है, मेरी सूचना यह है कि वोटर सूची भेजी जा चुकी है, जैसा कि सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में मुझे सूचना दी है। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि वोटर सूची में अगर कोई चीज कम रहती है तो, जैसा भारतीय जी ने कहा था, यदि आप मुझे वह बता दें तो मैं उसे सेक्रेटरी के पास भेज दूंगा कि हमारे पास यह सूचना आयी है कि वोटर सूची में यह कमी है और वह उसको देख लेंगे। हस्तक्षेप करने का जहां तक सवाल है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और न उसका कोई इरादा है।

श्री रामायणराय--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ९ की ओर दिलाता हूं। उसमें साफ लिखा हुआ है :-

"The State Government shall have the right to address the Board with reference to any of the works conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with which the Board is concerned." इत्यादि। सरकार को पूरा अधिकार है कि यदि वह चाहे तो इंटरफियर कर सके।

श्री अध्यक्ष--यह ऐड्रेस करने के लिये तो तैयार हैं। वह ऐड्रेस करेंगे, तो बोर्ड इगनोर नहीं कर सकता है। उसको जवाब देना पड़ेगा।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि इस चुनाव में ऐसे प्रिंसिपल भी खड़े हो रहे हैं जिनका टर्म अप्रैल और मार्च में समाप्त हो रहा है और अगर चुनाव पहले हो जाता है तो वे उसमें भाग ले सकेंगे। फिर यह मामला कोर्ट में भी जा सकता है और पूरा चुनाव इनवैलिड करार दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब उन्होंने यह जवाब दे दिया कि जो सूचना भी माननीय सदस्यों के पास हो वह उनके पास माननीय सदस्य भेज दें, तो वे उसको बोर्ड के पास भेज देंगे। यह ज्यादा हेल्पफुल है। आप अपना सुझाव उनके पास लिख कर भेज दें।

श्री राजनारायण--यह सूचना तो माननीय मंत्री जी के पास अवश्य होगी कि क्या ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि मार्च और अप्रैल में हट रहे हैं यानी अगर मार्च और अप्रैल के बाद चुनाव होते हैं तो वे खड़े नहीं हो सकेंगे और चुनाव इसीलिये जल्दी कराये जा रहे हैं, क्या सरकार के पास एसी जानकारी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे इसकी सूचना नहीं है कि मार्च और अप्रैल में कई प्रिंसिपल ऐसे हैं, सार्वजनिक विद्यालय के जो सरकार द्वारा कन्डक्ट नहीं होते हैं, जो रिटायर होने वाले हैं या नहीं। जहां तक चुनाव की तिथियों का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया कि वह आटोनामस बाडी है और उसका चेयरमैन उसकी तिथि निश्चित करता है। अब अगर और माननीय सदस्य कोई सुझाव मेरे पास भेजते हैं तो मैं उसे चेयरमैन के पास भेज दूंगा और वे उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि वोटरों की लिस्ट इन्कम्पलीट है और जो है वह दो साल पहले की है। तो क्या वे संचालक महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कृपा करेंगे कि नामीनेशन होने के पहले उस लिस्ट को कम्पलीट कर लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो जवाब दिया जा चुका है उसके बाद यह प्रश्न उठता नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी उन की सूची सदन की मेज पर रखने की कोशिश करेंगे जो कि मार्च और अप्रैल में रिटायर होने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरी इस शिकायत को कि जो दल इस समय पदासीन है वह अपने को पावर में रखने के लिये गड़बड़ी कर रहा है और चुनाव को समय से पहले ही करा रहा है, सूचना मान कर और इस अव्यवस्था को रोकने के लिये अपनी तरफ से चुनाव को हटाने के लिये लिखेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, यही दल है जो.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये । आप अपनी शिकायत लिख कर भेज दीजिये मंत्री जी के पास ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो इंटरमिडिएट एजूकेशन ऐक्ट है उसके ९वें सेक्शन के चौथे क्लाज में बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है---

"In any emergency which, in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken, the State Government may take such action in consistent with this Act as it deem necessary without the previous consultation with the Board, and shall forth with inform the Board thereof. .

तो नवें सेक्शन का चौथा क्लाज सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी विशेष परिस्थिति में जिसे वह उचित समझती है, बिना बोर्ड से पूछे हुए कह सकती है कि बोर्ड को इसके मुताबिक यह काम करना है । तो जब सरकार को बात अवगत हो गयी कि परिस्थिति विशेष है इसमें, चुनाव नहीं होना चाहिये । चुनाव अप्रैल मई में हो सकता है तो सरकार स्वतः इस नियम के मुताबिक ऐक्शन ले सकती है ।

श्री अध्यक्ष---कौन सी सरकार ? सोशलिस्ट पार्टी की सरकार ? (हंसी)

श्री राजनारायण---वह तो श्रीमन्, आने वाली है लेकिन मेरा मतलब जो वर्तमान सरकार है, उससे है ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने यह कबूल ही नहीं किया है कि उनको मालूम है ।

श्री राजनारायण---अब इतनी सूचना तो उन्हें मालूम हो ही गयी है कि ऐसा हो रहा है और उसमें लिखा हुआ है-- 'Without previous consultation of the Board.

श्री अध्यक्ष---जब सरकार को मालूम हो जायेगा तब वह कर सकती है ।

श्री उग्रसेन---मालूम कराने का तरीका क्या है, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने इसके लिये स्पष्ट कह तो दिया है कि आप लोग उनको बतलायेंगे तो वह उनको ऐड्रेस करेंगे । लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आप की जो जानकारी हो, जैसा राजनारायण जी ने कहा और जो जानकारी उनको न हो वह उसको स्वीकार ही कर लें । राजनारायण जी के कहने का मतलब तो यही है कि उनको जो बातें मालूम हो गयीं वह मानना चाहिये कि सरकार को भी मालूम हो गयी हैं ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। जब नामीनेशंस १५ तारीख को तय करेंगे और वह उसको भेजेंगे कैन्डीडेट्स के पास तो उसमें दो तीन दिन लगेंगे सूबे भर का क्षेत्र है तो पहली फरवरी के अन्दर कोई कैन्डीडेट सूबे भर में कैसे कन्वेंसिंग करेगा ? मैं क्या माननीय जी से निवेदन करूं कि वह कम से कम दो तीन महीने तक इस तारीख को हटा दें ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी भी इजाजत नहीं दूंगा। उन्होंने उत्तर दे दिया है कि आप इस सम्बन्ध में सब कुछ उनको लिख सकते हैं।

श्री उग्रसेन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष---यह एक सूचना श्री उग्रसेन की गिरफतारी के बारे में है। मैंने गृह मंत्री जी से पूछा था तो उनको यह जानकारी मिली है और उसके आधार पर उन्होंने मुझे यह सूचना दी है कि एक कामरोको प्रस्ताव में १९ तारीख को उनकी ऐरेस्ट हुई थी, ऐसा जिक्र किया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से उन्होंने जानकारी हासिल की और उसका जवाब यह है कि उग्रसेन जी १९ दिसम्बर को ऐरेस्ट नहीं हुए और यह भी गलत है कि वह उस रोज गिरफ्तार किये गये और फिर छोड़ दिये गये और फिर पकड़े गये। यह बात ऐसी नहीं हुई। इस कारण १९ तारीख को यह पीटे गये, या ड्रैग किये गये ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होता। वह २० तारीख को ऐरेस्ट हुए हैं ऐसी सूचना है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तार दिया था आप को भी और माननीय नेता सोशलिस्ट दल को भी।

श्री अध्यक्ष---जी हां, उसी के ऊपर तो मैंने इन्क्वाइरी की।

श्री उग्रसेन---१९ तारीख को दिन में मैं पकड़ा गया और दस बजे रात को छोड़ा गया और २० तारीख को फिर पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष---आपको ड्रैग किस रोज किया गया ?

श्री उग्रसेन---१९ तारीख को दस बजे रात को। दूसरे दिन मुझे फिर ऐरेस्ट किया गया लेकिन उस दिन मैंने उनसे, एस० डी० एम० सलेमपुर से पूछा कि किस दफा में मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो उन्होंने कहा कि दफा बाद में बतायेंगे और मुझे हिरासत में बैठाये रखा गया। २० तारीख को मुझे पौने तीन बजे फिर ऐरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी का वारण्ट भी नहीं था न २० को था, न २१ और न २२ को। जब २२ तारीख को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुझे जेल में मिले थे तो मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ कोई वारन्ट भी नहीं है तब २२ तारीख को वारण्ट आता है। तो मैं एस० डी० एम० सलेमपुर के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं, राइटिंग में बाद में दे दूंगा कि यह जो इनफारमेंशन मैंने दी है वह वाकया मेरे साथ गुजरा है।

श्री अध्यक्ष---आप तो अब बाहर आ गये हैं। आप मंत्री जी को भी बतला दें। मंत्री जी का भी, जब आप ऐसे स्टेटमेंट देते है तो उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि उसकी जांच करा के सही जानकारी हासिल करें।

श्री उग्रसेन---मंत्रीजी स्वयं उसकी जांच कर लें।

श्री अध्यक्ष---जी हां, जिला मैजिस्ट्रेट जैसी इत्तिला देते हैं खाली उसी से नहीं बल्कि स्वयं अन्य प्रकार से भी जांच कर के जान लें कि फैक्ट्स क्या हैं और वह सूचना सदन की अगली सिटिंग में दे दें। बस यह बात है।

समाचार-पत्रों में सदस्यों के नाम के साथ गलत पार्टी के प्रकाशन पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—मदन पांडेय जी ने एक शिकायत यह की है कि अखबारों में उनके नाम में स्वतंत्र प्रगतिशील विधान सभाई दल छप जाता है जब कि वह इस दल के सदस्य नहीं हैं। वह कहते हैं कि मैं सोशलिस्ट यनिटी पार्टी का सदस्य हूं। मैं समझता हूं कि उनकी शिकायत सिर्फ यही है कि अखबारों में उनके नाम के सामने सदस्य सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी ही छप जाया करे। इसलिये मैंने इसकी सूचना दे दी।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि इसी तरह से हम लोगों का नाम भी गलत छप जाया करता है।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर दें। जो लोग किसी पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में चले गये हों वह मेरे पास लिखित भेज दें तो मैं उनके नाम उस पार्टी में शामिल कर लूं। इस आधार पर मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता कि एक नेता कहे कि यह सदस्य मेरी पार्टी में है और दूसरा नेता कहे कि मेरी पार्टी में है लेकिन अगर वह स्वयं लिखित दे दें कि मैं इस पार्टी का हूं तो मैं परिवर्तन कर दूंगा।

श्री उग्रसेन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उग्रसेन जी की गिरफ्तारी की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें विशेषधिकार की अवहेलना हुई है और मैं इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप उठा सकते हैं, जिस वक्त वह स्टेज आयेगी और वह सूचना देंगे वहां से जानकारी करने के बाद। पूरे फैक्ट्स मालूम हो जाने पर आप प्रश्न उठा सकेंगे, उसका मौका मैं आपको दूंगा।

श्री गेंदासिंह—मैं समझता हूं कि जितनी सूचना इस वक्त तक आ चुकी है उससे यह प्रश्न उठने का समय आ गया है।

श्री अध्यक्ष—अभी इस सम्बन्ध में पूरी सूचना जांच के बाद दी जायगी। आपने नोटिस तो दे ही दी।

कानपुर गोलीकांड जांच कमीशन के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चार्थ समय-निर्धारण

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कानपुर इंक्वायरी कमीशन जो बैठा है उसके आधार पर सदन के प्रथम दिन ही मैंने दफा ५३ के अन्तर्गत लिखित रूप में सूचना दी थी और वह अभी तक आपके निश्चय के लिये पेंडिंग है।

श्री अध्यक्ष—उस पर मैंने अभी फैसला नहीं दिया है। मैं देख रहा हूं कि उसमें औचित्य है या नहीं। उस सम्बन्ध में मैं अपना फैसला दूंगा। अभी बहस चलने दी जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मैं आशा करूं कि सदन अभी जो बैठ रहा है इसके काल में ही आपका निश्चय हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—जी हां ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, क्या सदन आज के अलावा भी बैठ रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह मैं भी जानना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री बतायें क्या सदन कल भी बैठेगा ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने यह बात कही थी कि अगर २९ तारीख को बैठक समाप्त हो जाय तो अच्छा है लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि सदन कल भी चले इसलिये मैं उनकी इच्छा का निरादर नहीं कर सकता । इसलिये कल सदन बैठेगा ही ।

श्री अध्यक्ष—तो अब मैं यह फैसला देता हूं कि इस वक्त जो बहस चल रही है उसकी समाप्ति पर गन्ने के सम्बन्ध में दो घंटे बहस होगी । जहां तक कानपुर से सम्बन्धित प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्री अवस्थी जी ने दिया था उसमें मैंने उनसे कह भी दिया था कि अगर उसमें मैं कोई संशोधन करूं तो उसे आपको स्वीकार करना होगा क्योंकि बहस से किसी किस्म का कोई आक्षेप वहां जो कमीशन मुकर्रर हुआ है उस पर या उसके कार्य पर नहीं आना चाहिये । सिद्धान्त के बारे में ही केवल इस पर बहस होगी और इसके लिये मैं कल एक घंटा दे दूंगा । आज तो जो बहस है वह चलती ही रहेगी और गन्ने के सम्बन्ध में कल ही दो घंटे निश्चित हो गये थे और एक घंटा कानपुर के सम्बन्ध में भी आज निश्चित हो गया । लेकिन अगर यह बहस कुछ पहले समाप्त हो जाती है, तीन चार घंटे बच रहते हैं तो मैं गन्ने के सम्बन्ध में ढाई घंटे तक समय बढ़ा दूंगा और कानपुर के लिये भी डेढ़ या दो घंटे कर दूंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बतलाया कि इस तरह से आप कार्यसूची रखेंगे वह तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें केवल इतना परिवर्तन कर दिया जाय कि आज ५ बजे कार्य समाप्त होने पर २ घंटे के लिये गन्ने वाला विषय लिया जाय और कल भी ५ बजे तक चीन पर बहस हो कर १ घंटे के लिये कानपुर वाला विषय ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—तो इसका मतलब है कि कल दोपहर तक ही इस बहस को खत्म कर दिया जाय ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—जी नहीं, पालीवालजी का मतलब है कि कल ५ बजे तक चीन का विवाद चलकर उसके बाद कानपुर वाला लिया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जी हां ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—तो आज ५ बजे तक इस प्रस्ताव पर बहस रहेगी, चीन वाले पर । उसके बाद नियम ५३ के अनुसार गन्ने के विषय पर २ घंटे बहस होगी । कल ५ बजे तक चीन का विषय रहेगा और उसके बाद १ घंटे के लिये कानपुर वाला विषय होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो कार्यक्रम के दूसरे कार्य नहीं लिये जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यही है । अगर आप कोई अन्य सरकारी कार्य भी लिवाना चाहते हैं तो मैं मुख्य मंत्रीजी को मनवा लूंगा ।

चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव–(क्रमागत)*

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन करता हूं कि प्रस्तुत प्रस्ताव की पंक्ति १ के शब्द "द्वारा व भारत" के बीच शब्द "जो प्रसिद्ध बांदुंग सम्मलन के पंचशील सिद्धांत से आबद्ध है" रख दिये जावें तथा पंक्ति ५ के शब्द "ठहराने" के आगे शब्द "भारतीय सीमा रक्षकों को अकारण हताहत कर उनके साथ अमानुषिक निर्दय व्यवहार करने" शब्द बढ़ा दिये जायं और इसी पंक्ति के अन्तिम शब्द "तथा" के आगे शब्द "भारत सरकार की शान्ति नीति व दृढ़ सीमा-रक्षा-व्यवस्था के संकल्प का समर्थन करता है" और बढ़ा दिय जायं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल से यह विवाद चल रहा है और मैंने बड़ी गम्भीरता और धैर्य के साथ इसे सुना है। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। सीमा-विवाद पर आलोचना करने के पहले हमें गम्भीरता से विचार कर लेना चाहिये कि भारत सरकार की नीति सही है या गलत है। अभी आपने देखा कि उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम चारों दिशाओं के बड़े-बड़े महान् राष्ट्रों के बड़े-बड़े नेता यहां आते हैं। आज ख्रुश्चैव साहब या आइसनहावर साहब जरा सी आग लगने पर ही सारे विश्व को मिटा सकते हैं, ऐसे-ऐसे हथियार उनके पास हैं। ख्रुश्चैव साहब कहते हैं कि भारत हमारा परम मित्र है और विश्वसनीय उसकी शान्ति है। आइसनहावर साहब कहते हैं कि भारत हमारे सभी लोकतन्त्र राष्ट्रों में सबसे बड़ा राष्ट्र है और उसके हित में सारे लोकतन्त्र राष्ट्रों का हित है। भारत की शान्ति की नीति ने सारे मानव-समाज को राहत दी है। ये उन महान् पुरुषों के वाक्य हैं जो आज विश्व में महान् शक्तिशाली गिने जाते हैं। जहां वे पहले लड़ने पर उतारू रहते थे आज वहां शान्ति की खोज में हैं और इसी खोज में भारत आते हैं। आखिर क्यों ? गांधीजी की शान्ति व अहिंसा नीति केवल गांधीजी की शान्ति व अहिंसा नीति नहीं थी बल्कि वह नीति इस देश के मनीषियों की थी जो आदिम काल से अभी तक चली आई है और वह है "अहिंसा परमोधर्मः" "यतो धर्मस्तसो जयः" और "सत्यमेव जयते नानृतम्"। हमारे सभी राजा और शासक इसी नीति पर चले हैं। इसी पर हम आज भी कायम हैं। यह नीति किसने बनायी है ? यह उन मनीषियों ने बनायी है जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं चाहे वे शासक असुर के हों या देव के हों। यह नीति अपनाई है मानसरोवर तालाब पर जहां ब्रह्मा जी की तपोभूमि है और ५४ मील में वह फैली हुई है जिसकी गहराई ३,०००फीट है,। जहां पर नीलकमल उगता है, जिसे देखकर सारा मानवसमाज और देव समाज गद्गद हो जाता है वहां पर बैठकर उन्होंने इस बात पर विचार किया कि ये मनुष्य लोग अगर लड़ते हैं तो इस विश्व में एक ऐसी जगह भी होनी चाहिये जहां ये लोग लड़ न सकें। उसके लिये मानसरोवर से २० मील की दूरी पर कैलास पर्वत है जिसे हम कैलासपुरी कहते हैं, जिसकी परिक्रमा ३२ मील की है, इसे चुना गया और यहां पर शंकर जी का नृत्य होता है, उसके लिये श्लोक आया है :

"के शिरसि (शिवयोः) लासः नृत्यम् अस्मिन् इति कैलासः।"

इसमें कैलास शब्द की व्याख्या की गई है। 'के' अर्थात् मस्तक पर शिव पार्वती का जहां 'लास' अर्थात् नृत्य हुआ हो उसे 'कैलास' कहते हैं। कैलास पर्वत की चोटी पर शिव पार्वती का नृत्यस्थान माना जाता है। जब वहां भगवान शिव का पार्वती के साथ तान्डव नृत्य होता है तो हमारे मुंह से बर्बस निकलता है "हर हर महादेव"....

श्री अध्यक्ष—अब विषय पर आ जाइये।

श्री नारायणदास पासी—यह कैलासपुरी और दूसरी साकेत (अयोध्या) है। यहां पर भी कोई युद्ध नहीं होता है। तीसरा है काबा, वहां भी कोई युद्ध नहीं हो सकता है। इस तरह

*२८ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

[श्री नारायणदास पासी]

से ये ३ क्षेत्र अयुद्ध के विश्व में हैं, जिनकी परिक्रमा १४, १४ कोस के घेरे में है। तो चीन के साथ आखिर हमने क्या बुराई की जो वह क्रोध और अहंकार में सीमा का झगड़ा छेड़ रहा है? आप जानते हैं कि जिस समय पंचशील का निर्माण हुआ था उस समय हमारे सामने एक ही प्रश्न था। वह यह था कि दूसरे महायुद्ध के बाद जब लोक-तंत्रात्मक शक्तियां उठीं तो जो देश गुलाम थे उन्होंने अपनी आजादी के लिये प्रयत्न किया। हमारे पूज्य बापू जिनका कार्यक्षेत्र अफ्रीका में था उन्होंने यहां आकर अहिंसा और सत्य की अजय शक्ति को लेकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन किया और आजादी प्राप्त की। हम आजाद हो गये लेकिन पाकिस्तान के बटवारे के बाद। उसके लिये बड़ी कुरबानी हमें करनी पड़ी। हजारों-लाखों मनुष्य उस लड़ाई में मारे गये। देश क्षत-विक्षत हो गया। भारत के अतिरिक्त और राष्ट्र आजाद हुए ब्रह्मा, लंका, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि। वहां भी लोगों ने कुरबानी की और क्षत विक्षत हुए। वे भी गरीब थे पिछड़े हुए थे। चीन ने भी गृह युद्ध में काफी हानि उठायी। वह भी क्षत-विक्षत हुआ। ये सारे राष्ट्र बांडुंग में इकट्ठा हुए और उन्होंने मिल कर वहां पंचशील का निर्माण किया। उस पंचशील पर हिन्दुस्तान सदैव कायम रहा। उसके बाद मिस्र ने वहां के राष्ट्रपति नासिर के नेतृत्व में स्वेज का मामला उठाया। भारत ने उसका समर्थन किया और ब्रिटेन तथा पश्चिमी राष्ट्रों का कोपभाजन बना, उसने चीन का भी समर्थन किया जब वह कोरिया में जूझ रहा था। हम वहां पर शांति सेना भेजी। वहां पर भारत ने मेल कराया। इतना ही नहीं जब चीन का राष्ट्र संघ में बायकाट किया हुआ था और साम्यवादी ग्रुप या अन्य कोई भी उसको सदस्यता नहीं दिला सकता था भारत ने उसके लिये प्रयत्न किया और अभी तक उसके लिये बराबर युद्ध कर रहा है। यह क्यों? क्योंकि वह बांडुंग भावना से वचनबद्ध है उसको शांति की नीति अजर-अमर है।

इस तरह आप देखें कि यह तिब्बत की सीमा क्या है। कभी ऐसा समय इतिहास में नहीं आया जब तिब्बत की सीमा की बात उठायी गयी हो। अगर ऐसी बात होती तो आज हमारी सतलज, घाघरा, जमुना, गंगा, गंगोत्री, यमनोत्री और ब्रह्मपुत्र आदि सब नदियां जहां से निकलती हैं वह तिब्बत भगवान शंकर का क्षेत्र रहा है। इसलिए उसको हमेशा राजनीति से अलग ही रखा था। वह सदैव से शुद्ध आध्यात्मिक देश रहा। वहां युद्ध की कभी कोई बात न होती थी। इसलिये कभी भी भारत ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम यह विचार भी नहीं कर सकते थे कि तिब्बत की आड़ में चीन ऐसे नक्शे बनायेगा जो हिमालय के उस भाग को भी अपने में दिखायेगा जिससे हमारा भारतीय रक्त व बुनियादी संस्कृति तथा पवित्र नदियों का संबंध है और उसके द्वारा भारतीय जीवन पर कुठाराघात होगा। इसी प्रकार से लद्दाख क्षेत्र भी सदैव से शांति का स्थान रहा है। धर्म के विचार को छोड़ वहां बौद्ध और मुसलमानों की शादी होती है। जहां बौद्धों के साथ मुस्लिम स्त्रियों का शादी-ब्याह आपस में होता है वहां पर भारतीय सीमा के ऊपर हमारे उन सिपाहियों को जो कि घूम रहे थे, गश्त कर रहे थे बिना कारण मार दिया जाय, कैद कर लिया जाय और उनके साथ निर्दयता का व्यवहार किया जाय यह कोई मित्रता के मा` हैं? क्या मित्र इसी को कहते हैं? यह हमारे सोचने और समझने की बात है।

यही नहीं श्रीमन्, और जो हुआ सो हुआ, हमारे सामने उस समय एक भावना पैदा होती है कि आज सारा विश्व गांधी जी के बाद `हरू जी को अपना एक महापुरुष समझता है। इनको शान्ति-दूत के रूप में भारत की रूह समझता है। ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर जब कि शिशु दिवस मनाया जा रहा था जहां कि बच्चे एक-दूसरे का कान पकड़ कर झूम झूम कर प्रेम प्रकट करते हैं कहते हैं "च्याऊं-म्याऊं मकड़ी का जाला" तथा "चाचा नेहरू जिन्दाबाद" कह रहे थे उस समय भारत माता के एक बच्चे श्री त्यागी के हाथ में करम सिंह को लंगड़ा करके, उनके साथियों को घायल करके उन सिपाहियों के शव को वापस किया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे हृदय में कैसे भाव और कैसी भावना होती है कि हमारे मित्र कैसे हैं, इनको हम मित्र

कैसे समझें ? इस बात को देखते हुए हमें कोई ऐसी नई बात नहीं दिखलायी देती कि वे जब यह कहते हैं कि तुम यहां से हटो हमारा नक्शा ठीक है, हमने अभी कोई नक्शा नहीं पेश किया है हमारी तरफ से कोई बात नहीं हुई है, इसलिये आज हम कहते हैं कि इस बात के सोचने और समझने की जरूरत है कि चीन जो है वह जन-संख्या के लिहाज से विश्व का प्रथम राष्ट्र है और दूसरा राष्ट्र जो है वह हिन्दुस्तान है।

आज सारे विश्व की जनता भारत की और चीन की तरफ देख रही है। यदि वे इस विवाद को शान्ति के ढंग से हल कर लेते हैं तब तो सारे विश्व की भावना कि--

मानव गोरे पीले कारे। हम हैं मां के नैन के तारे ।।

तथा "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" का नारा भारत-चीन-तिब्बत को ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज को यह शान्ति देता है और अगर युद्ध होता है तो दुनिया का प्रलय होता है। ऐसी अवस्था में श्रीमन्, हमारे सामने जो समस्या पैदा होती है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां कि हमने यह प्रस्ताव पेश किया है इसकी आलोचना-प्रत्यालोचना करने के पहले हमें इस बात को गम्भीरता के साथ सोच लेना चाहिये कि आज जो बातचीत या समझौता हम करने जा रहे हैं आज जो कदम हम बढ़ायेंगे वह हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिये इतिहास में क्या स्थान रखेगा। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव पेश है वह एकांगी है और उसमें मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो वह प्रस्ताव पूर्ण हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रस्ताव है उसमें मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :--

"यह सदन चीनी कम्युनिस्ट सरकार .... राष्ट्र-विरोधी तत्वों को नष्ट किया जाना भी संभव हो सके" के आगे निम्नलिखित और बढ़ा दिया जाय--

"तथा सरकार उन राष्ट्र विरोधी तत्वों को जो जनता में आतंक पैदा करके देश के प्रति अश्रद्धा एवं अविश्वास फैलाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें युद्ध अपराधियों (war criminals) की तरह कठोरतम दंड देने की व्यवस्था करे"।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चीन का रवैया रहा है, जब हमारे राष्ट्र-नेता जवाहरलाल जी की नीति और भारतवर्ष की नीति ऐसी है कि हम लड़ाई से हटते जा रहे हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, वहां चीन की नीति ने तो बिलकुल इसको साबित कर दिया है कि चीन आज हमारे साथ युद्धरत है। बावजूद इन तमाम चीजों के कि चीन के लिये हमने कितना किया, पंचशील के सिद्धान्त को बनाया, जवाहर लाल जी बराबर चाहते रहे कि चीन हमारा दोस्त रहे, लेकिन चीन का रवैया यह है कि वह आज युद्धरत राष्ट्र है और पहले भी था। भले ही दिखलाने के लिये वह खुले रूप से युद्ध में भाग न ले रहा हो लेकिन उसकी नीति साफ है। मेरा जो यह संशोधन है श्रीमन्, वह बहुत शक्ति रखता है। और जब तक यह संशोधन पास नहीं होता है, तब तक मेरी समझ में इस प्रस्ताव में कोई शक्ति रह नहीं जायेगी। हमेशा लड़ाई में दो फ्रन्ट होते हैं, एक फ्रन्ट पर तो लड़ाई होती है और दूसरे में नीचे-नीचे एक भूमिका तैयार होती है कि लड़ाई का काम ठीक से चले यानी जनता का स्तर ऐसे समय में गिरने न पाये।

आज हमारे यहां कुछ पंचमार्गी लोग ऐसे हैं कि जो जनता में अविश्वास और अश्रद्धा की भावना फैलाना चाहते हैं ताकि देश में एक नर्वसनेस पैदा हो और विरोधियों का उससे लाभ हो। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। हम सब भगवान कृष्ण को मानते हैं और उनके नेतृत्व में ही महाभारत का महान् युद्ध चला था। इस समय मैं महाभारत का एक किस्सा बता दूं तो अनुचित न होगा। अर्जुन के मामा शल्य, करण के सारथी थे। अर्जुन श्रीकृष्ण से कहा कि आप चाहें तो उन्हें अपने पक्ष में ला दें। उन्होंने कहा कि उसी तरफ उन्हें रहने दो लेकिन बस तुम उनसे इतना कह दो कि जब लड़ाई हो तो वह उस समय तुम्हारे पक्ष की बात कहें और उधर के लोगों को निरुत्साहित करते रहें। जब लड़ाई होती तो शल्य

[श्री मुक्तिनाथ राय]
कहता कि तुम लड़ तो रहे हो लेकिन जब अर्जुन के बाण चलेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से वह था तो विरोधी पक्ष में लेकिन वह कौरवों के पक्ष को सदा नरवस या हतोत्साहित करता रहता था। इसी तरह से आज हमारे देश में ऐसे पंचमांगी हैं जो इस देश में पैदा हुए हैं। यहां खाते हैं, यहीं पलते हैं लेकिन वह देश में इस तरह की भावना और नरवसनेस फैलाते हैं कि घबड़ाओ नहीं मुक्ति सेना आ रही है तुम्हारा उद्धार करेगी। जहां ऐसे लोग हों वहां कितनी ही बड़ी फौज हो, राष्ट्रनायक पंडित जवाहर लाल जैसे ही क्यों न हों अगर ऐसे सांपों का मुंह न तोड़ा गया तो यह भावना बहुत खतरनाक है, जिसको फैलाने की वह कोशिश करते हैं। उसका निराकरण करने की नितान्त आवश्यकता है। उनके रहते हुए सफल नहीं हो सकते।

गत द्वितीय महायुद्ध में हमने देखा कि जहां देखो वहां दीवारों पर और हर जगह 'V' (वी), विक्टरी लिखा हुआ था। चर्चिल ने इस तरह से तमाम लोगों में विक्टरी या विजय का वातावरण पैदा किया, हर घर, हर दीवार को इस तरह से उसने विक्टरीमय कर दिया, इस तरह से भावना द्वारा उसने 'वी' को जीत का प्रतीक बनाया। इस तरह की चीज से लड़ाई में मदद होती है। ऐसे समय में देश में एक अनुकूल और विजयी वातावरण की आवश्यकता है न कि एक नर्वसनेस देश में फैले। यह चीज कितनी खतरनाक हो सकती है इसको हमें समझना चाहिये। अतः मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे इस आवश्यक संशोधन पर विचार करे और इसे स्वीकार करे। यदि इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तो चाहे कितनी ही फौज हो और कितने ही साधन हों यह अन्दर रहने वाले दुश्मन हमारे लिये एक खतरा हैं और वे एक नरवसनेस का वातावरण पैदा करते रहेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना और अनुरोध है सदन से कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए मैं एक गंभीर उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा हूं। मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि इस प्रस्ताव का अर्थ किसी प्रकार भी युद्ध का वातावरण पैदा करना नहीं है। इस प्रस्ताव का यह अर्थ भी नहीं है कि देश के प्रधान मंत्री या सुरक्षा मंत्री बदल जायं। इस प्रस्ताव का यह भी अर्थ नहीं है कि विश्व युद्ध का वातावरण पैदा किया जाय। बल्कि इस प्रस्ताव का यह स्पष्ट अर्थ है कि इस देश में कश्मीर समस्या के बाद हमारे प्रदेश और देश की उत्तरी सीमा पर जो चीन के आक्रान्ता होने से परिस्थिति पैदा हो गई है, उसके फलस्वरूप राष्ट्र में एक एकतामूलकराष्ट्रीय भावना का संचार किया जाय। यही इस प्रस्ताव का उद्देश्य है।

चीन की संस्कृति की बात कही गयी। भारत और चीन की पुरानी संस्कृतियों का सभी माननीय सदस्यों को आभास है। इतिहास के वह परिच्छेद भुलाये नहीं जा सकते जब कि फाहियान और ह्वेनसांग सम्भवतः हमारे उत्तर प्रदेश के ही ६ दर्रों से होकर भारत में आये थे और चीन और भारत के संबंधों में पुष्टि की थी। इसी प्रदेश में सारनाथ से वह तेजोमयी शक्ति उत्पन्न हुई जिसने बुद्धम् शरणम् गच्छामि का मार्ग विश्व को दिखलाया और चीन तथा तिब्बत तथागत के धर्म का महान् केन्द्र बन गये। इसी उत्तर प्रदेश में वह विभूति विकसित हुई और कुशीनगर में उसका देहावसान हुआ। तो जहां तक सांस्कृतिक संबंध हैं वह तो अटूट हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि जहां एक ओर भाई-भाई के नारे की बात होती है तो वहां दूसरी तरफ से भाईचारे को किस तरह से निभाया जाता है। हमने, भारत ने एक तरफ सन् १९५४ में पंचशील का समझौता किया। तिब्बत से अपनी फौजें वापस कीं। दलाई लामा को हिन्दुस्तान से तिब्बत भेजा कि जाओ चीन के साथ समझौते के साथ रहो। सन् ५४ के इस समझौते द्वारा ही एक समझौता प्रस्तावित किया गया जिसके अनुसार तिब्बत को 'आटोनामी' (स्वतंत्रता) दी गई। एक ओर सन् ५४ में हम भारत की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव कर रहे थे और दूसरी ओर उसी सन्, ५४ में चीनी भाई हमारे लद्दाख में अक्साई चीन में सैकड़ों वर्ग मील पर कब्जा

कर रहे थे। वहां पर भी १०० मील लम्बी मोटर रोड बनायी गयी। तो भाई-चारे का पैमाना क्या हुआ? भारत सरकार ने सन् १९५४ से ५९ तक भाई-चारे के कारण यह सूचना देश को नहीं .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न बहस में नहीं आ सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कल और लोगों ने तो जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष—अगर किया तो वह गलत किया। भारत सरकार ने यह किया वह किया, सही किया या गलत किया, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार तो जवाब दे के लिये यहां है नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न है कि जब यह चन्द्रजीत यादव जी का संशोधन लिया गया है जिसमें प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो नीति है उस नीति के समर्थन के लिये उन्होंने कहा है तो इस पर भी हमें कहने का हक होना चाहिये अन्यथा वह संशोधन ही निकाल दिया गया होता।

श्री अध्यक्ष—वह दूसरी चीज है। अगर जवाहरलाल जी की नीति आप यह मानते हैं कि चीन को हिन्दुस्तान सौंप देना है तो यह चीज आप कह सकते हैं। उनका तो मतलब यह नहीं है कि जो फैक्ट्स पहले गुजर चुके हैं उनका भी वे समर्थन करते हैं। उनके संशोधन में कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह जो श्री चन्द्रजीत यादव का चौथा संशोधन है उसमें लिखा है कि "यह सदन भारत सरकार की शान्तिमय समझौते द्वारा सीमा सम्बन्धी विवादों को हल करने की नीति का पूर्णतया समर्थन करते हुये यह विश्वास दिलाता है कि अपने प्रदेश एवं राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हेतु जो भी कदम उठाये जायेंगे उसमें हमारा पूर्ण सहयोग एवं समर्थन होगा।" मान लीजिये हम इस संशोधन में यह संशोधन करें कि भारत सरकार की अब तक की जो नीति है वह ठीक नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—उस तरह की चीज इसमें नहीं है। उसमें है कि आगे के लिये जो भारत सरकार ने नीति रखी है, शान्ति और समझौते की उसका वह समर्थन करते हैं। यह चीज उनके संशोधन में थी इसलिए उसे रखने की अनुमति दी गई थी।

श्री राजनारायण—तो इस संशोधन को निकलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपका कहना गलत है। माननीय नारायणदत्त जी, आप जारी रखिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं स्वयं अपने को संतुलित करने की पूरी चेष्टा करता हूं। आप मेरा पूरा वाक्य या मेरी पूरी बात सुनने की कृपा करें और फिर निर्णय दें तो ठीक होगा। मैं तो केवल यही कह रहा था कि कल भाई-चारे का प्रश्न यहां उठाया गया, आपकी अनुपस्थिति में। मेरा कहना यह है कि जहां भारत और देश की जनता का प्रश्न है हमने ४ साल तक भाई-चारे को निभाने की पूरी चेष्टा की। यू० एन० ओ० में चीन का सवाल बार-बार उठाया, और मैं यही कह रहा था कि एक तरफ पंचशील के समझौते पर दस्तखत हो रहे थे और दूसरी तरफ लद्दाख में चीनी फौजों द्वारा कब्जा हो रहा था। भारत सरकार ने ४ साल तक शान्तिपूर्ण तरीके से उस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया और किसी को मालूम भी नहीं होने दिया कि चीन ऐसी कार्यवाही कर रहा है। मैं भाई-चारे की सीमा बता रहा था और इसी सीमा के सम्बन्ध में आप देखें कि यहां कहा गया कि चीन ने भारत को कभी आक्रान्ता नहीं कहा।

अब मैं क्या कहूं, अगर हमारे समाचार-पत्र मिथ्या हैं, चीन के समाचार पत्र मिथ्या हैं जो यहां आते हैं, तब तो दूसरी बात है। लेकिन जिस समय इंटरनेशनल ला के अनुसार हमने दलाई

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लामा को 'ऐसाइलम' दिया तो चीन में हजारों मीटिंगों में यह कहा गया कि भारत प्रसारवादी नीति अपना रहा है और नेहरू जी को कहा गया कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चरणों पर चल रहे हैं। और चीन के प्रमुख एक अधिकारी ने यहां तक कहा कि 'हिन्दुस्तानी सुअरों को चीन की फुलवाड़ी में अपनी नाक घुसेड़ने का क्या अधिकार है।' तो इस समय यह कहना कि हमारे देश में युद्ध का वातावरण पैदा किया जा रहा है, और हमारा दोष है, गलत है। युद्ध का अगर कोई वातावरण है तो वह केवल अपनी सुरक्षा से संबंधित है। हमारे यहां लांगूज पर किसने हमला किया? मैं कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता से पूछना चाहता हूं कि कोकाह में हमारे ९ सिपाही किसने मारे? किसने वर्त्तमान वातावरण पैदा किया? कौन आक्रान्ता था? बाराहोती दर्रे पर १९५६ में चीन की फौजों ने अनधिकार कब्जा करने की चेष्टा की और कब्जा कर भी लिया और भारत सरकार की तरफ से लगातार शान्तिपूर्ण तरीके से पत्र-व्यवहार होता रहा। जब कि १९५४ के समझौते के अनुसार चीन के उप-परराष्ट्रमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ६ दर्रों को (बाराहोती, सांगचामल्ला, लपथाल, निलंग, जाधांग और पुलिंगसामदों के पास) उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जैसा खेत पत्र से मालूम होता है हमारे प्रदेश के पुलिंग और निलंग नामक स्थानों पर, जहां जान्हवी के स्रोत हैं तथा १६६७ के ताम्र-पत्र के अनुसार भी यह हमारे प्रदेश के ही अंग रहे हैं, इन पर हमारा अधिकार रहा है उनके मुख-द्वार पर चीनी फौजों ने आधिपत्य कर लिया। सांगचामल्ला और लपथाल के दर्रे के मुख-द्वार भी चीन के हाथ में हैं।

मैं कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता से कहूंगा कि वे राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें पढ़ें। उनमें निलंग और पुलिंग स्थान उत्तर प्रदेश तथा भारत में माने गये हैं। तब से यह सब स्थान भारतीय माने गये हैं जब कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का यहां पता नहीं था और कुमायूं के चन्द तथा कत्यूरी राजाओं का कूरमांचल गढ़ था और यह सभी दर्रे भारत के अंग रहे हैं। तो फिर, चीन के कार्य को अनुचित न मानना और यह भी कहना कि चीन की भर्त्सना न की जाय, यह अनुचित है। मैं पूछना चाहता हूं कि भर्त्सना क्यों न की जाय? इस प्रस्ताव के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? क्यों हम आज रक्षा चाहते हैं, देश में क्यों राष्ट्रीय एकता चाहते हैं? इसलिये चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के इन ६ दर्रों पर चीन का अधिकार बना रहा, लिपुलेक और बलचाधुरा के दर्रों पर चीन का अधिकार हो गया तो नतीजा यह होगा कि चीन की फौजों को केवल वहां से नीचे उतरने का ही समय चाहिये और हमारी आजादी किसी समय भी संकट में पड़ सकती है। यदि अपने देश में हमने एकता स्थापित नहीं रखी, सुरक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं किया तो व्यूह रचना (Strategic Importance) के दृष्टिकोण से साधारणतया ७ दिन के अन्दर चीनी फौजें दिल्ली और लखनऊ पहुंच सकती हैं, केवल उन्हें ऊपर से नीचे उतरना है। इसलिये केवल टेहरी गढ़वाल और कुमायूं का यह प्रश्न नहीं है अपितु यह भारत की सुरक्षा का बुनियादी प्रश्न है जो इस प्रदेश के ६ दर्रों में निहित है। भारतीय फौजें इन दर्रों पर कब्जा करने के बाद अगर चाहें भी तो साधारणतया महीनों तक पेकिंग नहीं पहुंच सकतीं। बीच में तिब्बत का पठार है। भयानक रास्ते हैं। चीन के खिलाफ हमारे दिमाग में बात उठे भी तो महीनों तक हमारी फौजें पेकिंग नहीं पहुंच सकतीं, लेकिन चीन की फौजें ७ दिन में दिल्ली पहुंच सकती हैं। इसमें न आइजनहोवर, अमेरिकन ब्लाक का सवाल है, न कोई षड्यंत्र है। केवल राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के सन्तुलन का सवाल है। अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस तरह के सन्तुलन की बात कहती है तो कुछ लोगों को अमेरिका का भूत नजर आता है, पर इसमें विशुद्ध राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के समन्वय का प्रश्न है, अपनी सुरक्षा का प्रश्न है।

आज प्रश्न है उन लाखों व्यापारियों का भी जो आज तिब्बत से व्यापार नहीं कर सकते, जिनको सन् १९५४ के समझौते के विरुद्ध वहां जाने की किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। उन व्यापारियों का क्या भविष्य होने वाला है, जो भोट प्रदेश में रहते हैं। कुमायूं-गढ़वाल के गरीबों और भूमिहीनों का क्या होगा, जिन्हें अभी तक तराई-भावर में जमीन नहीं मिल पायी है? अब तक यह नहीं समझा जाता था कि हमारे चीनी भाई हम पर आक्रमण करेंगे। वहां पर

पुलिस केवल कस्टम्स के लिये रखी जाती थी। लेकिन सहसा इस प्रकार सन् १९५४ के समझौते को भंग करके जो चीनी भाइयों ने विश्वबन्धुत्व के सिद्धान्त पर कुठाराघात किया है, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिल सकती। एक तरफ विश्वबन्धुत्व और दूसरी ओर उसकी अवहेलना।

कैलास-मानसरोवर की यात्रा के लिये हमारे इस प्रदेश के शत-शत व्यक्ति प्रत्येक वर्ष जाया करते थे। मैं पूर्ण धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति होने का दावा नहीं कर सकता, पर देश में ऐसे लाखों व्यक्ति आज भी विद्यमान हैं जो धार्मिक वृत्ति के हैं जिनके मस्तिष्क में कैलास की पावस हिमाच्छादित शुभ्र धवल शिखर की प्रतिमा विराजमान रहती है, जो मानसरोवर के पवित्र सरोवर में फूल अर्पित करना चाहते हैं। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की हम अवहेलना नहीं कर सकते। सांस्कृतिक सम्बन्ध होने के नाते भी आज वे यात्री वहां नहीं जा सकते। सन् १९५४ के समझौते में कई बातें यात्रा की सुविधा के संबंध में लिखी हैं, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश या इस देश के रहने वाले यात्री वहां नहीं जा सकते। यह कोई कम शिकायत की बात है? इसका क्या हल निकलने वाला है? जिनके धार्मिक अधिकार हैं उनके अधिकार क्या सन् १९५४ के समझौते के अनुसार सुरक्षित हैं? उनकी कौन रक्षा करेगा? किस प्रकार रक्षा हो सकेगी? क्या इसमें हमारा दायित्व नहीं है? सब राष्ट्रीय पार्टियों का क्या इसमें दायित्व नहीं है?

मैं किसी पार्टी की बात नहीं कहना चाहता था। लेकिन मेरे दोस्त यादव जी ने स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी की बात पहले कही। मैं यह जानता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे हजारों नवयुवक मौजूद हैं जो समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर जो सन् ४२ के तत्व मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय तत्व हैं, उनका क्या हाल है? मेरी सूचना के अनुसार इसी सदन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने जब एक वक्तव्य में कहा कि चीन में संभवतः कुछ बेरियावादी तत्व काम कर रहे हैं तो उनसे परिणामतः जवाब तलब किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—अनुशासन भंग करने के लिये जवाब तलब किया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—स्वागत है इस अनुशासन भंग करने के लिये जवाबतलबी करने का, लेकिन प्रश्न को मूल से अलग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता का संतुलन करते हुए, पंचशील के अन्दर सुरक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए और समाजवाद की पृष्ठभूमि में काम करते हुये हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य जो ७ करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब तक आसमान में सूरज है और जब तक हमारे हिमालय के अञ्चल से निकलने वाली हमारी यमुना और गंगा में मौजें हिलोरें ले रही हैं, तब तक हिमालय के दर्रे हमारे रहेंगे और पंडित जवाहरलाल जी के शब्दों में मैं फिर दोहराता हूं कि हिमालय हमारा मुकुट है। परम्परा के, भूगोल के और राजनीति के आधार पर हिमालय के दर्रे और चीन द्वारा अधिकृत भू-भाग हमारे हैं और हमारे रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सह-प्रस्तुत करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है इस पर कुछ कहने के पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस प्रस्ताव पर जितने भी भाषण अब तक हुए उनमें एक ही बात हम अपने देश के अन्दर व विदेशों को स्पष्ट बतलाना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिये, अक्षुणता के लिय तथा अखंडता क लिय हम १०५ हैं और बाकी इसकी रक्षा करने के लिये जो भी हमको करना पड़ेगा, वह करेंगे और जो भी सरकार कदम उठायेगी उसके लिये हम सहर्ष कंधे से कंधा मिला कर तैयार रहेंगे और जो भी बलिदान देना पड़ेगा, जो भी मूल्य चकाना पड़ेगा, उसको चुकाने के लिये भी हम तैयार हैं।

आज जो परिस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर हमें दृष्टिपात करना चाहिये और सब तरह से विचार करने के पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे देश की सीमा की स्ट्रेटिजिक इंपार्टेन्स क्या है? किसी भी देश की कुछ न कुछ स्ट्रेटिजिक इंपार्टेन्स हुआ करती है और यह

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कहा जा सकता है कि ये-ये हमारी सीमायें हैं। कहा जाता है कि जो चीन हमारी सीमाओं के अन्दर घुस आया है उससे हम सुलह की बात करें। क्या बात करें? किसस बात करें? चीन से सुलह की बात करने के मानी वैसे ही होंगे जैसे घर के दरवाजे पर चोर घुस आया हो और पड़ोसी कहे कि सुलह की बात करो। अगर उससे सुलह की बात करोगे तो वह एक ही बात कहेगा कि दरवाजा दे दो और उसके बाद जैसे वह चाहेगा वैसे हमें नचायेगा।

आज लद्दाख से लेकर नेफा तक जितने दर्रे हैं वे वाटर शेड्स कहलाते हैं और अगर वे चीन को दे दिये गये सुलह के नाम पर तो यह कार्यवाही उसी प्रकार की होगी कि एग्रेसर को एग्रीव्ड के बराबर लाना होगा। यह नहीं कि सुलह की बात न हो। हम भी चाहते हैं कि सुलह की बात हो, लेकिन सुलह के साथ हम स्वाभिमान भी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, 'पीस विद आनर' चाहते हैं न कि 'पीस विद डिसआनर'। किसी भी राष्ट्र को जिन्दा रहना है तो उसे स्वाभिमान के साथ जीवित रहना पड़ेगा। आज हम किसी के ऊपर निर्भर रह कर जीवित नहीं रह सकते। आज जो हमारी सीमाओं पर आक्रमण हुआ है उसके बारे में श्रीमन्, स्पष्ट है कि जैसा हमारे माननीय मित्र नारायण दत्त जी ने कहा है और वही बात आज अखबार में एक आर्टिकिल में आई है, एक लेख काश्मीर हाई कोर्ट के जज का है उसका एक अंश मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। जे० एल० किलम, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं उनकी सीरीज आफ आर्टिकिल्स में से कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूं। सन् १६६५ की जो संधि हुई थी उसकी डेफिनीशन के बारे में वह है :--

"Mr. J. L. Kilam, a retired Judge of the Jammu and Kashmir High Court, has in a series of articles maintained that the Indo-Tibetan border is not only well known and understood on the basis of usage and convention but is clearly defined in the treaty concluded in 1665 following the war between Laddakh and Tibet."

यह १६६५ की वह सुलह थी जब चीन के अन्दर कोई सीमा न थी, जब तिब्बत स्वयं स्वतंत्र था। उस समय लद्दाख व नेफा की सीमायें निर्धारित हो गयीं। फिर आज कौन सी बात है जो सीमा की बात फिर चीन ने उठाई? सीमा का विवाद खड़ा इसीलिये किया जाता है ताकि सीमा का विवाद खड़ा करा कर देश के अन्दर विप्लव पैदा किया जाय, देश के अन्दर सेल्फ रिलायन्स और कोआपरेशन की जो भावना है उसे मिनिमाइज किया जाय और इसी टेक्निक की आड़ लेकर चीन ने लद्दाख व नेफा पर आक्रमण किया जो हमारी सीमाओं के अन्दर हैं। एक तरफ कहा जाता है 'हिन्दी चीनी भाई-भाई' और दूसरी तरफ चीनियों ने हमारी चेक पोस्ट्स के ऊपर गश्त लगाते हुए सिपाहियों को गोलियों से भूना और उन्होंने करम सिंह को बरफ पर तीन दिन लिटाया। आज हम उसे ही अपना भाई बनाने की अपेक्षा करते हैं जो हमारे घर के अन्दर घुस कर विघटन करना चाहता है, उसी को हमसे भाई बनाने के लिये कहा जाता है। ऐसे भाई से तो भगवान रक्षा करे। हम विश्व को भाई बना सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान रख कर और अपना स्वाभिमान खोकर हम किसी को भाई नहीं बना सकते हैं। यह 'हिन्दी चीनी भाई-भाई' का जो नारा दिया गया है वह ऐसा ही है जैसे ओपियम दी गई हो, लोगों के हृदय में राष्ट्रीय भावना को सुलाने के लिये यह नारा दिया गया है और वही परिणाम वास्तव में हुआ है। आज इस नारे को लेकर हमारी आंखें वास्तविकता की ओर से बंद की गई हैं। आज चीन को आक्रामक माना जाय इस भावना को सुलाने के लिये इस नारे को दिया गया है। इसलिये मैं इसको कभी भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हमें असल में वास्तविकता की ओर जाना चाहिये। हमारे देश का हित पहले रहेगा। राष्ट्र हित सब से ऊपर रहना चाहिये।

श्रीमन्, दूसरी बात इसी के साथ और है और वह यह है कि आज जब यह प्रश्न हमारे सामने मुंह बाये खड़ा है तो हमें अपनी रक्षा के लिये और देश की रक्षा के लिये अपना मजबूत कदम उठाना है। इसी के साथ-साथ आवश्यक काम यह है कि राष्ट्रहित का प्रखर पाठ आज जन-जन

के हृदय में प्रसारित किया जाय। श्रीमन्, अस्त्र-शस्त्र से लड़ाई होती है, लेकिन इसी के साथ-साथ मनुष्य का जो हृदय है उसकी जो भावना है, वह जिस मात्रा में जाग्रत होगी, उसी मात्रा में वह अपनी तथा अपने देश की सफलता के साथ रक्षा कर सकता है। आज इस प्रश्न की ओर हमारी सरकार की सबसे पहले दृष्टि जानी चाहिये। आज देश के अन्दर जन-जन में "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" की भावना को जाग्रत करना चाहिये। आज हमारे देशवासियों में यह विश्वास हो कि यह हमारी मातृभूमि है और यह विश्व से ऊंची है और स्वर्ग से भी ऊंची है। यह भावना देश के प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर ओतप्रोत करने की आवश्यकता है। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि "कल्चर" शब्द को लेकर बड़ा अनर्थ किया जाता है। आज दुनिया भर की कल्चरल कांफ्रेन्सेज नाच गाने का स्थान हो गई हैं और वे मनुष्य में उच्च भावना जाग्रत करने का साधन नहीं हैं बल्कि मनुष्य की विषयी भावनाओं को जाग्रत करने का साधन हैं।

श्रीमन्, आज देश की सीमा के ऊपर हमारे गरीब लोग रहते हैं और उनको बहुत-सी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिये हमें सतत प्रयास करने चाहियें। मैं तो अपनी सरकार से यह कहूंगा कि आज इस बात की परम आवश्यकता है कि अपने प्रदेश में जो छोटे-छोटे कार्य चल रहे हैं, जैसे समाज कल्याण इत्यादि, उनको बंद कर दिया जाय क्योंकि आज तो हमारा समाज कल्याण घर के रहने में ही है, विघटन में समाज कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिये इन कार्यों का पैसा लेकर या अन्य कार्यों से पैसा लेकर, जैसे सरकार मुनासिब समझे, बजट से पैसा ले कर यूनाइटेड फोर्स के साथ इस क्षेत्र के अन्दर कम्युनिकेशन्स का डेवलपमेंट, मिलिटरी का डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करे। इसी के साथ-साथ आन्तरिक सुरक्षा की भी परम आवश्यकता है।

आज इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि हमारे देश में ऐसी विचारधारा बहुत से लोगों में है जो देश का साहस तोड़ने के लिये तैयार हैं। कल हमारे मित्र माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहा कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां वार साइकोसिस बना रही हैं। इसके लिये तो मैं एक ही तराजू जानता हूं कि जब १९४२ में कांग्रेस आन्दोलन कर रही थी तो उस समय किस ने अपना कदम देश के खिलाफ उठाया था और कितने आदमी कांग्रेस से उस समय निकाले गये थे? क्या यहीआपकी प्रगति है? क्या देश के ऊपर घात करना ही प्रगतिशीलता है? संधि की बात करते हुए, शान्ति की बात करते हुये जिस समय सरदार पटेल देश के कार्य में लगे हुए थे तो किसने तेलंगाना का विद्रोह किया था? किसने रजाकारों के साथ गठबंधन किया था और किसने दक्षिण में लोगों के अन्दर भावना जगाकर विघटन किया था और किसने श्रीमन्, पाकिस्तान का समर्थन करके कम्युनलिज्म को जगाया था? आज श्रीमन्, कम्युनल फोर्सेज का समर्थन करने वाला सिवाय कम्युनिस्ट के और कौन है? हम समझते हैं कि "An ounce of action is better than a ton of theory" आपके यह सारे कृत्य एक ओर हैं और दूसरी ओर आपकी घोषणा है कि एक-एक इंच भूमि की आप रक्षा करेंगे। हम कैसे इस पर विश्वास करें? हम विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन कदम उठाओ, देश के प्रति कृत्य करो। इसके लिए खाली प्रस्ताव और घोषणा से काम बनने वाला नहीं है। कल हमारे मित्र माननीय गोविन्दसिंह जी ने बताया कि कोई लोक कलाकार संघ है जिसने अल्मोड़ा में चीन की विजय के हेतु नाटक खेला। लज्जा की बात है। आज जो जयचन्द वृत्ति देश में मौजूद है उसको रोकने की जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि प्रतिबन्ध लगाया जाय, क्योंकि किसी भी प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक है कि वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए; लेकिन यह भी आवश्यकता है कि डेमोक्रेसी में वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर लाइसेंस टु डेस्ट्राय डेमोक्रेसी न हो। वैचारिक स्वतंत्रता की ओट में राष्ट्रविरोधी कृत्यों को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है।

'मुक्ति सेना आ रही है' यह नारा कौन लगा रहा है? इतना ही नहीं, मुझे मेरे मित्रों ने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े-बड़े कार्यकर्त्ता सीमा पर जाकर मजदूरों के अन्दर मेट बन कर कार्य कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि सम्बन्ध स्थापित हो, इल्लिसिट आर्म्स की

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

स्मगलिंग हो और वह देश में विघटन करने में सहायक हों। यह सारी चीजें रोकने की जरूरत है। जरूरत है कि सारे सीमा क्षेत्र को सेक्योरिटी एरिया डिक्लेयर करें। उसके अन्दर उन्हीं लोगों को जाने का अधिकार हो जो वास्तव में राष्ट्रवादी हों। उनको जाने का अधिकार न हो जो खाली पास का उपयोग करके राष्ट्र को सेबोटेज करने की कोशिश करें। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के शब्दों में, हजारों वर्षों से देश की जैसी परीक्षा नहीं हुई थी आज हो रही है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कठोर से कठोर कदम उठाएं। दूसरे, उस क्षेत्र में जो आफिसर नियुक्त किये जायं, वे अनुभवी नियुक्त किये जायं।

मैं किसी की प्रशंसा और अप्रशंसा नहीं करता, लेकिन वास्तव में जब अंग्रेज कलेक्टर थे तो घोड़े पर चढ़ कर गांव-गांव में लोगों से सम्बन्ध स्थापित करते थे। लेकिन मुझे लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे कलेक्टर बिना मोटर के गांव-गांव में नहीं जा सकते। कैसे सम्बन्ध स्थापित होगा? वह तो हमारी सीमा पर प्रचार कर रहे हैं, तरह-तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, और हमारे अधिकारी बिना मोटर के वहां जा नहीं सकते? यह गलत चीज है। वहां पर यंग आफिसर्स की जरूरत नहीं है। वहां अनुभवी आफिसर्स की जरूरत है जो वास्तव में परिस्थिति को समझ कर उसका निराकरण कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यह सारा सीमा-क्षेत्र कमिश्नरी के रूप में बना दिया जाय जिसमें सिविल अथारिटीज का पूरा सेनक्रोनाइजेशन आर्मी के साथ हो, जिससे सीमा की पूर्ण रूप से रक्षा की जा सके। इसलिए मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव है, किसी प्रकार की पार्टी पालिटिक्स का प्रस्ताव नहीं है और कम्युनिस्ट भाइयों का यह टेस्ट है कि आज वह राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ देश की सुरक्षा के साथ हैं या केवल शब्दों के जाल से, चीन की दृष्टि से, उसका हित करने के लिए, शब्दों से हमारे देश के मोरेल को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का उनका acid टस्ट है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को यह सदन स्वीकृत करे जिससे कि चारों ओर यह साबित हो सके कि देश की रक्षा के लिए सारा देश और सारा समाज एक है, किसी प्रकार का राजनैतिक विघटन नहीं, राजनैतिक विरोध नहीं क्योंकि देश के ऊपर सबसे बड़ी आपत्ति आ रही है। इस आपत्ति के पीछे दूसरा उसका अंश और है। हमारे जो सरहदी देश हैं, उनकी जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उनसे वह कह सकते हैं कि देखो हिन्दुस्तान तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम हमारे साथ आओ। आज सारे साउथ ईस्ट एशिया के अन्दर यह भाव फैलाया जा सकता है कि जिस हिन्दुस्तान के लिए कहा जाता था कि वह डेमोक्रेसी के रास्ते से आगे बढ़ रहा है वह भी हमारी टोटैलिटेरियन ताकत के आगे घुटने टेक कर रह गया है। इस तरह से एक डिमारेलाइजेशन सारे एशिया में फैल जायगा। इसलिए आवश्यक है कि जितने राष्ट्रवादी तत्व हैं वह सब एकत्र होकर एक भावना से सारे विश्व के आगे यह प्रकट कर दें कि हम एक राष्ट्र हैं और इसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, यू० पी० की विधान सभा ही नहीं और यू० पी० के नागरिक ही नहीं बल्कि सारे संसार के सभ्य लोग चीन के इस ऐग्रेशन, आक्रमण को बुरा बता रहे हैं। यहां तक कि आज पत्र में मैंने देखा कि रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव ने भी कहा कि चीन का यह कार्य स्टुपिड है। यह शब्द उन्होंने उपयोग किया। जहां तक इस का संबंध है कि उन्होंने आक्रमण कर बड़ी मूर्खता का काम किया यह तो सर्वमान्य है, इस पर दो रायें नहीं हो सकतीं। और भारत उसका मुकाबला करे, इसमें भी मेरे खयाल से हमारे देश के अन्दर दो रायें नहीं हैं। यहां तक कि कल मुझे यादव जी की बात सुनकर प्रसन्नता हुई। मगर मुझे यह मालूम था कि हमारे कम्युनिस्ट भाई हिंसा पर बड़ा विश्वास करते हैं और कल

उन्होंने अहिंसा की बात कही तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने कांग्रेस की अहिंसात्मक नीति को अपनाया और सम्भवतः अब वह विदेशी किसी भी संस्था से अपना सम्बन्ध विच्छेद करके कांग्रेस में सम्मिलित हो जायेंगे, ऐसा मुझे अनुमान लगा । बड़ी खुशी की बात है, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है तो अच्छा ही है । मुझे बड़ी खुशी हुई यह जानकर । अब उनके पिछले कारनामों को, जैसा यादव जी ने दोहराया, मैं नहीं दोहराना चाहता । उसकी वजह यह है कि गलती होती है मनुष्य से और मनुष्य वही है जो उन भूलों को सुधार करके ठिकाने से आ जाता है । मगर हमें इस बात को देखना होगा कि इनका यह पश्चाताप सही और सच्चे दिल से है या नहीं ?

कुछ मुक्ति सेना का जिक्र आया था । चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया तो उसको कुछ लोगों ने कहा कि मुक्ति सेना आ रही है । ऐसी चर्चा चली । मगर माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने इधर कहा कि इन्हें युद्ध अपराधी माना जाय । मुक्तिनाथ जी ठीक बात कह रहे थे, उन्हें युद्ध अपराधी नहीं तो देशद्रोही तो अवश्य कहा जा सकता है और मैं समझता हूं उसके लिए हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है और इसके लिए सावधानी बरती जा रही है । मगर जो भाषण मैंने इस सदन में सुने और खास तौर पर उधर के उपनेता प्रजा समाजवादी दल के श्री नारायणदत्त ने कहा कि सात दिन के अन्दर कम्युनिस्ट उन दर्रों को लांघकर लखनऊ और दिल्ली आ सकते हैं . . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर डिफेंस न हुआ तो ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं कहता हूं कि डिफेन्स कुछ भी न हो लेकिन जब तक हम जीवित हैं, कुमायूं और गढ़वाल के आदमियों की तरफ से कहता हूं कि गैर शस्त्र के सात महीने तक उनको रोक सकते हैं । यह कहना कमजोरी की बात है कि सात दिन के अन्दर वह दिल्ली और लखनऊ आ सकते हैं । अगर उनके पास वैज्ञानिक एटम बम है, या कोई हाइड्रोजन बम है या ऐसा कोई हथियार है जिससे सारा भारतवर्ष नष्ट हो जाय और भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सारा संसार नष्ट हो जाय तो फिर हमारे और आपके यह वश की बात नहीं है । मैं कहता हूं कि चीन के पास अगर वैज्ञानिक शस्त्र नहीं हैं तो वह रूस के आगे भीख मांगेगा, लेकिन जो देश गणराज्य के मानने वाले हैं क्या उन सभी गणतन्त्र देशों के शस्त्रागारों में जंग लग गया है ? मैं यह कहता हूं कि इसमें कोई भारतवर्ष का सवाल नहीं है । यह तो सभी गणतन्त्र के सिद्धान्त को मानने वाले देशों का सवाल है । हम अमेरिका से कोई भीख नहीं मांगते हैं । हम किसी भी गणराज्य देश से भीख नहीं मांगते हैं, किन्तु अगर संसार में गणराज्य के सिद्धान्त को रहना है तो अमेरिका हमको हाथ जोड़कर शस्त्र देगा अगर चीन सरकार हमारे देश पर आक्रमण करती है । फिर भी मैं यह समझता हूं कि इन चीजों का प्रयोग नहीं होगा । चीन के लिये सारा उत्तर प्रदेश दूर रहा और सारा भारतवर्ष दूर रहा हम केवल चार पहाड़ी जिले काफी हैं ।

जहां तक मैकमोहन लाइन का सवाल है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, इस लाइन को सब मानते हैं मगर जैसा कि अभी बाराहोती के विषय में सवाल उठाया गया कि बाराहोती पर उनका कब्जा हो गया है, तो बाराहोती पर चीन का कब्जा नहीं है । उस पर हमारा कब्जा है । बाराहोती पर कभी भी तिब्बत या चीन का कब्जा नहीं रहा है । वह हमेशा हमारे कब्जे में रहा है और आज भी हमारा कब्जा उसके ऊपर है । मेरे मित्र को पता नहीं है, मैं यह बताना चाहता हूं कि एक बार तिब्बतियों ने इस शताब्दि के प्रारंभ म और पिछली शताब्दि के अन्त में करीब सन् १९०० में एक बार यह कोशिश की थी कि बाराहोती पर कब्जा कर लिया जाय । लैंस-डाउन से फौज गई और हमारी फौज दिसम्बर के महीने में गई जब कि वहां पर बर्फ पड़ी हुई थी और बाराहोती पर अपना कब्जा किया । मैं यह सन् १९०० की बात कह रहा हूं । उस पर हमारा कब्जा बराबर रहा है । इस साल हमारे गढ़वाल के डिप्टी

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

कमिश्नर वहां गये थे । दुबे जी ने कहा कि हमारे कलेक्टर बड़े मुलायम होते हैं और वे मोटर के बिना सफर नहीं करते हैं । वहां पर अफवाह यह फैल गई कि वह गिरफ्तार हो गये । बाराहोती में हमारी पी० ए० सी० का झंडा लगा हुआ है । अभी थोड़े दिन पहले वह वापस लौटे हैं । बाराहोती पर कभी भी, किसी काल में भी, किसी समय में भी तिब्बत का या चीन का कब्जा या कोई हक नहीं रहा है । जब से चीन के साथ हमारी इस तरह की बातें चल रही हैं तब से बराबर हमारा कैम्प वहां पर रहता है । इसलिये मैंने निवेदन किया कि बाराहोती पर हमारा कब्जा है ।

जहां तक शास्त्रों का प्रमाण देने का प्रश्न है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मानस खंड और केदार खंड हमारे भारतवर्ष के अंग हैं और वह सदा से हमारी भारतभूमि क खंड रहे हैं । शास्त्रों की दुहाई देने से काम नहीं चलता, काम चलता है उस पर अपना कब्जा रखने से और कब्जा रखने के लिये हमारी सरकार सजग है, सचेत है। आप जिस तरह से समझ रहे हैं कि सरकार सोई हुई है या सोने की दशा में है, इस तरह की कोई बात नहीं है । आप इस तरह की शंका अपने दिमाग से निकाल दें । हमारी पी० ए० सी० की बटालियन जोशीमठ में है, नीलम में है और भटवाड़े में है । हां, यह बात जरूर है कि अभी उस तरह की सड़कें नहीं हैं जैसी आप चाहते हैं, किन्तु जब पगडंडी का भी ठीक प्रबन्ध नहीं था तब हमने नीति पास और बाराहोती के पास तिब्बतियों को हराया था ।

जहां तक सरहद का सवाल है, १८४५ में जोरावर सिंह ने इसके पच्छिम में दो दफा जीतकर कोट खरा तक अपना साम्राज्य कायम किया था । हमारे मित्र दुबे जी १९६५ के प्रमाण की बात कर रहे थे । वह तो बहुत पुरानी बात हो गई है । उसके बाद के भी प्रमाण हैं कि जब भारतवर्ष का कब्जा वहां पर रहा है मगर हमने कभी कोई जमीन उसके बाद नहीं ली; लेकिन पासेज के उधर का जो पठार है वह हिन्दुस्तान के कब्जे में रहा और रहेगा । इसमें कोई संदेह की बात नहीं है । जोरावर सिंह ने उधर अपना कब्जा किया और उस समय से अपना कब्जा उधर भी रखा है ।

जहां तक आने-जाने के साधनों का सवाल है, वर्तमान युग में इस बात की आवश्यकता है कि हम आने-जाने के रास्ते अच्छे रखें, ताकि हम अपनी सेनायें काफी तादाद में वहां भेज सकें और व्यापार आदि कर सकें । यह तमाम चीजें सदन में बताने की नहीं हैं कि कहां क्या काम हो रहा है, कहां कौन सड़क बन रही है । आप लोग अपनी मांग रख सकते हैं । उसमें कोई बुराई नहीं है और आपकी वह सब बातें सरकार के नोटिस में आती रहेंगी । अभी मुख्य मंत्री जी गढ़वाल गये थे और उस समय भी वहां पर इसी तरह की चर्चा हुई थी कि कुछ छतरीबाज उतर आये हैं । यह सब भ्रमात्मक बातें हैं वैसी ही जैसे कि यह अफवाह थी कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब पकड़ लिये गये थे । वह तीन महीने तक बाराहोती में रहे, वहां हमारा कब्जा रहा और फिर लौट कर आये । कोई बात नहीं, लेकिन एक हवा फैल गयी । यह ठीक है कि चीनी लोग अपने इलाके में सड़कें बना रहे हैं और इस बात को सभी जानते हैं । लेकिन अगर वह उसके लिये कभी विस्फोट करते हैं या उनके किसी काम के कारण अगर होराइजन पर कभी लौ दिखाई पड़ती है तो उन सब चीजों को तूल देने की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं है । यह कहना कि वहां की परिस्थिति बड़ी भयावह हो गयी है, मैं समझता हूं, अपने मोरेल को ऊंचा रखने के लिये अच्छा नहीं है । मुक्तिनाथ जी ने फिफ्थ कालमिस्ट के लिये एक बड़े सुन्दर शब्द का प्रयोग किया । शब्द था शल्य । तो इधर उधर की उड़ाई हुई बातों को ज्यादा तूल दिया जाना मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा नहीं है ।

एक बात मैं नहीं समझ पाया जो कल कही गयी थी । कुछ ने वहां के भोटियों में मंगोलियन ब्लड का जिक्र किया । मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि वहां के भोटिये, जो तिब्बत

से व्यापार करते हैं, वे हमारे प्रदेश के लोग हैं और उनमें मंगोलियन ब्लड वाली बात से मैं सहमत नहीं। वे हमारी तरफ के हैं और उनका इस प्रदेश और देश से उतना ही प्रेम है जितना कि हमारा। उनके पुनर्वासन का प्रश्न सरकार ने १९५२ में ही ले लिया था और टेहरी स्टेट के जितने जाट हैं उनको ८-८ मील भूमि हमने दे दी है और उनको खेती करने के लिये बांडलाइज करके गेहूं दिया गया था ताकि उसकी फसल जाड़े के पहले ही तैयार हो जाय। मैंने स्वयं उस काम को किया था। तो जहां तक उनका ताल्लुक है उनसे किसी तरह का खतरा नहीं है और हम लोगों से पहले उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि सरकार से हमारा अनुरोध है कि फौजी मदद हमको दी जाय और हम अपने देश के लिये अपना खून तक बहाने के लिये तैयार हैं। यह भ्रम नहीं होना चाहिये किसी के दिमाग में कि उनमें मंगोलियन ब्लड है। वे हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं और इस देश के रहने वाले हैं और जिस प्रकार हम अपने देश के लिये अपने को न्यौछावर कर सकते हैं उसी प्रकार वह भी कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि बाराहोती के बारे में मैंने यह नहीं कहा है कि बाराहोती पर चीनियों का पहले से ही कब्जा था। मैंने तो यह कहा कि भारत सरकार के श्वेतपत्र में यह लिखा है कि चीनियों ने बाराहोती पर एक बार कब्जा किया। फिर उनसे एक एग्रीमेन्ट हुआ। उसके अनुसार दोनों देशों ने अपनी फौजें बाराहोती से हटा लीं। इस एग्रीमेन्ट के विरुद्ध चीनियों ने अपने कर्मचारी सन् १९५८ के जाड़े में बाराहोती भेजे, यह मैंने कहा था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर यहां विवाद और विचार हम कर रहे हैं वह इतना गम्भीर और महत्वपूर्ण है कि हमारा विवाद भी उसके अनुरूप ही गम्भीरता के साथ होना चाहिये। यह अवसर किसी अपनी पार्टी की प्रशंसा करने का या किसी दल या पार्टी की निन्दा करने का नहीं है। यह अवसर ऐसा अवसर है कि जिस पर हम सभी को मिल कर यह सोचना चाहिये कि इस अवसर पर, इस स्थिति में, हमें क्या करना चाहिये। आज स्थिति मामूली नहीं है, साधारण नहीं है, बल्कि गम्भीर है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने स्वयं यह कहा है कि जिस स्थिति का आज हम सामना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति का सामना हमारे देश को दो हजार वर्ष के भीतर कभी भी नहीं करना पड़ा था। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने इस समस्या को एक डेंजरस ईश्यू कहा है। उन्होंने स्वयं इसको एक गम्भीर प्रश्न माना है। इसलिये हमें इस अवसर पर कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहिये जिससे कि आपस में विवाद में कटुता बढ़े, बजाय इसके कि हम सब एक होकर, एक मन से इस विषय पर विचार करें। मुझे दुख है कि विवाद का स्तर अभी तक यह नहीं रहा।

इस अवसर पर मैं एक बात बहुत साफ-साफ कह देना चाहता हूं और वह यह कि लक्ष्मण जी ने भी एक जगह कहा है—

"सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आप।
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर करहिं प्रलाप ॥"

हम प्रलाप नहीं करना चाहते। मैं तो चीनियों की भी निन्दा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो इस बात को ईश्वर की एक देन समझता हूं। चीनियों ने जो कार्य किया है, आज उसके कारण कम से कम हम सजग तो हैं। हममें देश-प्रेम तो है। ईश्वर जो करता है सो अच्छा ही करता है। कभी-कभी बुराई से भी भलाई निकल आती है। आज चीन ने हमारे अन्दर राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत कर दिया है। यह सब ईश्वर की देन है, ऐसा मैं मानता हूं। इसी दृष्टिकोण से आज हमें इसे देखना है।

मुझे दुख है कि माननीय चन्द्रजीत यादव ने इस प्रस्ताव में अपना संशोधन प्रस्तुत किया। मेरा यह निश्चित मत है कि चीनियों की हिमायत करके, इस प्रस्ताव में अपना संशोधन प्रस्तुत करके, उन्होंने चीनियों के साथ भी कोई भलाई नहीं की है, उनको भी इससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन उन्होंने ऐसा करके अपनी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है,

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जिसकी पूर्ति बहुत दिन तक नहीं हो सकती। मैं उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि वे स्वयं कम से कम अपने ठंडे दिल से इस पर सोचें और विचार करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो जरूर उन्हें यह अनुभव होगा कि उन्होंने इस प्रस्ताव में अपना संशोधन करके अच्छा नहीं किया है और यदि वे इस संशोधन को पेश न करते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने इसको पेश करके अपनी ही हानि की है।

कल उन्होंने यह कहा था कि कुछ पार्टियां हमारे विरुद्ध कुछ वातावरण पैदा करना चाहती हैं। मैं माननीय चन्द्रजीत यादव से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है वे अगर इसे छपवा कर जनता में बटवा दें और फिर देखें कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, जनता उसके बारे में क्या कहती है और उनकी पार्टी को कितनी हानि होती है, इससे अधिक इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया मैं किसी पार्टी की कोई निन्दा नहीं करना चाहता हूं और मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि सरकार की आलोचना करूं, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आज हमारे सामने सबसे पहले है। यह कार्य एक राष्ट्रीय महायज्ञ की तरह है। ऐसे समय में, ऐसे प्रश्न पर हमें अपनी सब कमजोरियों को भुला कर, दलगत भावनाओं को भुला कर, एक हो जाना चाहिए और सब को मिल कर समस्या का सामना करना चाहिये। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि वार साइकोसिस दूसरी बात है, युद्ध का वातावरण दूसरी बात है। लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा का वातावरण हम नहीं पैदा करेंगे तो हम देश के प्रति विश्वासघात करेंगे, राष्ट्र के प्रति विश्वासघात करेंगे। इसलिये हमें अपने प्रधान मंत्री जी से कहना है और जैसा वह स्वयं कह रहे हैं कि आज हम किसी से डरने वाले नहीं, लेकिन हम यह बात जरूर करेंगे कि हमें अपने देश को और राष्ट्र को सबल बनाना है और राष्ट्र को सबल बनाने के लिये राष्ट्र की जनता में देशप्रेम की भावना पैदा करनी है और ऐसी भावना पैदा करनी है कि चाहे चीन हो और चाहे संसार का कोई देश हो अगर वह हमारे देश पर लालच भरी निगाहों से आक्रमण करने की नीयत से, दृष्टि डालेगा तो हमारे देश का बच्चा-बच्चा अपने प्राणों की बलि देकर उसके दांत खट्टे कर देगा। यह बात हमें पैदा करनी है। आतंक नहीं पैदा करना है, बहादुरी पैदा करनी है जिससे न केवल आक्रमणकारी हमारे सामने टिक सके बल्कि आक्रमणकारी आक्रमण करने का साहस न करे।

मान्यवर, शान्ति की बात कही जाती है लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि—"Show of force is preventive for the use of the force." अगर हम शान्ति चाहते हैं तो आक्रमणकारी को यह मालूम होना चाहिये कि अगर तुमने आक्रमण करने का साहस किया तो तुम्हारी ऐसी पिटाई होगी कि लेने के देने पड़ जायेंगे, तब उनका साहस नहीं होगा कि वह आक्रमण करें। ऐसा इसलिये कि हमें अपने राष्ट्र को सबल बनाना है। मेरी समझ में नहीं आता कि चीन हमारे देश पर आक्रमण करे और देश के भू-भाग पर कब्जा कर ले तब आक्रान्ता नहीं होता, लेकिन अगर चीन समझौते से बातचीत करने के बाद, महीनों और बरसों तक बातचीत करने के बाद भी, हमारे भू-भाग पर वह कब्जा किये बैठा रहे तब वह आक्रान्ता नहीं होता? लेकिन अगर हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को सबल बनाने की बात कहें तो फिर उसमें आक्रान्ता कहा जाय यह बात समझ में नहीं आती। चीन हमें आक्रान्ता कहे उससे हमें क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब हमारे देश के लोग ही हमसे कहते हैं कि यह तुम अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिये नहीं बल्कि युद्ध का वातावरण पैदा करना चाहते हो तो वह चाहे माननीय चन्द्रजीत जी यादव हों या कोई देश का बड़े से बड़ा नेता हो, मैं कहता हूं कि उस समय मुझे प्रतिक्रियावादी होने में गर्व है और युद्ध का वातावरण पैदा करने में गर्व है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का वातावरण पैदा करना युद्ध का वातावरण पैदा करना समझा और कहा जाता है तो इस युद्ध के वातावरण को पैदा करने में हमें गर्व है।

मैं माननीय नेगी जी से इस बात में सहमत हूं कि मिलिटरी प्वाइंट आफ व्यू से सरकार क्या उपाय करे यह यहां के विवाद का विषय नहीं है; लेकिन उसी समय सरकार का यह भी

कर्तव्य हो जाता है कि यदि वह चाहती हैं विधान सभा में और लोक सभा में इस पर विवाद न हो तो ऐसे अवसर पर होना चाहिये जैसा कि सब सरकारें करती हैं कि वह विरोधी दलों को कान्फीडेंस में ले और एक सर्वदलीय सरकार बनावें। इसलिये ऐसे अवसर पर मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमें निश्चय ही इस विषय पर विवाद नहीं करना चाहिये कि मिलिटरी तैयारी क्या हो और उससे सम्बन्धित इंडस्ट्रियल तैयारी क्या हो, लेकिन दो तैयारियां ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं सरकार से कहूंगा कि वे तैयारियां अविलम्ब होनी चाहिये। उनको मैं दो श्रेणियों में बांट देता हूं। एक तो मेंटल तैयारी है अर्थात् मानसिक या साइकिक और दूसरी है मारल तैयारी, आत्मबल, नैतिक बल। यदि नैतिक बल हममें न हो तो सब शस्त्रबल रहते हुए, विज्ञान के बड़े से बड़े शस्त्रों के होते हुए भी हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते और नैतिक बल के बिना हम उनका उपयोग भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों प्रकारों की तैयारियों के सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि हमारी यह भावना आप केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचा दें कि यह दोनों तैयारियां हमारे देश में की जानी चाहिये। हमारे देश में यह भावना आनी चाहिये कि सन् १९४७ में हमने जो स्वाधीनता प्राप्त की वह जब खतरे में हो तब हमें एलान कर देना चाहिये कि हम स्वाधीनता को पराधीनता से बचाने के लिये मरना पसन्द करेंगे लेकिन हम स्वाधीनता को हानि नहीं पहुंचने देंगे।

मैं चाहता हूं कि इस तरह का देश में वातावरण हो, यह युद्ध का वातावरण नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का वातावरण होगा। हमारे विरोधी इस बात को समझ लें कि कोई भी आक्रमणकारी हो, चाहे वह चीन हो या अमरीका या रूस हो, अगर भारत पर आक्रमण होगा तो उसका एक-एक बच्चा अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह का भेदन करेगा। अगर भारत पर आक्रमण होगा तो भारत की एक-एक नारी झांसी की रानी होगी और भारत का एक-एक बूढ़ा भीष्मपितामह हो जायगा और देश की रक्षा करेगा। मैं चाहता हूं कि इस तरह का वातावरण पैदा हो। यहां का एक-एक युवक कहेगा "जो रन हमहिं प्रचारहि कोई, लरहिं सुखेन कोउ जनि होई।" कोई भी शत्रु हो हम उसका सामना करेंगे।

इसके साथ-साथ हमारे यहां नैतिक प्रिपरेशन होनी चाहिये मारल प्रिपरेशन ज्यादा जरूरी है। हमारे लिये आवश्यक है कि इस राष्ट्रीय महायज्ञ में हममें जो नैतिक कमियां हैं, हमारा जो नैतिक पतन हुआ है उसको स्वाहा कर दें और बहुत ऊंचे आगे बढ़ें, और हम इतना आगे बढ़ें कि हम कह दें कि चाहे हम अपने प्रदेश के भीतर आपसी मतभेदों के लिये मोटे तौर पर ३०० और १३१ हों लेकिन जब शत्रु का सामना करना होगा तो हम ४३१ होंगे, इस बात में कोई धोखा न रहे। इस बारे में हमारा मतभेद नहीं होगा। देश में हमें अभी से इस भावना को पुष्ट करना है और देश के हर बच्चे में जो ऐसा वातावरण आया है उसे हमें निरुत्साहित नहीं करना है बल्कि प्रोत्साहित करना है। अपने सम्बन्ध में मैं केवल एक बात कह देना चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में अगर कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिये बिगुल बजा तो मैं आपसी सभी बातों को भूलकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिये सेना के साथ सेपर एन्ड माइनर्स की तरह कार्य करूंगा और सरकार को सहयोग दूंगा। मुझे आशा है कि सरकार भी अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो प्रस्ताव पेश है मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ज्यादा आपसी वादविवाद का प्रश्न है।

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, पीठासीन हुए।)

आम तौर से सभी तरफ से कुछ मौलिक बातों को मानकर बातें कही गयी हैं। थोड़ा-सा फर्क जो कम्युनिस्ट पार्टी ने संशोधन पेश किया है वह इस बात का है कि चीन को आक्रमणकारी कहा जाय या न कहा जाय। बहरहाल, मेरा यह खयाल है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के सिद्धान्त का ताल्लुक है उसमें किसी को मतभेद इस बारे में नहीं है। सिर्फ मतभेद इतना हो सकता है कि कुछ दोस्तों का खयाल है कि तैयारी ज्यादा तेजी से होनी चाहिये। कम्युनिस्ट पार्टी भी मौलिक

[श्री गोविन्दसहाय]

रूप से उसी पालिसी की हामी है जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया है। अतः हमें इस बहस में इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपस में गर्मी लाने की कोई बात न हो।

पहला जो प्रश्न है वह यह है कि चीन ने ऐग्रेशन किया है या नहीं? इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं और मेरी ईमानदाराना राय यही है, यद्यपि हर मुल्क में बोर्डर डिस्प्यूट होते हैं, पाकिस्तान और भारत में भी है, लेकिन इस मामले में जो कुछ हुआ है उसको मैं केवल बार्डर डिस्प्यूट नहीं मानता। जो कुछ हुआ है, बहुत ठंडे तरीके से गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके अन्दर कोई दबी हुई साजिश तथा ख्वाहिश है और उसको किसी रूप में एक्सटेंशन की ख्वाहिश कहा जा सकता है चाहे वह टेक्नीकली हो या न हो, लेकिन चीन के समूचे व्यवहार से भारतीयों पर ऐसा असर पड़ा है कि हमारे साथ चीन ने जुल्म किया है, गलत काम किया है और एक तरह से आक्रमण हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? उसके भी कारण हैं। चीन के मामले में भारत ने सदैव से एक ऐटीट्यूड अख्तियार किया था। भारत ने चीन का समर्थन उस जमाने में किया था जब कि चीन का दुनिया में कोई दोस्त न था, तब भारत ने राष्ट्र-संघ में चीन के मामले को उठाया। जिससे मनुष्य का ज्यादा लगाव होता है अगर वह कोई गलत बात कर बैठता है तो उससे तकलीफ भी ज्यादा होती है। इसलिये चीन के इस व्यवहार से भारत को इतना क्षोभ हुआ है। जिसको उसने दोस्त समझा था उसने ऐसा कदम उठाया, इससे सभी को शिकायत का मौका मिला। भारतीय जनता पर इसीलिये ऐसा असर पड़ा कि उसने हमारे देश पर आक्रमण से पहले तिब्बत में सड़कें बनायीं और दूसरे ऐसे कार्य किये।

जनसंघ के नेता ने बड़े जोर से कहा कि इसकी सबसे पहली गलती वहां हुई जब कि हिन्दी चीनी भाई-भाई कहा गया, इसलिये नेगोसियेशन का रास्ता हमें छोड़ देना चाहिये और डकैतों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि मैं उनसे ज्यादा देशभक्त हूं, लेकिन किसी को गुस्से में डकैत कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि जब कभी दो राष्ट्रों में कन्फ्लिक्ट होती है तो पहले दोनों राष्ट्रों को नेगोसियेशन का रास्ता अपनाना चाहिये, ऐसी हमारी नीति है। मैं समझता हूं कि उस नीति को छोड़ देना सूसाइडल होगा। वह हमारी परम्परा है, हमारा इतिहास है, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं, अगर हम नेगोसियेशन का रास्ता अख्तियार नहीं करते हैं तो वह हमारी उस पालिसी के खिलाफ होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इन्डियन यूनियन गवर्नमेंट ने क्या यह प्रस्ताव पास नहीं किया था कि जब एग्रेसर जगह नहीं छोड़ता है तब हम उससे बात नहीं करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—अगर आप लोग आपस में बातें न करें तो अच्छा है।

श्री गोविन्द सहाय—आपस में बातें करने पर जब हीट पैदा हो जाती है तो पालीवाल जी को भी उससे बचना मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी राय बता रहा हूं, आप उससे इत्तफाक करें या न करें। मेरा कहना है कि नेगोसियेशन का रास्ता छोड़ना मुनासिब नहीं है।

अब सवाल आता है कि जो एग्रेशन हुआ है उसको दूर कैसे किया जाय। उसके लिये मुल्क में जो तैयारी होती है वह तीन प्रकार से होती है--दिमागी तैयारी, मारल तैयारी और तीसरी फिजीकल यानी मिलिटरी की तैयारी। देश के अन्दर अगर स्ट्रेंग्थ की बात है तो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये मोरेल स्ट्रेंग्थ और मेंटल स्ट्रेंग्थ का होना भी बहुत आवश्यक है। मैं इस बात में पालीवाल जी से सहमत हूं कि जो कुछ हुआ उसका मुकाबला होना चाहिये और उसका मुकाबला करने के लिये हमारे जितने साधन हैं उनको जुटाना चाहिये और उनको जुटाने के लिये जितने लोग उसमें शरीक हो सकते हैं, उसका दायरा बढ़ाना चाहिये। तो इस माने में जो एक बात कही गयी, मुझे खुशी है कि आज एक मसला आया जिसमें सब लोग एक मत के हैं और उनमें कोई मतभेद की बात नहीं है कि कंट्री के डिफेंस के लिये एक हो जाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ कंट्री के अन्दर जो आपकी ताकतें हैं उनका इकोनामिक कंसालिडेशन होना भी बहुत जरूरी है। देश के अन्दर एक सेक्यो-

रिटी पैदा करने की जरूरत है। इस लिये जिन दोस्तों ने युद्ध की बात की, मुझे आशा है कि वे देश के अन्दर कोई ऐसी नीति नहीं अपनायेंगे जिससे इंटर्नल डिस्ट्रक्शन हो या डिस्कंटेंटमेंट हो।

आज जो पोलिटिकल पार्टियां हैं वे भी इस बात को मानती हैं कि हमको समूचे साधन जुटाने चाहिये। तो जब उस समूचे साधन को डिफेंस की नजर से देखना है, तो होम फ्रण्ट पर सब में मेल होना भी सब पर फर्ज लाजिम हो जाता है। वे सब दोस्त जो मुकाबला करने की बात बहुत आवश्यक समझते हैं, उनको होम फ्रण्ट पर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिये जिससे इंटर्नल डिस्ट्रक्शन हो। और इसलिये होम फ्रण्ट परट्रूस होना जरूरी है। डिफेंस के प्राबलम को प्रोडक्शन के प्राबलम से जोड़ा जाय, डिफेंस के प्राबलम को इंडस्ट्रिअल प्राबलम से जोड़ा जाय, डिफेंस के प्राबलम को एग्रीकल्चर के साथ भी जोड़ा जाय, तो जो लोगों में अशान्ति की स्थिति है वह न हो। जो हमारा इंटर्नल फ्रण्ट है उसका मुल्क के प्रोडक्शन से सम्बन्ध जोड़ना बहुत जरूरी है।

जहां तक नेकनीयती की बात कही गयी है इसमें नेकनीयती और बदनीयती की बात बहुत काफी है। बदनीयती से मेरा मतलब एक्सप्लायटेशन से है। आज हमको सोचना यह है कि हम देश के अन्दर ऐसी आबोहवा पैदा करें जिससे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वे एक ही लहजे में चीन को जवाब दे सकें।

एक तरफ तो पेट्रियोटिज्म की बात की जाती है—लेकिन इस शब्द के ऊपर काफी बहस हो सकती है कि इसका असली मानी क्या है। अगर दुबे जी यहां होते तो मैं उनसे कहता। आज जो यहां पेट्रियोटिज्म की बात की जाती है, जब कि ब्रिटिश इम्पिरियलिज्म यहां था तो उस समय उनके खयाल के आदमियों को यह पता नहीं था और उन्होंने यह जरूरी नहीं समझा कि अपने देश को आजाद करने के लिये उस विदेशी शक्ति से लड़ाई लेनी चाहिये। आज मेरे बहुत से दोस्त लड़ाई की बात करते हैं। काफी दोस्तों ने पहले की लड़ाई में हिस्सा लिया जिससे देश को आजादी मिली, और आज भी वे लड़ रहे हैं तथा आगे को भी लड़ेंगे। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो सिचुएशन का फायदा उठा कर, Indo-China तनाव की स्थिति का फायदा उठा कर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जब मुल्क में लड़ाई का वातावरण हो तो उसके लिये आर्म्स के साथ-साथ सोशल इकोनामिक फ्रण्ट का होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिये जरूरी है कि राष्ट्रीय आन्दोलन की तरह से अपने मारल पोटेंसी को और इकोनामिक पोटेंसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय। यहां हम एक ऐसी आबोहवा पैदा करें और चीन के रवैये को एक छिपा हुआ ब्लेसिंग इन डिसगाईस समझें, चीन का जो रवैया है उससे उसने स्वयं एशिया में सोशलिज्म को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, भारतीय आत्मा को ठेस पहुंचाई है, और उनके रवैये से कम्युनिस्ट पार्टी को भी नुकसान हुआ है।

यह जो सोशलिज्म का मूवमेंट था और जो सोशलिज्म के एक्सपेरीमेंट्स चल रहे थे और जो एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने की बात चल रही थी उस में इस नीति ने एक जबरदस्त दीवार खड़ी कर दी है। इस समय ज्यादा एक दूसरे की मजम्मत का सवाल नहीं है, यह हमारी तैयारी का सवाल अधिक है। मैं उन माननीय सदस्य को बधाई देता हूं जो इस प्रस्ताव को लाये हैं। यह कोई इख्तिलाफ का सवाल नहीं है, यह सवाल इस बात का है कि अपने दिलों में और अपने दिमागों में साफ होकर सब के लिये यह लाजिम हो जाता है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा काम न हो जो उस मकसद के ही खिलाफ जाय जिस मकसद के लिये हम एक वातावरण और एक आबोहवा पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ तो हम मुकाबले की तैयारी करें और दूसरी तरफ ऐसी फिजा पैदा करें जिस में लड़ाई, झगड़े, स्ट्राइक, हड़ताल की चीजों को प्रोत्साहन दें। यह दोनों बातें मेल नहीं खायेंगी। अगर ऐसा होगा, ये चीजें बढ़ेंगी तो हम मिलिटरी एग्रेशन के नाम पर, मुल्क की सुरक्षा के नाम पर चाहे कितनी ही तैयारी करें, कितने ही साधन जुटायें, लेकिन वह वातावरण वह मारल, वह होम फ्रण्ट तैयार न हो सकेगा जिस की कि आज मुल्क को खास जरूरत है। हमारे खेत पर, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे लोगों के दिल व दिमाग में वह तैयारी न हो तो केवल मिलिटरी और डिफेंस के साधनों से ही देश की आजादी की सुरक्षा होने वाली नहीं है। हमें इन तीनों चीजों की तरफ पूरी तवज्जह देनी है। हमें अपने देश में ऐसी फिजा पैदा करनी है जिसके मातहत

[श्री गोविन्दसहाय]

हम अपने तमाम राष्ट्रीय तत्वों को एक साथ जोड़ सकें और हमारे प्रगतिशील राष्ट्रीय तत्व देश के मिलिटरी पोटेन्शियल को डेवलप कर सकें । हम अपने देश में ऐसी फिजा पैदा कर सकें कि हमारा समूचा देश किसी भी आक्रमणकारी डिजाइन्स का, चाहे वे चीन की तरफ से हों या पाकिस्तान की तरफ से हों, या किसी भी ओर से क्यों न हों, उन का मुकाबला कर सकें ।

सवाल यह भी है कि चीन के मामले में ही इतनी दिलचस्पी यहां के लोग आज क्यों लेते हैं, जब कि हमारा ४२,००० मील का रकबा पाकिस्तान ने भी ले रखा है ? उसके खिलाफ वह वातावरण क्यों नहीं पैदा होता, उन के मुकाबले में किसी को हमला नहीं दिखाई देता और चीन के मामले में दिखाई देता है ? यह साफ चीज है । चीन के मुकाबले में जब हमारा दिल व दिमाग साफ था इस कारण उसके वर्त्तमान कार्य में हमें विश्वासघात मालूम होता है, जो हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा लगा था और जो आशा इस देश के करोड़ों लोगों ने की थी उस को ठेस पहुंची है और उस से किसी का भला नहीं हुआ है । अब उस सिचुएशन को कौन कैसे रीड करता है, कैसे उसको पढ़ता है, कौन क्या रवैया पेश करता है इससे उस व्यक्ति या दल विशेष के सोचने के ढंग का पता चलता है । इस क्राइसिस के विषय में हमारा और कांग्रेस का एक रवैया है, एक सोचने का ढंग है जिस को प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल जी ने अपने संसद के भाषण में व्यक्त किया है । वही एक स्वस्थ तरीका है कि सुलह का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिये, मुकाबले की तैयारी रहनी चाहिये, देश की ताकत को बढ़ाना चाहिये, एक वातावरण और विचार तैयार होने चाहिए और जहां भी ऐसी ताकतें हों कि जो देश की आजादी को कायम रखने में बाधक हों और लड़ाना चाहती हों उन को तोड़ना चाहिये । इस में कोई मतभेद की बात नहीं है ।

इन चन्द शब्दों के साथ जो प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो रवैया चीन की तरफ से अख्तियार किया गया है उस के खिलाफ देश में सभी प्रकार का ऐसा वातावरण तैयार किया जायगा कि जो आक्रमण हुआ है उसके खिलाफ कार्यात्मक रूप में कार्य किया जायगा और जवाब दिया जायगा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो प्रस्ताव और संशोधन विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से उपस्थित हुये हैं उन प्रस्तावों में भी मैं एक प्रस्तावक के रूप में हूं । इसलिये अपने भाषण को आरम्भ करने के पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि प्रस्तावक की हैसियत से ही मेरे लिये भी समय का बंटन होना चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले भी यह कह दिया था, हमने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रथम दिन रखा था उस प्रस्ताव पर, कि इस प्रस्ताव पर बोलते समय पूरी तरह से हमारे मत का प्रकाशन हो सकेगा और ऐसा समय दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता---सिर्फ मूल प्रस्तावक महोदय को २५ मिनट दिये गये हैं । बाकी सबको १५ मिनट दिये जायेंगे ।

श्री राजनारायण---मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसको भाई गोविन्द सिंह जी द्वारा रखा गया है वह प्रस्ताव अपनी जगह पर बिलकुल सही है । मैं पहले से ही कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । चीन को मैं आक्रामक मानता हूं । चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया है । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और चीन का हमला हिन्दुस्तान पर आज नहीं हुआ है बल्कि चीन ने हिन्दुस्तान पर सन् १९५३ और ५४ में हमला शुरू कर दिया था । चीन की सेना क्रानली में ८० मील तक सन् १९५३-५४ में घुस आई थी । चीन की ओर से बार-बार हिन्दुस्तान की सीमा को चीन के नक्शे में दिखलाये जाने की बात शुरू हो गई थी और उस समय शुरू हुई थी जब हिन्दुस्तान में हिन्दी और चीनी भाई-भाई के नारे लग रहे थे, जब हिन्दुस्तान में चाउ एन लाई आये और जवाहरलाल जी गले मिल रहे थे । एक तरफ तो गला-मिलन हो और दूसरी तरफ चीनी हमारे मुल्क पर आक्रमण करते हों और हिन्दुस्तान की सीमा चीन के नक्शे में दिखाई जाती हो, क्या यह सही नहीं है ?

श्री चन्द्रजीत यादव नये कम्युनिस्ट हैं । नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है । मैं बताऊंगा कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी क्या है । हम आज अपने भाषण को तीन भागों में बांटेंगे ।

पहला कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा हमारे अब तक के प्रयत्न, और तीसरा जनता। मैं माननीय चन्द्रजीत यादव को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से सामने आये हैं। मैं अपने बुजुर्ग नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय पालीवाल जी को भी बतलाना चाहता हूं कि देश एक है, राष्ट्र एक है, सारी शक्तियां आक्रामक का मुकाबला करें, चीन का मुकाबला करें और हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा देश की बलिवेदी पर मिट जाने के लिये तैयार हो, यह सब सही है। हम देश की बलिवेदी पर मिटने को तैयार हैं। आक्रामक चीनी को पसन्द नहीं करेंगे, उसे यहां से मार भगायेंगे। क्या कम्युनिस्ट हिन्दुस्तान में नहीं रहते हैं? वह हमसे क्यों नहीं मिले? कम्युनिस्ट का और हमारा एका कैसे हो सकता है? हम कहते हैं, चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया है और कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि नहीं किया। पालीवाल जी कहते हैं कि हम और वह मिलें। ('शेम, शेम' की आवाजें) चन्द्रजीत यादव इतिहास देखें कम्युनिस्ट पार्टी का--सन् १९२४ से जब से पार्टी आई है सन् १९३६ तक की नीति, सन् १९३६ से ४० तक की नीति, सन् ४० से आगे की नीति और अब की नीति। हमेशा हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी नाबालिग रही। हमेशा हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रद्रोह किया और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ पाप किया। उनका एक अपना विश्वास है। उनका अपना मन्दिर है--पीकिंग और मास्को। उस मन्दिर से उनको दर्शन मिलता रहा है और मिलता रहेगा। एक नहीं हजारों पालीवाल जी बलिवेदी पर भले ही चढ़ जायें।

सन् १९३० और ३२ की आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी महात्मा गांधी जी की मुखालिफत करती रही। तिरंगा झंडा फाड़ती रही। बार बार कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी कि कांग्रेस पूंजीपतियों की जमात है, इसलिये इस लड़ाई में हमको नहीं शामिल होना है। परन्तु जब सन् ३६ में मास्को ने बागडोर खींची और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन हुए तब यह कांग्रेस में शामिल होने की बात करने लगी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में आये। श्रद्धेय आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने सारा दक्षिण का इलाका इनको दे दिया कि जाओ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संगठन करो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फंड और उसके साधन कम्युनिस्ट पार्टी को दिये गये। कम्युनिस्टों ने उस साधन का इस्तेमाल कम्युनिस्ट यूनियन बनाने में किया। जब उनकी चिट्ठियां पकड़ी गईं १९४० में तो यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से निकाले गये। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आया। उसमें शुरू-शुरू में जब गोल्डन चेन आफ फ्रेन्डशिप स्टालिन और हिटलर में बनी, हिटलर ने बम लंदन पर गिराना शुरू किया तब कम्युनिस्ट पार्टी यहां से कहती थी कि साम्राज्यवादी युद्ध हो रहा है, हम लड़ने के लिये तैयार हैं। लेकिन जब वह मित्रता की सुनहरी चेन टूट गई और हिटलर के बम मुंह फेरकर मास्को की ओर जाने लगे और ब्रिटेन, अमेरिका और रूस में संधि हुई तब हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। क्या हुआ बनारस की जेल में? यह यादव जी को नहीं मालूम होगा। वह उस समय बच्चे रहे होंगे। जेलों में बैठ करके एक रात में कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्राज्यवादी युद्ध को जन युद्ध में बदल दिया। अपने जनयुग अखबार को अंग्रेजों के पैसे से निकालना, सुभाषचन्द्र बोस को जापान का मित्र बताना, जय प्रकाश, लोहिया को जापान तथा हिटलर का दूत बताना और महात्मा गांधी को पूंजीपतियों का दलाल बताना, वगैरह वगैरह--इस प्रकार के नारे कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाये।

सन् १९४८ मार्का कांग्रेस इन कम्युनिस्टों का नहीं मुकाबला कर पायेगी। उसे सन् १९४२ मार्का कांग्रेस बनना पड़ेगा तब इनका मुकाबला कर पायेगी। जो मिनिस्टर चश्मा लगाये बैठे हैं यह नहीं मुकाबला कर पायेंगे। हमको भावावेश में नहीं जाना चाहिये बल्कि वस्तु-स्थिति में जाना चाहिये। माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने मार्क्स के उस कोटेशन को छोड़ दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति ही नहीं करता है बल्कि प्रगति भी करता है, आगे बढ़ता है। सन् १९४२ में जो इन्होंने गद्दारी की, स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया, जब कांग्रेस से निकाले जाने का प्रस्ताव आया तो इन्होंने राष्ट्रपिता, फादर आफ

[श्री राजनारायण]

दि नेशन के नाम एक पुस्तक लिखी और महात्मा गांधी जी से कहा कि हे पूज्य गांधी जी हम ही तुम्हारे पुत्र हैं, तुम अहिंसावादी हो और कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी ने देश में हिंसा के कृत्य किये हैं। लेकिन कृत्य सब हिंसा के इन्होंने ही किये। यह लिख करके गांधी जी के खैरख्वाह बनना चाहते थे लेकिन वह तो इनकी नस को अच्छी तरह पहचानते थे। वह मौखिक सहानुभूति से अपने को प्रसन्न नहीं रखते थे। बावजूद इनकी उन तमाम कोशिशों के यह कांग्रेस से निकाले गये १९४५ में। आज वही चन्द्रजीत यादव पंडित जवाहरलाल नेहरू की शरणागत हैं, कहते हैं, हे जवाहरलाल जी, आपकी शान्तिपूर्ण समझौता वादी नीति बिलकुल ठीक है। हम उसी के अनुयायी हैं, उसके भक्त हैं और आप देश को बचा रहे हैं, हम आपके साथ हैं।

मैं चाहता हूं माननीय चन्द्रजीत यादव याद करें कि कम्युनिस्ट प्रोलीटेरियट परिभाषा में क्या आता है ? कम्युनिस्ट सर्वहारा का कोई अपना मुल्क नहीं होता है। इस नाते उनका प्रस्ताव ठीक है। वह कहते हैं कि अगर हमारे देश पर कोई हमला होगा तो हम अगली कतार में रहेंगे। इनका कोई मुल्क ही नहीं है तो हमला किस पर मानेंगे ? यह हिन्दुस्तान पर हमला मानेंगे ही नहीं। इसलिये उनका प्रस्ताव अपनी जगह पर ठीक है। जब हिन्दुस्तान को अपना मुल्क मानें तब हिन्दुस्तान पर हमला कबूल करें। इसलिये उनका जो संशोधन है और जिसको परख माननीय गोविन्द सहाय ऐसे लोगों को तो हो ही नहीं सकती, जिन्दगी में, क्योंकि वह तो कल्चरल डेलीगेशन में चीन और रूस जाते हैं, पीकिंग का हलुवा खाने। मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार सम्हल जाय। हमारे देश का इतिहास बताता है कि यहां जयचन्द भी हुये, मीर जाफर भी हुये और विभीषण भी हुये। आज कम्युनिस्ट अपने को कह रहा है कि हम विभीषण हैं। आज कम्युनिस्ट कह रहा है कि जिस तरह राम की सेना आयी थी रावण से उद्धार करने के लिये उसी तरह से चीनी सेना आ रही है मुक्ति सेना के रूप में हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों से हिन्दुस्तान के गरीबों को छुटकारा दिलाने के लिये। क्या आज कांग्रेस पार्टी के सरकारी पक्ष में बैठे हुए लोग इन बातों से अवगत नहीं हैं ? मैं अवगत हूं, मैं किसानों के बीच में रहता हूं। आज यह कम्युनिस्ट किसानों से कहते हैं कि तुम्हारी दशा वही रह गयी है, संपूर्णानन्द बदल गये, कमलापति बदल गये, जवाहर लाल बदल गये और बहुगुणा की शेरवानी में फूल लगने लगा, मगर तुम अपनी जगह पर रह गये, तुम्हारा कुछ नहीं बदला। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकारी पक्ष के लोग जरा इस वस्तुस्थिति का अध्ययन करें। (हंसी) हंसिये नहीं। अगर उनको कम्युनिस्ट शक्ति का मुकाबला करना है तो देश के मन को बनाना होगा। देश का मन केवल राजनारायण, संपूर्णानन्द और जवाहर लाल नहीं हैं। देश का मन यहां की ग्रामीण जनता है। देश का मन है--यहां के किसान, मजदूर, यहां के नंगे भूखे मानव इंसान। उनकी दशा को सुधारिये, कम्युनिस्ट हमला अपने आप रुक जायगा वरना नहीं रुकेगा। वह किसान मजदूर के नाम पर उनको धोखा देगा बाद में। श्रीमन्, इतिहास से सबक लें। थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मैं और कह दूं।

श्री अधिष्ठाता--कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय मूल प्रस्ताव पर बोलिये तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री राजनारायण--मूल प्रस्ताव ही है। श्री चन्द्रजीत यादव ने कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो प्रस्ताव पेश किया उसकी वजह से मुझे मौका मिल गया।

श्री अधिष्ठाता--एक ही शब्द की व्याख्या में सारा समय न समाप्त हो जाय।

श्री राजनारायण--और फिर कभी कह दूंगा। तो मैं यह कह रहा था कि देश के बटवारे के बारे में माननीय चन्द्रजीत यादव सन् १९४१ से लेकर बराबर अपनी पार्टी के अखबार "जन युग" को पढ़ें। टू नेशन थ्योरी का नारा क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं दिया था? यह क्यों दिया था? मुसलमानों के प्रति कोई उनका अगाध प्रेम नहीं था। ये समझते थे कि अगर हिन्दुस्तान का बटवारा हो जायगा तो रूस को मौका मिलेगा कमजोर मुल्क में अपना अड्डा जमाने के लिये। मगर जब पाकिस्तान ने रूस से दोस्ती नहीं की और अमेरिका और इंग्लिस्तान से दोस्ती की तो आज पाकिस्तान दुश्मन है। क्या इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने दक्षिण में जाकर के द्रविड़िस्तान बनाने का नारा नहीं दिया था? क्या इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने उत्तर में जाकर सिक्खिस्तान बनाने का नारा नहीं दिया था? क्या इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने कश्मीर आजाद रहे, इसका नारा नहीं दिया था? क्या इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने तेलंगाना बना कर रहेंगे, इसका नारा नहीं दिया था?

शुरू से इसका इतिहास रहा है गद्दारी का, देशद्रोहिता का और वह इतिहास आज फिर सामने आया है। सन् १९४२ के गद्दार आज पुनः दूसरे रूप में सन् १९५९ के गद्दार साबित हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने सोच रखा था कि सन् १९४२ की गद्दारी के बाद संभवतः कम्युनिस्ट पार्टी अब सुधर जायगी। मगर मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९१७ से लेकर लगातार नारे इन्होंने बुलन्द किये और सन् १९२३ के बाद एक रूप में नारा बुलन्द किया कि स्टालिन हम सब का है, स्टालिन जिन्दाबाद। मगर उसी स्टालिन के मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। तो मेरे नौजवान मित्र, माननीय चन्द्रजीत यादव, अगर तुम्हारे में बुद्धि है तो इस वस्तुस्थिति का विश्लेषण करो। तुम कम्युनिस्ट पार्टी में जरूर शामिल हो गये हो, मगर नये हो। कम्युनिस्ट साजिश, कम्युनिस्ट तिकड़म, कम्युनिस्ट वितंडावाद तुम नहीं समझ पा रहे हो। आज अगर चीन की सेना दिल्ली में भी जाय तो ये कहेंगे कि मुक्ति सेना आ रही है, चलो स्वागत करो, स्वागत करो। और बराबर इन्होंने पूर्वी इलाकों में मुक्ति सेना का प्रचार कर रखा है। मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी से इनकी जानकारी करायी और उनको बताया कि हमारा रेडियो, हमारे समाचार-पत्र, हमारे प्रचार के जितने सरकारी और गैर सरकारी साधन हैं वे इन बातों को क्यों नहीं प्रकाश में लाते हैं, मगर उसकी तरफ कोई खयाल नहीं किया गया।

अब मैं सीमा की तरफ जाना चाहता हूं। मैंने पहले ही बताया था कि लद्दाख के बारे में क्या आज भी ये मानने के लिये तैयार हैं? संशोधन रखते हैं कि लद्दाख हमारा है, हिन्दुस्तान का है और अब से नहीं बहुत पहले से। आपने लाल बत्ती जला दी, नहीं तो लद्दाख का इतिहास मैं बताता। लद्दाख का पूरा इतिहास हमारे पास है। सन् १८३४ में जोरावर सिंह की सेना ने लद्दाख को काश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के आधिपत्य में किया। आज से नहीं, बहुत पहले से लद्दाख हिन्दुस्तान का है, रहा है और रहेगा। एक नहीं, हजार कम्युनिस्ट शक्ति उसको अलग नहीं कर सकती। हमारी सरकार को अपनी सीमा के बारे में सचेत होना चाहिये। नेपाल में क्या हो रहा है? एक हमारे मित्र के० आई० सिंह हैं। उन्होंने बयान दिया है कि नेपाल जिस तरह से हिन्दुस्तान को मानता है उसी तरह से चीन को भी मानता है। मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९४६ में के० आई० सिंह कहां थे जब बनारस में नेपालियों का हमने संगठन किया। डाक्टर लोहिया ने १९४६ में गोआ का आन्दोलन शुरू किया था, उसी समय से नेपाल की आजादी की लड़ाई में भी डा० लोहिया ने नेतृत्व प्रदान कर हिन्दुस्तान को उसके साथ शामिल किया। इसलिये नेपाल के प्रति होने वाले आक्रमण को हिन्दुस्तान पर आक्रमण माना जायगा, अगर यह नेहरू जी कहते हैं तो सही कहते हैं और हमको विचलित नहीं होना चाहिये। आज सरकार ने अपनी दुर्बल नीति के कारण चीन को न्योता दिया हिन्दुस्तान पर हमला करने के लिये। चीनी खतरे का सामना करने के लिये सरकारी नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा, सीमा पर रहने वाली जनता से तादात्म्य करके उन्हें उठाना होगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है मैं इसका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ विरोधी पक्ष की उन पार्टियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि चीनी आक्रमण से भारत की जनता में जो बेचैनी और गुस्सा पैदा हुआ है उसका कुछ थोड़ा-सा प्रतिबिम्ब उन्होंने अपने इस प्रस्ताव के रूप में रखा है। मुझे इस बात का खेद है कि हमारे देश और विशेषकर इस प्रदेश की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने में अपना हस्ताक्षर नहीं किया। साथ ही साथ मेरे मित्र चन्द्रजीत जी यादव ने एक संशोधन पेश किया। मुझको कम्युनिस्ट पार्टी की देश भक्ति में कभी कोई संदेह नहीं था और करना भी नहीं चाहिये। मगर बदकिस्मती हमारी और उनकी दोनों की यह है कि कुछ उनकी तरफ से जो काम होते हैं उनसे संदेह पैदा होने लगता है। आज देश में जो वातावरण है, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जो आज जनसाधारण में भावना है उसके समाधान का एक ही तरीका था कि यह प्रस्ताव केवल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विधान सभा में पेश किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को आइसोलेट किया और दूसरी पार्टियों ने इस प्रस्ताव को हाउस में पेश किया।

मान्यवर, कहा गया कि वार साइकोसिस नहीं पैदा करना चाहिये। मुझे आप क्षमा करें यदि मैं कहूं कि जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसकी इससे ज्यादा सीधी और साधारण भाषा हो नहीं सकती थी। जितना गुस्सा हिन्दुस्तान के अन्दर है और जितनी लोगों के अन्दर हलचल और बेचैनी है उसका सही प्रतिबिम्ब हमारे इस प्रस्ताव के अन्दर नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे कम्युनिस्ट मित्र ने इस तरह का संशोधन दिया यह एक दुःख की बात है।

हमारे मित्र गोविन्द सहाय जी ने कहा कि निगोशियेशन का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिये। इस प्रस्ताव में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि निगोशियेशन के रास्ते को छोड़ दो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टैंड लिया है उसके खिलाफ एक शब्द भी इसमें नहीं है। सिर्फ इसमें इतनी बात लिखी है कि चीन ने जो भारत की सीमा पर आक्रमण किया है उसका हम कन्डेमनेशन करते हैं। अगर कन्डेमनेशन भी न करें तो क्या तारीफ करें? एक सीधा सादा शब्द है "कंडेमनेशन" का। साथ ही साथ दो बातों की मांग की गयी है, एक तो हमारी सिक्योरिटी को स्ट्रांग किया जाय और दूसरे उस क्षेत्र को डेवलप किया जाय ताकि वहां से गरीबी दूर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज परिस्थिति स्पष्ट है। मैं पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता हूं और माननीय नारायण दत्त तिवारी तथा राजनारायण जी ने कम्युनिस्ट पार्टी का लम्बा चौड़ा इतिहास सदन के सामने रखा है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं इस पार्टी के प्रति इस समय कोई बात कहना नहीं चाहता हूं। यह सही है कि जब मैं हिन्दुस्तान से आस्ट्रेलिया गया तो वही समय था जब वहां खबर पहुंची थी कि चीन ने हिन्दुस्तान के ९ सिपाहियों को लूट कर दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। आस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तथा अन्य राजनीतिज्ञों के सामने यही प्रश्न था—मैं भी उस समय मौजूद था—कि बताइये पंडित जी की अब क्या नीति होगी। "उनको तो कम्युनिस्ट कंट्रोल पर बड़ा भारी भरोसा था" और वहां के लोगों ने यह भी कहा कि "अब तक हिन्दी चीनी भाई भाई थे लेकिन अब बाई बाई हो गये।" श्रीमन्, अजीब स्थिति है और मैं इस बात से सहमत हूं कि हम सब को भाई-भाई मानते हैं—"वसुधैव कुटुम्बकम्", हमारा आदर्श यही है लेकिन एक उदाहरण हो, दो हों, तीन हों, हमेशा चीन ने इसके विरुद्ध काम किया और मैं कह सकता हूं कि चीन ने जो हमारे साथ किया है, उस की मिसाल मिलना कठिन है। विश्व के इतिहास में इतना बड़ा विश्वासघात शायद ही किसी और ने किया हो जितना चीन ने किया है। सोचिये जिस समय चीन का कोई मित्र व विश्वासी नहीं था उस समय हिन्दुस्तान ने सबकी नाराजगी उठाकर यह कहा कि यू० एन० ओ० में चीन को भी स्थान दिया जाय। यही नहीं हिन्दुस्तान पर एग्रेशन होने के बाद भी उसी नीति को अपनाया गया जिसकी वजह से हमारे सुरक्षा मंत्री, श्री मेनन की इतनी बड़ी आलोचना हुई। एक तरफ, श्रीमन्, हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के साथ भाई चारे को निभाया और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट मुल्क चीन ने यह किया। एक हमारी तरफ से तो दोस्ती की बात कही जाय और

उसी के साथ-साथ उनकी तरफ से पीठ में छुरा भोंकने की बात की जाय। मैं इससे भी सहमत हूं कि अभी देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि हिन्दुस्तान में वार साइकोसिस पैदा की जाय लेकिन मोठी-मोठी बातें भी कहने और भुलावे में पड़े रहने का हमारे पास समय नहीं है। देश को हर परिस्थिति में तैयार ही रहना चाहिये।

श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि प्रधान मंत्री के पत्र को गये हुये तीन सप्ताह से ज्यादा हो गये लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात हैं उसका कोई जवाब चीन से नहीं आया है। आज परिस्थिति यह है और कम्युनिस्ट भाई कहते हैं कि निगोशियेशन्स की बात करो। हमने अभी तक वही किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर चीन नहीं मानता है तो हमारे पास क्या तरीका है उन हिस्सों को वापस लेने का जिन पर चीन का अधिकार है? (आवाजें---युद्ध) यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि युद्ध किया ही जाये पर हमको उसके लिये भी तैयार रहना ही है। मैं उनसे पूछता हूं कि आज दो प्रश्न हैं। एक तो यह कि चीन का अब आगे आक्रमण होने नहीं देंगे। दूसरा यह कि जहां हो गया है उसका क्या करेंगे? चीन ने जहां कब्जा कर लिया है उसको उनसे खाली कराना होगा, तो जो परिस्थिति है उसमें निगोशियेशन्स तो चल ही रहे हैं। विधान सभा के सामने केवल एक ही बात है कि वह इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार जो स्वयं जागी हुई है, सचेत है, उसका पुनः ध्यान आकर्षित किया जाय। साथ ही साथ जो जन धारणा है यानी प्रदेश की जनता की आवाज को जो यहां रखा गया है वह भारत सरकार के पास पहुंच जाय।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि अक्सर कहा जाता है कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां इस चीज का फायदा उठा रही हैं और मेरे मित्र गोविन्दसहाय जी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने ४२ हजार स्क्वायर मील जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन चीन के पास केवल २० हजार मील ही है और उस पर यह सारा शोर मचाया जाता है। इस तरह की चीज मेरी समझ में नहीं आई। मैं मानता हूं, कि चाहे पाकिस्तान हो या कोई देश हो, जिसके कब्जे में हिन्दुस्तान की एक इंच भी जमीन है उस जमीन को वापस लेना है, अगर हममें राष्ट्रीयता है। पाकिस्तान और चीन के मुकाबले का सवाल नहीं है। पाकिस्तान भी एग्रेसर है और चीन भी एग्रेसर है। हमको दोनों का सामना करना है। पाकिस्तान की स्थिति एक और भी है, चूंकि उसका मामला सीक्योरिटी काउंसिल में है।

एक बात और भी है कि यादव जी ने कल यह कहा कि चीन ने कभी भी हिन्दुस्तान को यह नहीं कहा कि हिन्दुस्तान एग्रेसर है। मैं जानता नहीं कि एग्रेसर की क्या डेफिनीशन है। अगर चाऊ एन लाई के पत्रों को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि उन्होंने पंडित नेहरू को इम्पीरियलिस्ट और ऐक्सपैंशनिस्ट भी कहा है। तो इस तरह की टेक्निकल बात कहना कि एग्रेसर कहा है या नहीं कहा है निरर्थक है। आज एक बात की खुशी है कि पंडित जी के प्रति एक बड़ी मुहब्बत की लहर हमारे कम्युनिस्ट भाइयों में पैदा हो गयी है, यह अच्छी बात है। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि जिन पंडित जी के प्रति आज इतना प्रेम उमड़ रहा है उन्हीं को अमेरिका का दलाल कहा गया और जब केरल की सरकार खत्म हुई तो पंडित जी को कौन-कौन से तमगे नहीं दिये गये। वह एक दुख की बात है। मैं उन लोगों में से हूं जिनके कम्युनिस्ट पार्टी में अपने व्यक्तिगत दोस्त भी हैं। चाहता हूं कि उनकी बात पर विश्वास करूं, लेकिन दुख है कि जब उनके कारनामे सामने आते हैं तो विश्वास अपने आप हट जाता है। उन्होंने फरमाया कि हम जनतंत्र को मानते हैं। मेरा विश्वास है कि कम्युनिस्ट जनतंत्र पर विश्वास कर ही नहीं सकता और जिस दिन विश्वास करेगा उस दिन वह कम्युनिस्ट नहीं रहेगा। केरल के अन्दर जो कुछ हुआ उसने यह साबित कर दिया कि उनका जनतंत्र में कितना विश्वास है। सन् १९४२ में जब कि हम अपनी आजादी की जंग में लगे हुए थे उस वक्त पीपुल्सवार का नारा लगाया गया। लेकिन जब देश की आजादी आयी, चाहे वह उनके हिसाब से इत्तफाक से आयी हो या पूज्य महात्मा गांधी के नेतृत्व में त्याग और बलिदान से आयी, जैसे भी आयी, उसमें वह भी हमारे बराबर के साथी हैं। अच्छी बात है। वह हमसे कहते हैं

[श्री नवलकिशोर]

कि हम देश भक्ति में आपके साथ हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती। वह हमारे साथ भी हैं और प्रस्ताव में संशोधन भी देते हैं, ऐसे प्रस्ताव के अन्दर जो कि बहुत ही माइल्ड और इन्नोसेंट है। यह जिस भाषा में आया है, वह क्रान्तिकारी भाषा नहीं है अगर इसमें जोश होता या युद्ध मनोवृत्ति होती, तो उस भाषा में न आता, उसमें अधिक फायर (आग) होती। इतना सीधा सादा प्रस्ताव आया है जिसके अन्दर केवल अनुचित कह कर छोड़ दिया जाय "भर्त्सना भी न की जाय," यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आज जो गम्भीर समस्या है वह केवल प्रस्ताव पास करने से हल नहीं हो सकती। जिस प्रकार का खतरा है उसमें आज जनतन्त्र भी अपनी कसौटी पर है। दुनिया इस प्रयोग को देख रही है। अगर हिन्दुस्तान के अन्दर जनतन्त्र कामयाब नहीं हुआ तो एशिया से जनतंत्र बिलकुल खत्म हो जायगा। ऐसी स्थिति में वह तमाम राजनीतिक पार्टियां जिन जिन का जनतन्त्र में विश्वास है उनका फर्ज है कि आज इस संकट काल में, जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, उसके लिए एक हो जायं और एक मत से देश के साथ खड़े हों। कांग्रेस पार्टी का उससे बड़ा उत्तरदायित्व है। आज देश के अन्दर जो आवाजें आती हैं, कांग्रेस पार्टी का फर्ज है कि अपने में एकता कायम करे। जब अपने में वह एकता कायम कर लेगी तो राष्ट्रीय एकता की मांग तथा उसको कायम करने में उसको सुविधा होगी। जब राष्ट्रीय एकता पैदा हो जायगी तो चाहे चीन हो या पाकिस्तान, उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार, जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है वह उस जिम्मेदारी को उठाने के लिये मजबूत है और उठायेगी। एक दो बात और कहना चाहता हूं। जहां तक बार्डर का सवाल है मेरे दोस्त मिस्टर विष्ट ने जो कहा वह ठीक है। वहां की जनता गरीब है। गरीबों के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी को प्रचार करने का मौका मिलता है और तिब्बत की तरफ से जो स्पाईज आते हैं और एजेंट आते हैं वह कहते हैं कि मुक्तिसेना आ रही है और हम तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे। इसलिये यह जरूरी है कि वहां इस तरह की योजनायें चालू की जायं जिससे कि वहां के रहने वालों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो और वह उनके प्रचार के शिकार न हों। एक बात मैंने अखबार में पढ़ी जो कि मेरे दोस्त विष्ट जी ने सूचना विभाग के बारे में कही थी। मैं इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट की बात नहीं कहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े-बड़े सीक्रेट्स हैं वह सब लीक आउट होते हैं और अखबारों में छप भी जाते हैं। मान्यवर, यह एक बड़े सोचने की बात है कि ऐसे समय में जब कि देश के ऊपर संकट हो, जबकि हो सकता है कि किसी वक्त भी हमारी फौजें इधर से उधर भेजी जायं, सैनिक हलचल हो, तो ऐसे समय में सरकार को इस बात के लिये बड़ा सतर्क रहना है कि अगर इस तरह के अफसरान किसी भी डिपार्टमेंट में हों, अगर उनमें देश-भक्ति न हो, अगर वह ट्रेटर हों और स्पाइज हों तो उनके साथ आयरन हैंड से डील किया जाय और उनको चेक आफ करना, निकाल देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे ऐसे ही पास करेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस वक्त यह प्रश्न सदन में प्रस्तुत हुआ और जब इस की चहल-पहल हाउस में देखी तो तबियत में एक उमंग पैदा हुई देश के प्रति और उसकी सुरक्षा के प्रति जोश पैदा हुआ। परन्तु जब उसके ऊपर संशोधन देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि अपनी बाहें धोखा दे रही हैं, ऐसा मालूम हुआ कि अपने पैर जवाब दे रहे हैं, ऐसा मालूम हुआ कि आंखों की रोशनी जवाब दे रही है। अधिष्ठाता महोदय, संशोधन देखकर कुछ पुरानी तवारीख की तरफ नजर घूमने लगी और याद आने लगी वह बात जब कि मुहम्मद गोरी ने चढ़ाई की थी और उसके हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने के वक्त जो दुर्बल नीति और नम्र व्यवहार पृथ्वीराज ने बरता था और उसके बाद फिर पृथ्वीराज के साथ मुहम्मद गोरी ने विश्वासघात किया, आज वह चीज बिलकुल चरितार्थ हो रही है। एक बात की मैं आपको और आपके द्वारा सदन को याद दिलाना चाहता हूं। इसी सदन में हमारे माननीय सदस्य जो बोर्डर के रहने वाले हैं, माननीय प्रतापसिंह जी, जिन्होंने कि बार बार इस सदन को चेतावनी दी थी कि भोटिया ट्रेड चल रहा है, मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमको इस सब बात की खबर है।

बार बार इस बात की चेतावनी दी गई, बार बार इस बात का एलान किया गया कि यह भोटिया ट्रेड जो चल रहा है इसका ठीक वही नक्शा है जो कि किसी जमाने में, सन् १६०० के जमाने में नवाब अली वर्दी खां, मुर्शिदाबाद के नवाब, के साथ अंग्रेजों ने अपना ट्रेड शुरू किया था । जिस तरह से अंग्रेज मुर्शिदाबाद में दाखिल हुये थे बिलकुल ठीक उसी तरह से यह चीनी दाखिल होंगे, यह योजना बन रही थी । मगर इस तरफ से उदासीनता बरती गई । कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया । सन् ४२ में जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता ठीक वही काम कर रहे थे जो कि कलकत्ते में अंग्रेजों को पनाह देने के लिये और मुर्शिदाबाद के नवाब शुजाउद्दौला को शिकस्त देने के लिय सेठ अमीचन्द कर रहे थे । सन् ४२ में वह यही पार्ट अदा कर रहे थे जिस वक्त कि माननीय पटेल साहब हैदराबाद को मुक्त कराने के लिये रजाकारों पर प्रतिबन्ध लगा रहे थे, उस वक्त के ऊपर ठीक कम्युनिस्ट पार्टी ने मानसिंह का पार्ट अदा किया था । उस वक्त के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ने हिन्दुस्तान में एक घबराहट पैदा की ।

एक बात मैं आपके द्वारा और सदन को बताना चाहता हूं । आज जो लखनऊ से कम्युनिस्ट आसाम में जाकर भर्ती होते हैं और वहां पर स्वयंसेवक का रूप ग्रहण करते हैं वह काम आज ठीक उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से जयचन्द ने किया था। यह एक बात नहीं है बल्कि अनेक दृष्टान्त आपके द्वारा मैं इस सदन को प्रस्तुत करना चाहता हूं । एक बात और बताना चाहता हूं कि कलकत्ते में दस हजार आदमियों का एक जलूस निकला और उसका यह नारा बुलन्द हुआ कि अगर चीन यहां आयेगा तो हम उस चीन का स्वागत करेंगे । आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से कहेगा कि अगर यहां पर चीन आयेगा तो उसका स्वागत करेंगे और वह हमारा रक्षक है, हमारे लिये मुक्ति फौज लेकर आ रहा है । इस तरह से जयचन्द, सेठ अमीचन्द और मीर जाफर का पार्ट अदा करने वालों को इस देश की सरकार ने नजरअन्दाज किया है और अगर उसने नजरअन्दाज नहीं किया है तो कम से कम धोखे में वह जरूर रही है । आज उस सरकार को सचेत करने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है ।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात और आपको बतलाना चाहता हूं । इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस वक्त लखनऊ में नवाब वाजिदअली शाह के महल में २०० पालकियों में बेगमों को परदा डाल कर लाया जा रहा था और जब वह पालकियां महल में उतारी गईं तो उनमें बन्दूकों से लैस अंग्रेज सिपाही निकल पड़े । ठीक उसी तरह से अल्मोड़े में एक लोक कलाकार संघ की स्थापना हुई है और उस लोक कलाकार संघ ने सिर्फ वही कार्य करना शुरू किया है जो अंग्रेजों ने पालकियों में बैठकर लखनऊ में नवाब वाजिदअली शाह के महल पर कब्जा करके किया था ।

आपको एक बात और बतलाना चाहता हूं । जिस वक्त के ऊपर जिस तरह से नवाब नकी ने उन पालकियों का स्वागत किया था ठीक उसी तरह से नवाब नकी की तरह लोक कलाकार संघ आज अल्मोड़ा में सरहद पर उन चीनियों का स्वागत करने के लिये तैयार है । यह भी आपसे निवेदन करूं कि जिस समय मैंने इस प्रस्ताव को देखा तो मेरी समझ में कुछ बात आई । उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस प्रस्ताव के दो शब्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । उनकी तरफ किसी माननीय सदस्य ने गौर नहीं किया । उसमें जो संशोधन लिखा है वह इस प्रकार है "को अनुचित समझता है" अगर इन शब्दों को यहां पर रख दिया जाता है तो उससे यह साफ हो जाता है । "आदि भारत विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना" को वह निकालना चाहते हैं । जिस चीज को हम उचित समझते हैं कि चीन की उसके कार्यों के लिये भर्त्सना की जाय उसको वह निकालना चाहते हैं । जह इस चीज को अनुचित समझते हैं । उनका मतलब यह है कि हम जो यह भर्त्सना कर रहे हैं अनुचित है । माननीय सदस्य इसको पढ़ें तो साफ हो जायगा । उनका प्रस्ताव है कि "ठहराने" तथा "करता है" क बीच के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर "को अनुचित समझता है" रख दिये जायं । अब यह बनता है कि "आक्रान्ता तथा अनधिकृत अधिकारी ठहराने को अनुचित समझते हैं" । अधिष्ठाता महोदय, इससे अधिक गद्दारी की बात दूसरी नहीं हो सकती है । मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको देखा जाय कि यह कितनी बड़ी गद्दारी है ।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन में यह कहा गया है कि "चीनी लोकगणराज्य" रख दिया जाय। उनके लिये ये शब्द रख दिये जायं जिन्होंने हमारी इतनी बड़ी दोस्ती को दुश्मनी की तलवार से कत्ल कर दिया। उसके लिये गणराज्य लिखा जाय जिसने इसका खुद विरोध किया है। हमसे इससे क्या मतलब है कि हम उसको चीनी कम्युनिस्ट राज्य न कहें। जब केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो उसके लिये यह कहा गया कि हमने वहां पर कम्युनिस्ट सरकार बनाई और कम्युनिस्ट राज्य कहने में आपको कोई हिचक नहीं है, मगर चीन को कम्युनिस्ट राज्य कहने में आपको लज्जा मालूम होती है और हमारी तरफ से अगर कम्युनिस्ट राज्य चीन के लिये कहा जाता है तो वह चीज आपको बहुत अखरी।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि अभी उधर से एक कम्युनिस्ट सदस्य ने आवाज कसी कि गान्धी जी की हत्या किसन की। हम समझते हैं कि गान्धी जी की हत्या अन्धी साम्प्रदायिकता ने की, यह सारा देश जानता है। मगर इस देश की हत्या कौन करेगा? यह अन्धी अन्तर्राष्ट्रीयता इस देश की हत्या करेगी, लेकिन हम कभी इसकी हत्या नहीं होने देंगे, न इसे बर्दाश्त करेंगे, इस देश की हत्या इस अन्धी अन्तर्राष्ट्रीयता द्वारा नहीं होने देंगे। इस देश का बच्चा-बच्चा कुर्बान हो जायगा लेकिन इस देश की हत्या नहीं होने पायेगी।

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि समय कम है और बहुत से सदस्यों को बोलना है, इसलिये जल्दी जल्दी कहने की जरूरत है। कम्युनिस्ट चीनी व्यवहार के प्रति कहा जाता है कि नफरत न पैदा की जाय, लोगों में डर न पैदा किया जाय। क्यों न किया जाय? जब उन्होंने अपने सारे चीन में हमारे देश के प्रति नफरत पैदा की है, माननीय जवाहरलाल जी के प्रति नफरत पैदा की है, उनके दत्तक पुत्र इस देश के कम्युनिस्टों ने इस देश में नफरत पैदा की है और कर रहे हैं तो हम क्यों न अपने देश में चीन के प्रति नफरत पैदा करें? अगर हम नफरत न पैदा करेंगे तो हमारे जवान तैयार नहीं हो सकेंगे। इसलिये हम नफरत पैदा करेंगे और जरूर करेंगे और एक-एक जवान की नस नस में जोश भर देंगे ताकि देश का एक एक नौजवान इस के लिये तैयार हो सके। कहा गया था "हिन्दी चीनी भाई भाई"। ठीक है, लकिन आज देश की सुरक्षा का सवाल है। एक तरफ राजनीतिक दांव पेंच, दूसरी तरफ हिन्दी चीनी भाई भाई का झूठा नारा—किसी ने कहा है कि :

"यह सियासत है कुछ बात न ऐसी वैसी,
ग़ैरों की कहे कौन सगे बाप की ऐसी तैसी।"

अधिष्ठाता महोदय, माननीय खाद्य मंत्री का भाषण हुआ और मुझे उसे सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे कि आप निश्चिन्त रहें, कुछ नहीं हो सकता है। कबूतर की यही खसलत होती है। उसके सामने जब बिल्ली आती है तो वह आंख बंद कर लेता है और यह महसूस करने लगता है कि बिल्ली है ही नहीं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उसके पास केवल चोंच और टांगें ही बच जाती हैं और कुछ नहीं रह जाता। यही खसलत आप लोगों की मालूम हो रही है। यह भावना हममें नहीं आनी चाहिये। हमारे खाद्य मंत्री जी ने कहा कि जब तक हम जिन्दा हैं हम उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, आप खाद्य मंत्री हैं, चाह जितनी लम्बी चौड़ी बात कह डालिये। आप मंत्री हैं, आपको इसका अधिकार है, लेकिन इतना आप याद रखें कि जब तक देश जिन्दा है तब तक आप जिन्दा हैं और अगर देश जिन्दा नहीं रहता तो आप जिन्दा नहीं रह सकते। आपने बाराहोती पर १९०० में कब्जा करने की बात बताई। मरे हुये लड़के की बड़ी-बड़ी आंखें होती हैं। वह जमाना कौन था, शासक कौन था? अंग्रेजों का निजाम उस समय था। उस समय उन्होंने जो किया उस पर आपको आज अभिमान हो रहा है। मरे हुये लड़के की तो आंखें बड़ी होंगी ही, जो सामने है उसकी ओर देखो और बात करो। हमारे खाद्य मंत्री जी को आशा है कि कम्युनिस्ट अपनी पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में आने वाले हैं। हमको ऐसा मालूम हुआ कि बहुत मुमकिन है कि खाद्य मंत्री जी आज ही कांग्रेस की मेम्बरी की एक कापी लेकर शाम को उनके कमरों में जायं

उनको चवन्नी का मेम्बर बनाने के लिये । उनकी आशा से ऐसा मालूम हुआ कि इनकी अब शुद्धि होने वाली है । मैं कहता हूं कि उनकी शुद्धि हो नहीं सकती, उनकी शुद्धि न आप कर पायेंगे और न हम और न किसी वेद में इनकी शुद्धि के लिये कोई मंत्र है ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय । इस मामले में जितना भी कहा जाय थोड़ा है, लेकिन चूंकि बहुत से लोग कहने वाले हैं इसलिये मैं थोड़ा ही कह कर समाप्त करूंगा । मेरा सुझाव है कि अगर इस देश की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, तो इधर के जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उनको देख समझ कर, वहां की नाजुकता देख कर, परेशानी देखकर, जो खतरा है उसे देखकर, इस प्रदेश और देश के कम्युनिस्टों को काठगोदाम से आगे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ताकि उसके आगे वे न जाने पायें । अगर इसमें आपने गफलत की तो वहां के सारे नक्शे और रेखायें चीन तक पहुंच जायेंगी और वे इसी रास्ते से यहां आ जायेंगे । माननीय नेगी जी कहते हैं कि वे ७ दिन में यहां पर नहीं आ पायेंगे, यह गलत है । यहां से चांद तक जाने में ४८ घंटे से ज्यादा देर नहीं लग सकती है, तो बाराहोती से और लीपूलेक से लखनऊ और दिल्ली कितनी दूर है ? हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे देश का, प्रदेश का जब तक एक भी बच्चा जीवित रहता है, तब तक उनका मुकाबला किया जायेगा और उनको यहां आने नहीं दिया जायेगा । अगर हमारे प्रदेश के सामने गुलामी का सवाल आता है तो हमारे प्रदेश की जनता प्राणों की आहुति देकर उसकी रक्षा करेगी, छै दर्रों से जहां पानी की नदियां बहा करती हैं, वहां उन्हीं दर्रों में अपने खून की नदियां बहाने को सदैव तैयार रहेगी ।

*

(इस समय २ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एक ही इकलौता बेटा है जिसकी उम्र करीब १६ साल की है । इस देश की सुरक्षा के लिये मैं उसकी बांह माननीय कमलापति त्रिपाठी और बाबू सम्पूर्णानन्द जी को पकड़ाये देता हूं और यह आश्वासन देता हूं कि जब तक देश की सुरक्षा नहीं हो जाती, जब तक एक एक चीनी सीमा से बाहर खदेड़े नहीं जाते, उस वक्त तक उसको मुझे वापस न किया जाय ।

कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी (जिला इलाहाबाद)---मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए अपने कुछ विचार इस सदन के समक्ष रखना चाहती हूं । माननीय राजनारायण जी ने जो भाषण दिया उसका उत्तर तो मुझे देना नहीं है, उसका उत्तर तो कम्युनिस्ट भाई ही देंगे ; लेकिन अगर नारायणदत्त जी यहां होते तो मैं उन्हें बता सकती थी. . . .

श्री शिवप्रसाद नागर---वह यहां मौजूद हैं ।

कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी---ठीक है । तो मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में इन वीर बहादुरों के होते हुए यह असंभव है कि चीनी देहली या लखनऊ तक ७ दिन में चले आयेंगे । वे अपने दिल पर हाथ रख कर कह दें कि क्या हमारे होते हुए चीनी यहां आ सकते हैं । कदापि नहीं । मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि ऐसा नहीं हो सकता ।

आज मुझे बहुत सी पुरानी बातें याद आ रही हैं । जब जापानीज के आने का डर था तो मीरा बहन ने बापू को लिखा कि देहाती भी कहते हैं "Oh, the aeroplanes that make a great noiseare British, but there are silent planes also. They are Mahatma's planes." तो मैं यह कहना चाहती हूं कि वह साइलैन्ट बापू के प्लेन्स अभी भी मौजूद हैं । हम देश की रक्षा के लिये कोई भी कसर उठा नहीं रखेंगे । हम सब बापू के बच्चे देश की रक्षा के लिये सदैव तत्पर रहेंगे । हमें गांधी जी की विचारधारा को जीवित रखना है । हमारा

[कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी]

बच्चा-बच्चा देश की सुरक्षा के लिये कुरबान हो जायेगा। इस अवसर पर मैं गुरु गोविन्द सिंह जी के दो नन्हें पुत्रों के वचन याद दिलाना चाहती हूं, जबकि वे जिन्दा दीवार में चुने जा रहे थे।

"मुगल बादशाह बड़े ही भोले,
जो इतना भी समझ न सकदे,
सिंह नहीं सब्जीवल तक दे,
सुरे नहीं मौत ते डर दे,
सिक्ख नहीं भोगां ते मरदे,
जिस गुरु दे असी दुलारे,
मन्स छड्डे ओस सुख सारे।"

इसका मतलब यह हुआ कि श्री गुरु गोविन्दसिंह के दोनों पुत्र, जब वे दीवार में चुने जा रहे थे, उन्होंने उस समय सरहिन्द के नबाब से कहा कि मुगल बादशाह बड़े भोले भाले हैं, वे यह भी नहीं जानते कि क्या कभी शेर भी सब्जी की तरफ देखता है, वीर पुरुष भी कभी मौत से डरते हैं। सच्चे सिक्ख भोग विलास में पड़ कर नहीं मरते। जिस गुरु की हम सन्तान हैं, वह सभी सुखों को तिलांजलि दे चुके हैं।

आज हम सबसे जिनको बापू की औलाद होने का गौरव है यह कायरता नहीं हो सकती और कोई हमको रोटी कपड़े के लालच में नहीं बहका सकता कि चीन आ जायगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। वह आवेगा कैसे ? एक-एक व्यक्ति में यह विश्वास होना चाहिये कि जब तक हम हैं तब तक वह आयेगा कैसे। जब हम नहीं होंगे तब परमात्मा देखेगा। सिर्फ एक प्रार्थना मैं करना चाहती हूं कि हमें शान्ति और धैर्य से काम लेना चाहिये और ऐसी चीजें हमें न कहनी चाहिये और न करनी चाहिये जिससे हमें हानि पहुंचे, हमारे देश को हानि पहुंचे। अगर कोई ऐसी बात होती है जिससे मुल्क की शान्ति में बाधा पहुंचती है उसे हमें नहीं करना चाहिये। हमें शान्ति का, प्रेम का संसार बनाना है लेकिन हमें कायरों का समाज नहीं बनाना है। वास्तविक रूप से सच्चरित्र लोगों का संसार बनाना है जिसको शान्ति और प्रेम का पाठ हम पढ़ावें और जो सत्य और अहिंसा के चिराग को अपने हाथों में लिये हुए विश्व को जगाता फिरे। अभी चन्द वर्ष ही हुये हैं, उसी चिराग के सहारे हमने यहां पर ब्रिटिश को जीता था और उसी हथियार के बल पर हम आगे बढ़ेंगे।

मैं अपनी सरकार से भी एक नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि सब जिले में, गांव-गांव में, शान्ति सेना खोलें और शान्ति की तरफ सभी अग्रसर हों, ऐसे लोगों की एक सेना बना दीजिये। जब निहत्थे आदमी बलिदान के लिये तैयार होते हैं तब किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह उनको नीचा दिखा सके। वैसे भी लोग मरते हैं तो लोग मरेंगे, लेकिन जब निहत्थे बहादुर लोग अपना सब कुछ न्योछावर करेंगे तब बड़ी सी बड़ी फौज का धैर्य छूट जायगा। बापू जिनका हम नाम लेते हैं उनके नाम से हमको प्रेरणा लेनी चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वह मेरी विचारधारा पर कार्य करना आरम्भ करें।

इसके बाद मैं संगठन की बात कहती हूं। अकेले तो हम आप सब बहादुर हैं लेकिन जब संगठन की बात आती है तो लोग उससे दूर भागते हैं। इसलिये मातृभूमि के नाम पर हम को संगठित होना चाहिये और किसी के गौरव पर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये, चाहे वह कम्युनिस्ट भाई हों, चाहे कोई हों, इस बात में सब को गौरव होगा कि जब हमारी मां हमेशा के लिये हमारी ओर देखती है तो हम भी संगठित रूप में उसके लिये अपना परिचय दें। और जब हम इस प्रकार शान्ति सेना के रूप में संगठित होंगे तो संसार की तड़पती हुई आंखें हमारी ओर देख रही हैं और देखेंगी कि ये बापू के नुमाइन्दे, बापू की औलाद संसार की रहनुमाई कर रहे हैं और हम दिखा देंगे कि इसके बल पर अपने अन्दर के दुश्मन को भगा दिया तो

बाहर के दुश्मन को भी हम शान्ति से भगा सकते हैं। वह एटम बम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, इस एटम बम के सामने जो शान्ति का एटम बम होता है, जो बहादुरी का एटम बम होता है उसके आगे झुकने वाला होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम और आप सब मिलकर शान्ति सेना का संघटन करें, इसलिये नहीं कि देश को भयभीत करदें कि कोई बड़ी आफत आने वाली है, कोई आफत नहीं आ सकती जहां कि ४० करोड़ आदमी पक्के इरादे के रहते हों। अगर हम विश्वास से चलें, अगर हम उस विचारधारा को जीवित रखना चाहते हैं जिसने हमारी मातृभूमि को उस गुलामी से छुड़ाया जिसमें हम सदियों से जकड़े हुए थे, हम वीर बहादुरों की औलादें हैं, हम गांधी जी के शिष्य अपने गुरु को भूल जायं, ऐसा हो नहीं सकता। आज हम सब मिलकर शान्तिमय तरीके का परिचय दें, कोई उतावलेपन की जरूरत नहीं है। हम सब अपने में शान्ति सेना का संघटन करके बाकी सरकार पर छोड़ दें, जो वह लेना चाहती है वह ले और हमें आशा है कि वह ले रही है।

इस प्रस्ताव में मुझे दो शब्दों पर शंका हो रही है, वैसे मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। इसमें लिखा हुआ है। सभी राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त कर देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जायं। "कदम उठाये जायं", इन शब्दों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों को यह शक है कि अभी कदम उठाये नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी को शक हो लेकिन मुझे उन भाइयों की देशभक्ति पर कोई शक नहीं है। इसलिये मैं समझती हूं कि इसकी जगह पर लिखना चाहिये कि ऐसे कदम उठ ही रहे हैं और उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन इसको और उत्तेजित होकर किया जाय। इस तरह का अगर कोई सुझाव होता तो मैं समझती हूं कि वह ज्यादा अच्छा रहता। इसके अतिरिक्त मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि यह सदन भी इसका स्वागत करेगा।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विरोधी दलों की ओर से लाया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं किन्तु आपकी अनुमति से शुरू में कहना चाहता हूं कि मेरा ऐसा विचार है कि इस प्रस्ताव ने इस आदरणीय सदन को एक कठिन स्थिति में रख दिया है। यदि हम यह कहें कि चीनी आक्रमण का जो भय हमारे प्रदेश और देश में आज व्याप्त है उस सम्बन्ध में सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई और सरकार को जो कार्यवाही करनी चाहिये थी वह नहीं की और रक्षा की आवश्यक तैयारियां नहीं कीं उस स्थिति में जब कि हम सब युद्ध की आशंका करते थे, जबकि हम मानते हैं कि चीन ने आक्रमण किया है तब तो इस प्रकार सरकार की समालोचना नहीं होनी चाहिये। इसके विपरीत यदि हम सरकार द्वारा की गई तैयारियों का जिक्र करें, इस बात का जिक्र करें कि इस प्रकार रक्षा की व्यवस्था की जा रही है तब भी मैं समझता हूं कि युद्ध स्तर पर जो तैयारियां होती हैं उनकी गोपनीयता को नष्ट करना होगा और जनहित में नहीं होगा। यद्यपि इस प्रस्ताव का समर्थन विपक्ष और सरकारी पक्ष दोनों ओर से हुआ है किन्तु एक तीसरा पक्ष भी है कम्युनिस्ट मित्रों का जिन्हें इस प्रस्ताव ने एक दयनीय स्थिति में रख दिया है। श्री चन्द्रजीत यादव ने जो मूल प्रस्ताव में संशोधन पेश किया है वह दो भागों में विभाजित है। एक ओर वह कहते हैं कि प्रस्ताव से वह अंश निकाल दिये जायं जिनमें चीन की भर्त्सना की गई है और दूसरे अंश में कहते हैं कि यदि रक्षा के साधन सरकार अपनायेगी, कोई तैयारी करेगी तो उसमें हम सब उसके साथ होंगे। मैं समझ नहीं पाया कि उनकी नीति क्या है। यदि वे मानते हैं कि चीन आक्रान्ता है, युद्ध की अवस्था है तो उन्हें प्रस्ताव के पहले भाग को मानना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं मानते हैं तो किस चीज का समर्थन करने की वे बात कहते हैं? इसलिये उनके संशोधन के दोनों भाग अस्पष्ट और भ्रामक हैं। पहले हमारे कम्युनिस्ट भाइयों की प्रेरणा का स्थान संसार में केवल एक था और वह था मास्को। कम्युनिस्ट प्रसारवादी मनोवृत्ति के हैं लेकिन दुर्भाग्य से आज कम्युनिज्म दो भागों में विभाजित हो गया है। एक ओर तो रूस है जो अपनी मौजूदा स्थिति में संतुष्ट है। लेकिन एक दूसरा देश एशिया में है जो चीन है, रूस स्वयं भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखता है। आज के ही अखबार में माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि चीन के इस काम को महामान्य ख्रुश्चेव ने

[श्री रामकुमार वैद्य]

स्टूपिड ऐक्शन (stupid action) कहा है। हमारे कम्युनिस्ट मित्र आज तक प्रेरणा लेते थे मास्को से लेकिन आज उन्हें एक दूसरी ओर भी देखना पड़ता है जहां उन्हीं के विचार और आइडियालाजी वाले लोग हैं और जहां से उन्हें शीघ्र सहायता प्राप्त होने की आशा है, यदि उनका भारत में कम्युनिज्म स्थापित होने का स्वप्न पूरा होने लगे। जबकि चीन ने हमारे ९, १० सैनिकों को मार डाला और बहुत से क्षेत्रों पर प्रसारवादी मनोवृत्ति के कारण कब्जा किया और कम्युनिस्ट भाइयों ने यह संशोधन रखा है तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है यद्यपि यह बहुत गम्भीर विषय है और ऐसे विषय पर बजाय शेर कहने के बहुत गम्भीरता से ही विचार होना चाहिये। शेर यह है—

"लगे नजर न कहीं उनके दस्तोबाजू को,
ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं ?"

मैं नहीं जानता कि कम्युनिस्टों की दृष्टि में राष्ट्र की कल्पना क्या है, उसका स्वरूप क्या है। उसकी सीमायें हिमालय से कन्याकमारी तक हैं या मास्को से चीन तक ? लेकिन मैं उनके राष्ट्र का वही स्वरूप माने लेता हूं जो हमारे लिये है। तो फिर उन्हें इस प्रस्ताव का समर्थन करने में क्यों आपत्ति हुई और क्यों इसमें यह संशोधन रखा ? क्या कारण था कि उन्होंने इसमें एक अनुचित विवाद उत्पन्न कर दिया ?

मैं भी नहीं चाहता था कि मूलतः इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में आवे। हम एक ही कार्य कर सकते थे कि सरकार को हम यह आश्वासन देते कि हम सभी जनतांत्रिक और देशभक्त होने के नाते सरकार के साथ हैं। अधिक भावुकता भरी बातें कहने से काम नहीं चल सकता, जैसे एक मंत्री जी ने यह कहने की कृपा की कि उनके चार जिले चीन के लिये काफी हैं, उसे रोके रखने के लिये। मैं मंत्री जी की बात जरा कम समझ पाता हूं, यह मेरा दुर्भाग्य है लेकिन मुझे उनकी यह बात जरा और भी अजीब सी लगी। माननीय नारायणदत्त जी ने तो कहा था कि यदि किसी भी असावधानी से हमारे किसी क्षेत्र में आक्रामक आ जावें तो उनको लखनऊ और दिल्ली पहुंचने में १ सप्ताह से अधिक नहीं लगेगा। किन्तु मंत्री जी ने कहा कि हट जावें हमारे अन्य मित्र और हम चार जिलों के लोग ही आक्रान्ता को ७ महीने तक रोक रखेंगे। आज जबकि युद्ध की चालें और हथियार बदल गये हैं, बड़े-बड़े योद्धाओं को आज युद्ध से डर लगने लगा है, जबकि आज युद्ध संसार के अस्तित्व और विनाश, इन दो ही चीजों में से एक को चुन सकता है, तो कैसे ४ जिलों के लोग ही एक महान् राष्ट्र की एक महान् सेना को रोक लेंगे ? खैर, उनके प्रति मैं कोई आशंका प्रकट नहीं करता हूं लेकिन मैं अपनी अक्षमता और अज्ञानता की बात कहता हूं कि मैं उनकी बात ठीक से समझ नहीं पाया।

मैंने आज के भाषणों से देखा कि कुछ मित्रों में बहुत भय है। अवश्य इस देश में कुछ लोग हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीयता में एक विशेष प्रकार की आस्था है और वे एक विशेष प्रकार के शासन में विश्वास करते हैं। वे क्या-क्या कर सकते हैं, इसके संबंध में काफी विवरण राज नारायण जी ने यहां दिया। मैं उसमें अधिक नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उनकी ओर इस निगाह से देखना कि देश की रक्षा उन्हीं कुछ नौजवानों पर निर्भर करती है, मैं इसे हीनता का परिचायक समझता हूं। कृपा करके इस बात पर जोर न दीजिये कि कम्युनिस्ट पार्टी का इस मामले में क्या रुख है। स्वदेश जैसी चीज कम्युनिस्ट भाइयों के दिमाग में कभी नहीं रही, यह ठीक है। सामान्यतः मैं यह समझता हूं और बार-बार मैंने यह पाया है कि उनके दृष्टिकोण में भारत जैसी कोई चीज नहीं है। चीन ने तो हमारी थोड़ी-सी जमीन को अपने नक्शों में मिलाकर दिखाया है। मेरे खयाल से अगर इनकी बात चले तो वे सारे भारत के नक्शे पर लाल रंग भरवा दें और उसे चीन को दे दें। इस प्रस्ताव में हमने केवल यही कहा है कि चीन की एक्टिविटीज को हम नापसन्द करते हैं। लेकिन उन्होंने भर्त्सना या निन्दा को प्रशंसा में बदलना चाहा है। इस प्रकार की मनोवृत्ति जिस दल विशेष की हो उसे ज्यादा महत्व देना अनावश्यक और अप्रासंगिक होगा।

एक बात करने की आवश्यकता है। यह प्रदेश जो देश की लगभग १/५ आबादी का प्रतिनिधित्व करता है उसे केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी भावनायें रखनी चाहिये और अपने निश्चय की घोषणा करनी चाहिये कि यदि इस देश की स्वतंत्रता पर कभी कोई आंच आती है तो उत्तर प्रदेश प्रत्येक कदम पर केन्द्रीय सरकार का साथ देगा। हम देखते हैं कि जब चीन के आक्रमण की कहीं कोई बात आती है तो हमारा बच्चा-बच्चा क्रोधित हो उठता है। उसके अन्दर एक भावना है कि हम चीन को ऐसा करने से किसी भी हालत में अवश्य रोकें। यह भी बात किसी से छिपी नहीं है कि संसार की राजनीति में हमारे नेताओं ने एक विशेष प्रकार का पार्ट अदा किया है। चीन जो आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था यू० एन० ओ० से बहिष्कृत है, उसमें नहीं लिया गया है, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा उसे स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है। यह हमने विश्व की राजनीति में एक दूरदर्शिता का कदम उठाया है और उस के लिये हमें कभी भी पश्चात्ताप नहीं है। मैं उनको प्रतिक्रियावादी मानता हूं जो यह कहते हैं कि आज भी हमारी सरकार चीन को यू० एन० ओ० में सम्मिलित करने का प्रयत्न क्यों कर रही है। हमारा यह काम तो और भी प्रशंसनीय हो जाता है, इस तरह से कि जब हमारे साथ चीन की इतनी दुर्भावना है तब भी हम उनको सम्मानित राष्ट्रों की श्रेणी में बैठाना चाहते हैं। मैं अपनी सरकार के इस कार्य को गौरव की बात समझता हूं। लेकिन श्रीमन्, दो, ढाई वर्ष से सरकार का ध्यान चीन की इस प्रकार की गतिविधियों पर दिलाया जाता रहा लेकिन हमारी सरकार ने उसका कोई प्रबन्ध नहीं किया। अनेक मित्रों ने सीमा क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार की ओर से उसका सामना करने के लिये उपयुक्त कदम नहीं उठाये गये।

ठीक है, यदि कुछ मित्र चीन को निर्दोष समझते हैं, और वे भारत को प्रसारवादी मानते हैं। यदि वे ऐसा कहते हैं तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन उससे हमारे अन्दर कर्त्तव्य-निष्ठा जाग्रत होनी चाहिये और देश की सरकार के अन्दर जागरूकता आनी चाहिये।

कुछ मित्रों का कहना है कि विरोधी पार्टियों में कुछ पार्टियां इस प्रश्न को एक्सप्लाएट कर रही हैं। यद्यपि, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि यह प्रश्न किसी भी रूप में इस सदन के सामने आता, लेकिन फिर भी अगर वह आ गया है तो उसमें ऊहापोह करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे प्रदेश और देश की सरकार वही कर रही होगी जो उनको करना चाहिये। मैं यह कभी नहीं चाहता कि वहां पर हमारी जो गति-विधि है उसको प्रकट किया जाय फिर भी हमें माननीय मुख्य मंत्री से यह आशा थी कि वह हमें इस बारे में आश्वस्त करते। लेकिन जब-जब एजेन्डे में इस विषय को लाने का प्रयत्न किया गया तो उनकी तरफ से सौदेबाजी के रूप में यह कहा गया कि सरकार की तरफ से अमुक अमुक बिल जो आये हैं पहले जल्दी से उनको पास कर दिया जाय तब हमें ऐतराज नहीं होगा। इसको देख कर मुझे थोड़ा दुःख हुआ और लज्जा अनुभव हुई। जिस प्रकार से यह समस्या बंगाल और आसाम में है उसी प्रकार की समस्या से हमारा उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उन स्थानों में आने में तो चीन को देर भी लग सकती है लेकिन हम तो ज्वालामुखी के मुख पर ही बैठे हुए हैं। अतः इस प्रकार की सौदेबाजी की बात को मैं अनुचित समझता हूं और अपने भाव आप के द्वारा उन तक पहुंचा देना चाहता हूं। जो बातें गोपनीय हैं उनको मैं टच करना नहीं चाहता, लेकिन सरकार को इतना आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक भारत की स्वाधीनता का संबंध है हम प्रत्येक दशा में और प्रत्येक प्रकार से सरकार का साथ देंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। उनके विचार तूफान और उफान की तरह इस सदन के सामने आये हैं। मैं उनके विषय में केवल एक बात आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। भय खाये हुए दिमाग से किसी भी राष्ट्र की समस्या हल नहीं की जा सकती है। अगर किसी गम्भीर मसले पर आपको विचार करना है, अगर भारतवर्ष की सुरक्षा का प्रश्न इस देश के सामने उपस्थित है तो भय खाये हुए दिमाग से इसके ऊपर विचार करना महान् भूल होगी। मैं समझता

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हूं कि जो तूफान की तरह बातें किसी मुल्क के ऊपर छा जाती हैं वह तूफान की तरह नष्ट हो जाया करती हैं, वे चन्द घंटे या चन्द मिनट तक नहीं टिक पाती हैं। हमें मुल्क की असलियत से दूर होकर इस मसले पर विचार नहीं करना है।

मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि चीन के मुताल्लिक नेपोलियन ने भविष्यवाणी की थी "लेट चाइना स्लीप, एल्स दि यलो रेस विल डिवावर दि होल ग्लोब आफ दि अर्थ" (Let China sleep, else the yellow race will devour the whole globe of earth) यानी चाइना को सोने दो नहीं तो यह किसी दिन सारे संसार को हड़प कर जायगा। मैं आपको बतला दूं कि वह भविष्यवाणी आज स्पष्ट रूप से सच्ची साबित हो रही है। जापान का हमला जो चीन के ऊपर हुआ वह चीन के लिये आशीर्वाद साबित हुआ है। इसमें दो रायें नहीं हैं कि चीन का जो मूवमेंट है उसका जाल आज साउथ-ईस्ट एशिया के हर मुल्क में बिछा हुआ है। चाउ-एन-लाई दुनिया के सामने यह साबित करना चाहते हैं कि एशिया के नेता हम हैं न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे अपने को एशिया का नेता समझते भी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने वे अपनी प्रेस्टिज पर एक आघात समझते हैं। चाऊ-एन-लाई समझते हैं कि साउथ-ईस्ट एशिया के अन्दर जो अनडेवलप्ड कंट्रीज में विकास का कार्य हो उसकी नकेल हमारे हाथ में हो जिससे जिस कंट्री को चाहें विकास के कार्य में अग्रसर करा सकें। वे समझते हैं कि इसका असली हकदार पेकिंग गवर्नमेंट है न कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट।

मेरा कहना है कि ऐसा उनको नहीं समझना चाहिये। जो लोग छोटी तबियत से इस बात को कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है, खतरा बहुत बड़ा है लेकिन भय खाये हुए दिमाग से इसको हल करना चाहते हैं तो वह हल नहीं हो सकता। हमारी पालिसी आज दुनिया के साथ है। मैं समझता हूं कि कोई भी अनडेवलप्ड कंट्री लड़ाई लड़ कर बाजी मार ले जायगा, इसमें मुझे सन्देह है। "फोर्सेज आर आर्मीज मार्च मोर आन स्टोमक दैन आर्मामेंट्स" (Forces or Armies march more on stomach than armaments) फौजें लड़ाई के मैदान में मशीनगन और हथियारों की अपेक्षा पेट भरने पर ही आगे बढ़ती हैं। भूखा सिपाही लड़ाई के मैदान में हर्गिज नहीं लड़ सकता है।

मैं आपको बतला दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी ने इसीलिये लूज किया कि वहां खाने की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया। इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया को डिफेंस के साथ-साथ डेवलपमेंट के सम्बन्ध में भी सोचना है, इसमें दो रायें नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिये था। मैं आपको बतला दूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सन् ४२ में लखनऊ-लासा रोड के लिये घोषणा की था कि यह भारतवर्ष की मोटर सड़क होगी जो लखनऊ से लासा तक जारी रहेगी। अगर इसमें किसी को शक हो तो सरकारी रेकर्ड को देख लिया जाय। लखनऊ-लासा सड़क का प्रपोजल किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लापरवाही की। हम समझते हैं कि दुनिया में सब ईमानदार हैं, हम समझते हैं कि जिनको हम अपना भाई समझते हैं वे हमारे भाई ह, लेकिन इस बात का खयाल नहीं किया गया, जैसा कि मैंने बार-बार इस सदन में पहले भी बतलाया था कि भूखा, नंगा तथा प्यास से पीड़ित रह कर कोई किसी देश की रक्षा नहीं कर सकता है। इसम क्या सन्देह है और क्या इसमें सन्देह की गुंजायश हो सकती है? यह मसले हमारे सामने हैं। हमें इन हालात में अपनी न्यूट्रेलिटी की पालिसी पर आरूढ़ रहना चाहिये। हमारी फारेन पालिसी की बड़ी हलचल है, जिस तरह से आज हम अमरीका की मदद चाहते हैं उसी तरह से वह भी कभी इंडियन ओशन तक पता न चले कब अपनी फौजें लाकर उतार सकते हैं। पालिटिक्स से खेलना कोई मजाक नहीं है, एक बार फोबिया फैलाना और मुल्क के अन्दर की हालत को न देखना कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। वह मुल्क जो अभी निर्माण के स्टेज में हो, जिस का होम फ्रन्ट कमजोर हो उसके लिये बिना सोचे समझे वार फ्रन्ट की बात अधिक करना कोई ज्यादा अक्लमन्दी की बात नहीं है। आप को उस स्थिति का अन्दाजा ही नहीं है कि जिसका सामना किसी देश को लड़ाई के समय में करना पड़ता है। जब कभी किसी मुल्क पर आक्रमण होता है तो

वहां की सरकार को लड़ाई के साधनों के अलावा तमाम सिविल आबादी का भी ठीक से इन्तजाम करना पड़ता है और तमाम लोगों को बसाने आदि की व्यवस्था सोचनी पड़ती है, जो वार एफेक्टेड क्षेत्र होता है वहां के लोगों के लिये यह सब प्रबन्ध करना होगा और सोचना होगा। अगर न सोचा हो तो अभी समय है, वह सब हमें सोच लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यह कोई मैदान की मामूली लड़ाई नहीं है। यह तो १२ हजार से २५ हजार फुट की ऊंचाई की लड़ाई है। जो लोग कश्मीर फ्रन्ट पर लड़े हैं वे जानते हैं कि बर्फ में क्या दिक्कतें सर्दी की वजह से होती हैं। जिनके रिश्तेदार और भाई रहे हैं वहां वह जानते हैं कि किस तरह से वहां पर बर्फ से लोगों की हाथ पैर की उंगलियां गल कर गिर जाती हैं। चीन की फौजों के पास तमाम साधन हैं, उनके पास ऐसे खालों के कपड़े हैं जिनके अन्दर बाल रहते हैं और जो वहां की बर्फ से बचा सकते हैं और जिन्दा अपने को रख सकते हैं। वहां पर अगर लड़ाई होती है तो उन बर्फीली चोटियों पर अपनी फौज की रक्षा के लिये हमें तमाम इन्तजाम करना होगा। जो भाई कहते हैं कि हमने आज लड़ाई की बात यहां की और कल लड़ाई हो गई और हिन्दुस्तान जीत जायगा, उनका यह स्वप्न है, यह वस्तुस्थिति से आंख बन्द करना होगा। हमें लड़ाई करने से पहले अपने ३६ करोड़ आदमियों के बारे में सोचना होगा, केवल सदन में भाषण दे देने से लड़ाई नहीं जीती जा सकती मुझे इसमें सन्देह है, केवल सन्देह नहीं यह धोखा है। हमने आज तक कभी अपने मुल्क में लड़ाई के मन्जर को नहीं देखा है, करोड़ों आदमियों को हताहत होते हमने यहां नहीं देखा है, लड़ाई के मैदान की खूंरेजी हमने नहीं देखी है। आज पंडित जवाहर-लाल नेहरू जो न्यूटरेलिटी की बात करते हैं उनके दिमाग के सामने आज के हिन्दुस्तान की जीती-जागती तस्वीर है। मैं कहता हूं कि अगर लड़ाई हुई तो देश की क्या दशा होगी, हम कहां पर खड़े हैं यह हमें मालूम होना चाहिये। यहां पर यह कहना कि हम ४ जिले ही सारे चीन के आक्रमण को झेल लेंगे, मैं कहता हूं कि यह दिमाग से खारिज बात है। आज जब कि हमारे सामने एक गम्भीर मसला है और एक ऐसा समय है तो ऐसी बात न होनी चाहिये। मुल्क के जिम्मेदार लोगों को कुछ जिम्मेदारी से बात करनी चाहिये, क्योंकि इसी से राष्ट्र की परिस्थिति का ठीक से अन्दाजा होता है।

"Breathes there the man with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own my country land".

अब वे व्यक्ति जो देश के इस कठिन मसले पर सन्देह से बात करते हैं और भारत के विरोधियों को मदद करने वाले हैं, ऐसे अधम व्यक्तियों को गोली से उड़ा देना चाहिये, ऐसे पापियों के जिन्दा रहने के लिये देश में कोई स्थान नहीं है, उनको तो मौत के बाद फूंकने के लिये भी इस देश की भूमि पर स्थल नहीं देना चाहिये। इसलिये मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि चाहे वे किसी भी पार्टी के आदमी हों, सरकार के पास सब साधन हैं—दे शुड बी थ्राट टु दि बुक्स। उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमे चलाये जाते? सरकार को अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिये। यही नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर मैं यह कहना चाहता हूं कि लड़ाई की बात बहुत बड़े पैमाने पर कही जाती है, लेकिन इससे राष्ट्रों का हित नहीं हुआ करता है। अगर लड़ाई लड़नी है और लड़ाई जीतनी है तो मुल्क के प्रोडक्शन को बिना बढ़ाये आप यह दावा नहीं कर सकते। अगर कोई यह दावा करता है और इस प्रकार का विश्वास रखता है तो मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह शेखचिल्लियों के किस्से पढ़ते हैं, राजनीति नहीं, वे स्वप्न की दुनिया में बैठे हैं।

यह तो कहना बड़ा आसान है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरे भाई सब मुल्क के लिये कुरबान हो जाएंगे। लेकिन आपके पास कौन से ऐसे आरमामेन्टस् हैं जिनसे आप दुनिया में इस चीज को दिखा सकते हैं कि लड़ाई क्या होती है? क्या आप किसी कन्दरा में तपस्या करके अपने मुल्क को ताकतवर बना सकते हैं? क्या कवियों की कविता की उड़ान की तरह से मुल्क को लड़ाई में ढकेलकर उसको नेस्तोनाबूद करना अक्लमन्दी है? इसलिये निहायत अदब के साथ में माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

लोगों को बहुत लम्बा-चौड़ा विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बातें फारेन कंट्रीज तक चली जाती हैं, केवल यहीं तक नहीं रहती । सेकिन्ड वर्ल्ड वार की बात है । किसी बात पर एक जापानी और अमेरिकन में वाद-विवाद हुआ तो उस जापानी ने अमेरिकन के मुंह पर थूक दिया । फौरन ही अमेरिका ने जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया । तो यह छोटी बातें नहीं हैं । जहां तक इन्टरनेशनल सिचुएशन का सवाल है, उसमें इस प्रकार के भाषण और उबाल और जोश-खरोश नहीं होने चाहियें । पहले अपनी ताकत को देखना चाहिए । हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा पूरा-पूरा विश्वास पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की न्यूटेरेलिटी की पालिसी पर है । हम देश को लड़ाई के क्षेत्र से दूर रखना चाहते हैं । लड़ाई से मुल्क तहस-नहस हो जाता है । हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क वार शैटर्ड हो । मैं कहता हूं कि समझौते से सलामती के साथ अगर हम अपने मुल्क को विकास की ओर ले जाते हैं तो इसमें क्या दोष है ? यदि आदर के साथ और हमारे स्वाभिमान की रक्षा होते हुए आपस के झगड़ों को मिटाया जा सकता है तो क्या बुरा है ? लेकिन अगर चीन हमारे उस हिस्से को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है तो हमें सोये नहीं रहना चाहिये, हमारी फौजों की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए । यह सब हमारे मुल्क के शक्तिशाली होने पर मुनहसिर करेगा । इसलिये नौजवानों को ट्रेनिंग होनी चाहिए । केवल यह कहने से कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, कोई फायदा नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस प्रस्ताव पर बोलूं, मैं नेता सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी २१ तारीख की प्रार्थना को स्वीकार करके २ दिन का समय इस चीन सम्बन्धी प्रस्ताव के लिये दिया ।

श्रीमन्, हम लोगों को, जो प्रस्तावक हैं, यह पूर्ण विश्वास था कि यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से इस सदन में पास होगा तथा राष्ट्र की रक्षा के लिये हमारे सदन के सम्मानित सदस्य एक मत के साथ इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे । हमें दुख है कि कुछ भाइयों ने अपने संशोधन भी प्रस्तुत किये । मैं उन संशोधनों के सम्बन्ध में विशेष न कह करके सिर्फ संशोधनकर्त्ता का ध्यान भारत सरकार द्वारा निकाले गये श्वेत-पत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं । यदि उनको एक बार उन्होंने पढ़ा होता तो संशोधन की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती । कुछ भाइयों में यह गलतफहमी हो गई है कि हमने यह प्रस्ताव करके चीन को आक्रान्ता घोषित किया है । मैं एक प्रस्तावक के रूप में सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की भाषा जो नरम रखी गई है, जैसा कि आक्षेप नवल किशोर जी ने किया है, हम लोगों ने ध्यान रखा है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को कहां तक अधिकार मिला हुआ है, हम लोग किस सीमा तक विचार प्रकट कर सकते हैं, भारत की रक्षा और विदेशी नीति के सम्बन्ध में हमको कहां तक अधिकार है, इन सब दृष्टियों से हमने इस प्रस्ताव को रखा है । मैं चन्द्रजीत यादव जी को सिर्फ एक छोटा सा कोटेशन जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने चाउ-एन-लाई को एक पत्र लिखा था, उसमें से पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि वह जान सकें कि चीन ने भारत को आक्रान्ता घोषित किया है—

"You have suggested in your letter that the Government of India have applied all sorts of pressure on the Chinese Government including the use of force, to make the Chinese Government to accept the Indian demand."

इसके अलावा, नीलंग पर अधिकार के बारे में जो चाउ-एन-लाई ने लिखा है कि "India has invaded and occupied Chinese territory" उससे स्पष्ट है कि आपने चीन की सरकार के ऊपर हर तरह का दबाव डाला और चीन की सीमा के अन्दर, जो कि वास्तविक तौर पर उनकी सीमा नहीं थी, अधिकार किया और हमला किया । तो मैं नहीं कह सकता कि इन शब्दों के बाद कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि चीन ने भारत को आक्रान्ता घोषित नहीं किया, जब कि भारत आक्रान्ता

नहीं है वरन् चीन है । इसके अतिरिक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस पत्र में जो उन्होंने चाऊ-एन-लाई को लिखा है कहा है कि "I had no idea that the People's Republic of China would lay claim to about 40,000 square miles of what in our view has been indisputably Indian territory for decades and in some sectors for over a century . . . . . ." इससे भी स्पष्ट है कि भारत की सीमा पर चीन ने सिर्फ हमला ही नहीं किया वरन् ४०,००० वर्ग मील का भाग अपनी टेरीटरी घोषित किया है । आज भारत की थोड़ी बहुत नहीं ४०,००० वर्ग मील भूमि पर चीन अपना अधिकार चाहता है और वह इस भारत के मुकुट हिमालय की ४० हजार वर्ग मील भूमि को अपनी भूमि बतलाता है और अधिकार करना चाहता है । १८४२ में भारत और तिब्बत में एक समझौते द्वारा जो सीमायें निर्धारित की गयी थीं उसमें तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा, चीन के एम्परर व भारत के प्रतिनिधि मौजूद थे तथा उनके हस्ताक्षरों वाला समझौता अभी तक सरकार के पास है तथा पिछली एक शताब्दी से इन सीमाओं को किसी ने चैलेंज नहीं किया । १९५८ में चीन ने आज जिस भूमि के लिये वह दावा कर रहा है उसके लिये अपना मानचित्र प्रकाशित किया था । उसमें बाराहोती व निलंग स्थानों को ही चीन ने अपनी टेरीटरी के अंग नहीं बतलाये थे, बल्कि अफसोस है इसके विपरीत अब जो नई मांग है उस में उत्तर प्रदेश में अल्मोड़े तथा टेहरी के कुछ स्थान भी आज चीन की भूमि में घोषित किये गये हैं, घोषित ही नहीं किये गये, मैं आदरणीय जगमोहन सिंह नेगी को जो कुमायूं को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बतलाना चाहता हूं कि चीन ने वहां अपनी फौजी चेक पोस्ट्स बना रखी हैं ।

अभी उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि वहां की रक्षा का भार कुमायूं वालों पर है और वे बिना किसी दूसरे की सहायता के ही चीन का मुकाबला कर लेंगे और चीन को इस देश के अन्दर घुसने नहीं देंगे । मैं पुनः विनम्र शब्दों में उनसे कहना चाहता हूं कि नेगी जी इस विधान सभा के सदस्य ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की सरकार के एक सम्मानित और जिम्मेदार मंत्री भी हैं । क्या उन्होंने पंडित जवाहर लाल तथा चाऊ एन लाई के उस पत्र-व्यवहार को पढ़ने का प्रयत्न किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार चीन ने हमारे इस प्रदेश के बाराहोती तथा निलंग आदि स्थानों पर अधिकार किया ? मैं यह बतला दूं कि सतलज नदी तथा अलखनन्दा के बीच स्थित बाराहोती का डेढ़ वर्ग मील इलाका है जो सदियों से भारत का रहा और यकायक उसको चीन वालों ने अपना घोषित किया और सशस्त्र सैनिक उनके वहां आये । बाराहोती में अप्रैल, मई, १९५८ को चीनी सैनिकों ने आकर अनधिकार चेष्टा करके अपनी चेक पोस्ट्स कायम कर लीं । निलंग व दूसरे स्थानों में भी जैसे संगचा और लेफथाल, वहां भी चीनियों ने अपनी चेक पोस्ट्स बना ली हैं । आज टेहरी उत्तर प्रदेश का अंग है और उस टेहरी में निलंग और उसके आस-पास के स्थानों पर जिनके सम्बन्ध में सदियों से कोई भी आदमी नहीं कह सकता था कि वे कभी भी चीन के अधिकार में रहे हैं, उस निलंग जैसे स्थान को आज चीन अपनी भूमि बतला रहा है जो भारतीय बोर्डर से ४ मील दक्षिण की तरफ है । यही नहीं, अल्मोड़े जिले में संगचा और लेफथाल जो बार्डर से २–३ मील और ६ मील क्रमशः दक्षिण में हैं वहां भी चीनियों ने आ कर अपनी फौजी चैक पोस्ट्स कायम कर ली हैं । इस पर भी सरकार द्वारा इस प्रदेश की जनता को धोखे में रखने की कोशिश की गयी । जनाब नेगी जी बतलायेंगे और स्पष्ट करें कि यह कैसे हुआ । यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं । माननीय पंडित जवाहरलाल जी के पत्र-व्यवहार से कह रहा हूं और यह सब आज नहीं १९५६ से लेकर मई, १९५८ तक कायम हुईं । आज जिस प्रदेश की जिम्मेदारी नेगी जी पर है जो कि प्रदेश के मंत्रिमंडल के मंत्री कहलाने का हक रखते हैं वह कृपा कर बतलायेंगे कि इन चन्द स्थानों पर चीनियों की चेक पोस्ट्स कैसे बन गयीं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की । यह बात स्पष्ट घोषित कर रही है कि हमारे प्रदेश की यह सरकार सिर्फ उस फैक्ट को छिपाने का ही प्रयत्न करती है । आज जब कि देश की रक्षा के लिये देश का जन-जन आतुर हो रहा है, देश की सभी राजनीतिक पार्टियां देश के लिये बलिदान होने को तैयार हैं और देश की एक-एक इंच भूमि की रक्षा करने के लिये आतुर

[श्री जगन्नाथ लहरी]

हैं, उस समय प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री का यह कह देना कि इस प्रदेश की रक्षा के लिये कुमायूं के केवल चार जिले ही काफी हैं, यह बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आयी ।

बन्धुओ, मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं । आजाद होने के बाद हमारा देश गणतन्त्र राज्य घोषित हुआ । आज अगर प्रजातन्त्र की मशाल को प्रज्वलित रखने का कहीं प्रयत्न हो रहा है एशिया के अन्दर तो वह भारत देश ही है । भारत के साथ-साथ एशिया के अन्य देशों में भी प्रजातन्त्र की आग प्रज्वलित हुई थी, जैसे इंडोनेशिया, बरमा, पाकिस्तान आदि में । मगर हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज इन देशों में प्रजातन्त्र के स्थान पर सैनिक तानाशाही ने स्थान ले लिया है और गणतन्त्र वहां पर दफना दिया गया । आज गणतन्त्र को जिन्दा रखने के भारत के प्रयास की ओर सारे विश्व की आंखें लगी हुई हैं । भारत में जनतन्त्र को अगर कायम रखना है तो हमें भारत के जन-जन की आकांक्षाओं का सम्मान करना भी आवश्यकीय है । आप किसी भी शहर में चले जाइये भारत के, उत्तर से दक्षिण तक, हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक, चाहे अपढ़ हों चाहे विद्वान हों, सरकारी कर्मचारी हो या कोई साधारण नागरिक हो, आज हर एक की जबान पर चीनी आक्रमण से भारत की रक्षा करने का प्रश्न है तथा हर प्रकार का बलिदान करने को तैयार हैं । आज यह भारत के जन-जन का प्रश्न बन गया है । यह नितान्त आवश्यक है कि हम भारत के जन-जन में यह विश्वास पैदा करें कि भारत में वह शक्ति है कि चीन जैसे विशाल और शक्तिशाली देश का वह मुकाबला कर सकता है और वह मुकाबला तब कर सकता है जब हम उसके लिये एक होकर कुछ प्रयत्न करें । इसलिये हमने राष्ट्रीय एकता की भाषा रखी है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस देश के लिये हमारे राष्ट्र नायक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिस समय चीन को विश्व में कोई पूछने वाला नहीं था उस समय यू० एन० ओ० में हमने उसकी आवाज को बुलन्द किया, लेकिन उसी समय से, सन् ५४ से ही जहां हम चीन को एक मान्यता का स्थान दिलाने की कोशिश कर रहे थे और जिसकी वजह से बड़े बड़े राष्ट्र हमारे विरोधी हो गये हैं, वहां उसके विपरीत तभी से हमारी भूमि पर चीन का आक्रमण जारी है । यह बात हमारे प्रधान मंत्री के पत्र-व्यवहार से साफ जाहिर है । तब भी देश की जनता को फैक्टस् ऐंड फीगर्स नहीं दिये गये जिससे सही-सही स्थिति का पता चल सकता, लेकिन आज विवश हो कर राष्ट्र नायक को यह मन्जूर करना पड़ा है । सब भेदों को भुला कर हम लोग राष्ट्र रक्षा का प्रण लें, इसी में भारत की भलाई है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, जो सीमा विवाद की यहां चर्चा चल रही है मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं । वहां पर जो स्थिति है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं । जहां तक देश की सुरक्षा का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक भारतवासी का कर्त्तव्य है कि वह अपने देश की रक्षा के लिये कुरबान हो । लेकिन सीमावर्ती लोगों का आज आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने का सवाल है । वह एक समस्या बन गया है और सरकारी तौर पर जो प्रयत्न किये जाते हैं उनमें अधिकतर वह कामयाब नहीं होती है । खास तौर से उद्योग-धंधा विभाग वहां अच्छी तरह से काम नहीं कर सका है । वहां पर गरीबी बहुत है और लोग उससे परेशान हैं । पहाड़ी इलाके में यातायात के जो साधन होने चाहिये वे नहीं हो पाये हैं । मुझे बड़ा दुःख है कि वहां पर ऐसे अधिकारी भेजे जाते हैं जो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं । १९५७ में पी० डब्लू० डी० विभाग द्वारा जो सड़क बनानी शुरू की गई थी वह वैसी ही पड़ी हुई है और कोई काम नहीं किया जा रहा है । जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, यातायात की नितान्त आवश्यकता है । खास तौर से नीलंग से टेहरी जानेवाली सड़क है, वहां पर ऐसी चट्टानें हैं जिनको तैयार नहीं किया जा रहा है । ऐसे अधिकारी वहां भेजे जाते हैं जो दंडित होते हैं । इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलाके में अच्छे अधिकारी भेजे जायं जो गवर्नमेंट की गुड बुक्स में हों ताकि वे सीमावासियों की सेवा कर सकें ।

खास तौर से सीमान्त इलाके के नजदीक जो गांव हैं वहां पर बाढ़ आई थी और गांव के गांव तबाह हो गये थे । सहायता के लिये जो सरकारी तकावी दी गई उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं हुआ है । जरूरत इस बात की थी कि अनुदान मिलना चाहिये था । अन्य विभागों से भी लोग परेशान हैं । ऊपर से चीन के आने का खतरा बराबर बना रहता है । घुंघुन नाले तक चीनी लोग क्लेम करते हैं । इससे लोग परेशान हैं और सरकार का इंफारमेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है । उसे जरूरत नहीं है कि वह वहां के लोगों को सही हालत बताकर उनकी परेशानी को दूर करे और उनको धैर्य दिलाये ।

दूसरे, अधिकारी वर्ग में भी असंतोष है, क्योंकि एक ही विभाग के कुछ लोगों को सीमावर्ती अलाउन्स मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है । इस इलाके में शिक्षा की ओर भी सरकार का ध्यान नहीं है । जिस तरह से दूसरे इलाकों में हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोले गये हैं वैसे ही यहां पर भी जरूरत है । घटकारी में हाई स्कूल की तथा उत्तर काशी में कालेज के खुलने की जरूरत है । इंडस्ट्री विभाग को काटेज इंडस्ट्री को वहां पर फैलाना चाहिये । काटेज इंडस्ट्री की वहां काफी गुंजायश है और जल्दी से जल्दी इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये, और जल्द से जल्द उस तरफ ध्यान दिया जाय जिससे वहां पर आम लोगों को अपनी रोजी-रोटी का साधन मिल सके । वहां जंगलात, जिसके बारे में बड़ा भारी असंतोष था, इस बारे में एक जांच समिति नियुक्त हुई थी । उसने चारों जिलों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी लेकिन उसके बाद भी जंगलात विभाग का ऐटीट्यूड बहुत परेशान करने वाला है । सीमान्त प्रदेश के लोगों को, जब कि पास ही जंगल है वहां से लकड़ी नहीं मिलती ।

जहां तक सुरक्षा का सवाल है, जब तक आन्तरिक सुरक्षा और संतोष नहीं होगा तब तक, जैसा कि सदन में कहा गया, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि लोगों को भड़का सकते हैं । इस लिये बहुत आवश्यक है कि वहां पर सरकार योग्य अधिकारियों को भजे । वहां पर ऐसे अधिकारियों को भेज दिया जाता है जिनको दंड देना होता है । इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पहले भी सुझाव दिया था वहां के लिये जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, एक अलग से प्लानिंग होनी चाहिये । अगर ऐसा होता तो यह समस्या आज हमारे सामने नहीं होती । जहां तक सुरक्षा का सवाल है वहां के लोग बहुत आतंकित हैं । वहां पर खेती की रक्षा के लिये भी बन्दूक के लाइसेंस नहीं मिलते । मेरा सुझाव है कि वहां पर ऐसे लोग जो चरित्रवान हैं, उनको आम तौर से बन्दूक के लाइसेंस दिये जायं जिससे वे अपनी सुरक्षा कर सकें । बन्दूक पाने का जो सिस्टम है उसमें पटवारी से लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक सैकड़ों रुपये लाइसेंस लेने के लिये खर्च करने पड़ जाते हैं । इस लिये सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसों की आम सुविधा दी जाय जिससे कि वे खेती और आत्मरक्षा कर सकें ।

इसी प्रकार हमारे यहां रेल का यातायात भी नहीं है । मैं चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार पर जोर डाले कि सुरक्षा के लिये जहां आसानी से रेलवे लाइन जा सकती है, वहां पर रेल का प्रबन्ध किया जाय ।

वहां जो औषधालय हैं उनमें सहायक वैद्य रखे जाते हैं । इस प्रकार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है । जिस प्रकार और जगहों पर योग्य वैद्य रहते हैं उसी प्रकार वहां भी वैद्य रहने चाहिये । यह नहीं कि वहां पर एक औषधालय खोलकर और एक सहायक वैद्य को, अनट्रेंड वैद्य को रखकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—अब बाकी लिख कर भेज दीजियेगा ।

श्री रामचन्द्र उनियाल—इसी प्रकार वहां पर यातायात के साधनों में, जहां तक कि पैदल मार्ग का सम्बन्ध है, उसका भी वहां पर बिल्कुल अभाव है । हमारा जिला सन् ४९ के पहले एक राज्य था और वहां पर सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी । लेकिन आज जब कि हमको

[श्री रामचन्द्र उनियाल]

यहां मर्ज हुए इतने साल हो चुके हैं तब भी वहां पर सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल आ जा सकें। मोटर मार्ग तो बड़ी समस्या है ही। मेरा सुझाव है कि इन तमाम विकास की बातों की तरफ और खास कर यातायात के साधनों की तरफ और उनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इसी तरह से कुछ वहां पर पी० ए० सी० में भर्ती के लिए भी लोग आये थे। इस बारे में भी उन लोगों में बड़ा असन्तोष है। वह सब बड़े स्वस्थ होने पर भी भर्ती नहीं किये गए। मेरा सुझाव है कि जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो उसमें उनको प्रिफरेंस देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों की हालत इतनी खराब है, सामाजिक स्तर इतना गिरा हुआ है कि इस जमाने में भी जब कभी कोई चुनाव होता है तो देवता की पूजा की जाती है। इसलिए सरकार को वहां पर शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए जरूर प्रयत्न करेगी। जय हिन्द!

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खड़े होते ही मेरे दोस्तों ने तालियां बजायीं। मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मेरा कटु व्याख्यान सुनने के बाद भी अगर तालियां बजायें तो और मुझे खुशी होगी। चन्द मिनटों के अन्दर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर इस विषय पर रोशनी डालने की जरूरत नहीं कि हम बेकसूर हैं, हमने शराफत की, चीन ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारी चीज छीन ली। यहां पर सब पढ़े-लिखे लोग हैं, अखबार पढ़ते हैं, जानते हैं। प्रश्न यह है कि हम इनका मुकाबिला कैसे करें? संक्षेप में हमको इस पर रोशनी डालनी चाहिए कि हमको सफलता कैसे मिले? कहां कमजोरी है, कैसे इसको ठीक किया जाय? इसलिए इस पर मैं रोशनी नहीं डालूंगा कि हम बहुत ही बेकसूर हैं। फिर भी इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक कि शराफत का ताल्लुक है, भलमन्साहत की बात है, सुलह करने की बात है, यह तो हुजूरवाला, हमारे हिन्दुस्तान की परम्परा है। उस परम्परा का पालन होना चाहिए। महाराज रामचन्द्र जी ने सुलह की कोशिश की। भगवान् कृष्णचन्द खुद सुलह करने के लिए दूत बनकर चले गए। सुलह करने की कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, शराफत है, लेकिन एक हद से ज्यादा जाकर सुलह करना तो बुजदिली है। दुश्मन उससे फायदा उठाता है, जानता है यह कमजोर है इसलिए सुलह की बात कर रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सुलह की कोशिश हो चुकी। एक हद तक कोशिश हुई और अब सुलह की कोशिश करने का नतीजा यह होगा कि यह समझा जायगा कि हम कमजोर हैं, डरते हैं, तब सुलह की बात करते हैं।

एक बात और। बहुत नाजुक मौका है, बहुत नाजुक मौका है, सभी लोग कहा करते हैं। मैं सहमत इससे नहीं हूं। मैं समझता हूं, लड़ाई नहीं होगी। क्या उनकी हिम्मत हिन्दुस्तान से लड़ने की है? फारमोसा को तो वह ले नहीं सके। सारी ताकत और फौज उनकी खड़ी रह गई लेकिन फारमोसा पर कब्जा नहीं हो सका। तो क्या वह हिन्दुस्तान से लड़ लेंगे? वह जानते हैं कि हिन्दुस्तान हक़ पर है और हिन्दुस्तान के पास ताकत भी है, फौज भी है और ईमान्दारी भी है और दुनिया की हमदर्दी भी हमारे साथ है, लेकिन मैं मुगालते में नहीं पड़ता। दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिये। छोटे दुश्मन से भी खबरदार रहना चाहिये। इसलिये हमारा फर्ज है कि हम होशियार रहें। जरूरत इस बात की है कि कमजोर को बहादुर बनाने वाली चीज, गीता, को हम देखें। उसका वह श्लोक जो भगवान् कृष्ण ने अर्जुन के लिये कहा था, उसको स्मरण करें। अर्जुन ने कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा और भाई, मित्र, चाचा, दादा, मामा को मार कर मुझे राज्य नहीं चाहिये। उस फिकरे को छपवाकर फौज और बच्चों में बंटवा देना चाहिये। उस श्लोक में भगवान् ने कहा था कि :

"हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।
तस्मात् दुतिष्ठ कौन्तेय, युद्धोस्य कृत निश्चयः॥"

तुम अगर हार गये तो तुमको स्वर्ग मिलेगा और विजयी हुये तो इस पृथ्वी पर राज्य करोगे। लिहाजा, निश्चय करके लड़ना चाहिये। इस प्रकार से जो बतलाया जायगा तो वह हमको

लड़ने के लिये तैयार करेगा। बाइबिल, गुरु ग्रन्थ साहब, कुरान के जितने भी इस तरह के पद आये हों जो मनुष्य को लड़ने के लिये तैयार करते हों उनको छपवा कर बंटवा देना चाहिये ताकि हमारे आदमी उनको पढ़ें और उससे शिक्षा लेकर उत्साहित हों। बच्चों के लिये स्कूलों में बंटवाना चाहिये। उनके अन्दर भी उत्साह बढ़ाना चाहिये। इससे उनमें और जोश पैदा होगा। आज बच्चों के अन्दर बहुत जोश है। वे लड़के लड़ने के लिये तैयार हैं। उन्होंने हमेशा देश की मदद की है। यह समय उनकी शिकायत करने का नहीं है। (व्यवधान) "अमिय सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच" जो बुरा है वह जितना ही बुरा हो वही अच्छा और जो अच्छा हो वह जितना ही अच्छा काम करे उतना ही अच्छा। हमें उनसे नहीं बल्कि अपने दोस्तों से शिकायत है। हमारे दोस्त कहां से कहां जा रहे हैं? आज कांग्रेस बेंचेज से मैंने एक स्पीच सुनी। एक भाई ने उधर से कहा कि साहब ४२ हजार वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान के पास है, उसके लिये तो लोगों ने शोर नहीं किया, लेकिन चीन के पास केवल ४० हजार वर्ग मील का इलाका है, चीन ने ले लिया तो इसके लिये इतना शोर मचाया जा रहा है!

हुजूरवाला, इस वक्त बच्चों में देश के लिये जोश ज्यादा है। हुकूमत अगर न्याय के साथ नहीं काम करेगी तो जोश कम हो जायगा। मातभूमि की इज्जत बढ़ाने के लिये जरूरी है कि इस तरह से सरकार मजबूती से काम ले। अगर हुकूमत अच्छी नहीं है तो घबराकर अनेक जयचन्द बन सकते हैं। लड़कों के साथ इस वक्त इन्साफ नहीं हो रहा है। मैं हमेशा उन गलत आन्दोलनों की मुखालफत करता था लेकिन हमारे ये दोस्त उनकी तारीफ किया करते थे। इस वक्त लखनऊ के लड़कों ने ठीक काम किया है। लड़कों ने हड़ताल के ठीक मौके पर की है और इससे उन्होंने विश्वविद्यालय का मस्तक ऊंचा किया है। बड़े ऊंचे करेक्टर को उन्होंने दिखाया है। इलाहाबाद में अगर लड़कों के खिलाफ ऐक्शन सरकार ले तो ठीक है लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के लड़कों ने बहुत बहादुरी से काम लिया है। उनको शाबाशी देनी चाहिये। उनकी पीठ ठोंकनी चाहिये और तारीफ करनी चाहिये। अगर कोई गलत काम हो तो उसको गलत बतलाया जाय। अगर हम सही काम को सही बतलायेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी। उससे हमारी शक्ति बढ़ेगी।

अब हुजूरवाला, जरा जड़ को भी देखना चाहिये कि जड़ में कहां खराबी है। मेरी गुजारिश यह है कि आपको काम ठीक करना होगा और जड़ की खराबी को पहले दूर करना होगा। हमारे प्रधान मंत्री बहुत अच्छे हैं। मुझे फख्र हासिल है उनके साथ रहने का। लखनऊ जेल में जब मैं सन् २१ में गया था तो एक छोटे से सिपाही के नाते मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला था। उनके साथ पी० सी० सी० और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी काम किया है। हमारे झोपड़े पर भी वह तशरीफ ले गये थे। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। भगवान् ने उन्हें खूबियां दी हैं और बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। जहां तक देशभक्ति की बात है, उसकी सेवा में कहीं रुकते नहीं, कहीं दम नहीं लेते, बड़ा त्याग किया है। जहां तक उनकी मेहनत का ताल्लुक है, बड़े मेहनती हैं। (व्यवधान) किन्तु उसके बाद लेकिन लग जायगा और वह 'लेकिन' यह है कि उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। साधारण जगह पर भी गुस्सा आ जाता है और भरी सभा में भी। पार्लियामेंट में अपने मिनिस्टरों को बेइज्जत कर देते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं, जहां बहुत सी खूबियां हैं उनके साथ यह एक कमजोरी भी है। यह बात साधारण समय में तो चल सकती है, लेकिन इस नाजुक समय में गुस्सा बहुत खतरनाक है। यह सही है कि गलती करके वे तत्काल क्षमा मांगते हैं किन्तु माफी एक दिन, दो दिन, चार दिन तो मिल सकती है, रोज नहीं। अगर आप रोज गलती करते हैं और रोज माफी मांगते हैं तो आप उस कुर्सी के काबिल नहीं हैं, आपको स्वयं हट जाना चाहिये और दूसरे किसी योग्य को बैठाना चाहिये। अहिंसा परमो धर्मः जो हमको सिखाया गया था वह उस समय के लिये ठीक था जब कि हमारे पास हथियार नहीं थे किन्तु वह हर समय लागू नहीं होता। आज के जमाने में अहिंसा परमो धर्मः का प्रयोग नुकसान पहुंचायेगा। उदाहरणार्थ जब हमारी फौजें काश्मीर में तेजी से बढ़ रही थीं और लुटेरे भाग रहे थे तो...

श्री उपाध्यक्ष—काश्मीर का विषय यहां कहां से आ गया? (हंसी)

श्री सीताराम शुक्ल---आपने कह दिया इसलिए लोगों ने हंस दिया, लेकिन इसका इससे सम्बन्ध है। काश्मीर में जब हमारी फौजें बढ़ रही थीं उस समय पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम नहीं लड़ रहे हैं, यह तो कबायली लुटेरे हैं फिर भी हमार पंडित जी यू० यन० ओ० में फरियाद करने चले गये। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कैसे बना, बनाने वाला कौन है। दूसरी बात आपने काश्मीर के राजा को गद्दी से उतार दिया और वहां प्रधान मंत्री, शेख अब्दुल्ला, को बनाया जिसने बगावत की। आपको अपने दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है। आप माओत्से तुंग को पहचान नहीं सके। इधर हिन्दी-चीनी भाई-भाई कहते रहे और उधर वे हमारी जमीन में सड़क बनाते रहे। कहा जाता है कि हमने जब श्री दलाई लामा को शरण दी तब उन्होंने सड़क बनाई...

श्री उपाध्यक्ष---आप प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू सीक करें और उन्हें यह सब बता दें तो ठीक हो। यहां आप विषय पर ही बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल---आपका हुक्म होगा तो खुशी से यह बात मानूंगा और जरूर जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा, किन्तु जो यह कहना है कि शरण देने के बाद वह सड़कें बनीं वह ठीक नहीं है। आपके शरण देने के पहले ही हुजूरवाला, वह सड़कें बनवा रहा था और अटैक करने की तैयारी कर रहा था। आप पहचान नहीं सकते हैं दोस्त और दुश्मन को। तीन मर्तबा धोखा हो गया है।

"फिर नहीं जननी जन्मिहै फिर नहीं हाथ कमान,
सात बार तू चूकि गै अब न चूकु चौहान।।"

इसलिये मेरी गुजारिश है कि पंडित जी को अब प्रधान मंत्री नहीं रहना चाहिये। जब पिछली लड़ाई छिड़ी और हार पर हार हुई तो इंग्लैन्ड की पार्लियामेन्ट में प्रस्ताव आया और गवर्नमेन्ट के बहुत से मेम्बरों ने भी निन्दा का उसके साथ वोट दिया और चेम्बरलैन को हटा कर चर्चिल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एमरी साहब ने भी निन्दा के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसलिये यहां भी उस व्यक्ति को प्रधान मंत्री के पद पर बैठाया जाय जो कि "प्रीति साधुजने नयो नृप जने शाठ्यं सदा दुर्जने" जानता हो जो बदमाशों के साथ बदमाशी और अच्छे आदमी के साथ अच्छाई करने में निपुण हो, ऐसे आदमी को ही प्रधान मंत्री होना चाहिये। पंडित जी को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिया जाय, वे उद्घाटन किया करें, किन्तु प्रधान मंत्री की कुर्सी पर तो ऐसे आदमी को ही रहना चाहिये जो कि इन कम्यनिस्टों के साथ सहानुभूति न रखता हो। इन शब्दों के साथ में समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस मेरी बात को सपोर्ट करेगा।

***श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है उसकी भावनाओं से मैं हृदय से सहमत हूं। यद्यपि मेरा विचार है कि यह प्रस्ताव जिन शब्दों में लिखा गया है वह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, उचित रूप में नहीं है और जिन शब्दों में यह प्रस्ताव रखा जाना चाहिये था उन शब्दों में नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय शब्द का कोई महत्व नहीं है बल्कि उससे एक भ्रान्ति पैदा होती है। मेरे खयाल से उसमें यह शब्द "राष्ट्रीय सीमा" नहीं होना चाहिये था बल्कि "चीन की सीमा" शब्द होना चाहिये था। दूसरे, आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारतवर्ष किसी तरह भी इस परिस्थिति में आक्रान्ता है। अगर आक्रान्ता है तो सब से पहले चीन ही है। अतः इस चीज का भी इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये था। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट होना चाहिये था कि अगर चीन की तरफ से कोई भी हमला होता है और कोई भी आवश्यकता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ती है तो उत्तर प्रदेश की जनता केन्द्रीय सरकार को विश्वास दिलाती है कि वह हर प्रकार से त्याग एवं बलिदान के लिये प्रस्तुत है और प्रस्तुत रहेगी। इसका इस प्रस्ताव में आश्वासन होना चाहिये।

खैर, यह बात निश्चित है कि आज हजारों वर्ष के बाद देश को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति मेरे खयाल से इतिहास में कभी नहीं आई। आज इस देश में चीन की तरफ से आक्रमण का खतरा पैदा हो गया है जहां कि कभी आक्रमण ही नहीं हुआ। चीन और भारतवर्ष में सदैव मित्रता रही, किन्तु अब चीन द्वारा आक्रमण का भय उत्पन्न होता जा रहा है। आज स्थिति बदल गयी है। आज विश्व की महान् शक्ति जनसंख्या है और इस दृष्टि से भारतवर्ष और चीन विश्व के दो महान् देश हैं। यह दो प्रबल देश हैं। आज उनमें अगर संघर्ष की परिस्थिति पैदा होती है तो यह इस देश के लिये ही नहीं, चीन के लिये ही नहीं, समस्त विश्व के लिये चिन्ता का विषय है। तो आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमें बड़ी गंभीरता से उनके अन्दर होकर चलना है। लोग कहते हैं कि 'चीनी-हिन्दी भाई-भाई' का नारा लगाकर हमने एक बड़ी गलती की थी। मैं इसे स्वीकार नहीं करता और विश्वास करता हूं कि वह मैत्री का नारा इस देश के लिये ही नहीं, विश्व के लिये एक महान भविष्य पैदा करने वाला है। केवल हमें उन परिस्थितियों को पैदा करना होगा जिससे चीन और हिन्द वास्तव में दोस्त होकर रहें। लेकिन पण्डित नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां भारत की एक इंच भूमि का प्रश्न होगा वहां हमारे और चीन के बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता। हम एक इंच भूमि भी चीन को नहीं लेने देंगे और उसके लिये यदि आवश्यक होगा तो हम कुरबानी के लिये भी तैयार रहेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि हमने दलाई लामा को इस देश में बुलाकर, यानी उनका स्वागत करके, गलती की तो मैं उनसे कहता हूं कि यह महज खयाल की बात है। मेरा खयाल तो यह है कि दलाई लामा के आने के बहुत पहले से चीन की योजनायें थीं और वह उन पर काम कर रहा था। दलाई लामा का और जो रिफ्यूजी तिब्बत से आये, उनके आने पर किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिये आवश्यक था कि राष्ट्रीय नियमों और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अन्दर उनका स्वागत किया जाय और भारतवर्ष जैसा स्वाभिमानी देश जिसने इस बात की प्रतिज्ञा ली है कि गरीब और निर्बल राष्ट्रों का हमेशा साथ देगा, उसने दलाई लामा के साथ जो व्यवहार किया था वह उचित ही था। परन्तु हमारी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दलाई लामा के स्वागत का अर्थ यह नहीं है कि हम चीन की राजनीति में कोई दखलन्दाजी करना चाहते हैं, हमारा उनके स्वागत के आगे और कोई लक्ष्य नहीं है। तो जिन लोगों ने यह सब बातें कहीं उनको सुनकर मुझे ठेस पहुंची।

मैं आज भी कहता हूं कि भारतवर्ष की आज भी जो यह नीति है कि हम किसी भी शक्ति से दबकर नहीं रहेंगे उससे विश्वशान्ति के लिये और उसके स्वाभिमान के लिये बल प्राप्त होगा और हमें उस पर सख्ती के साथ अवलम्बित रहना चाहिये। भारतवर्ष की एक नीति है जिसपर वह सख्ती से चलता है और चलता रहेगा कि जितने भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न होंगे उनको नेगोशियेशन्स से हल किया जाय और मैं समझता हूं कि चाहे जो भी परिस्थितियां हों, आज भी हम उस पर उतने ही दृढ़ हैं कि हम उनको नेगोशियेशन्स और शान्ति से हल करेंगे। लेकिन मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं कि एक ओर जब हमारी भूमि पर चीन की फौजें जमी हुई हैं, वह आक्रान्ता के रूप में हमारे प्रदेश पर अब भी कुछ भूमि पर कब्जा किये हैं और उनकी जो योजनायें हैं वह स्पष्ट हैं कि हमारे देश और प्रदेश की ४० हजार स्क्वायर माइल्स पर कब्जा करना चाहता है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तक वह उस भूमि से न हट जायं तब तक नेगोशिएशन का रास्ता कहां खुलता है? हमने यह कब कहा कि हम नेगोशिएशन से समस्याओं को हल नहीं करना चाहते? इसलिये जब कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शान्ति और अहिन्सा की बात लाई जाती है तब हमको शक और सन्देह होता है उनकी नीयत पर।

मैं पूछना चाहता हूं क्या आज भारतवर्ष, नेहरू और कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति और अहिंसा की शिक्षा देगी? हम दावा कर सकते हैं कि दुनिया में अहिंसा के लिये और

[श्री देवकीनन्दन विभव]

शान्ति के लिये भारतवर्ष ने और कांग्रेस ने जो कुछ किया है, जिस नीति का अवलम्बन किया है उसके लिये कोई दावा नहीं कर सकता कि उससे ज्यादा किसी ने किया है। आज हमें शान्ति और अहिंसा का पाठ पढ़ाना उसी तरह से मालूम होता है जैसा कि सन् १९४१ की मुझे एक घटना याद है। मैं आगरा सेन्ट्रल जेल में बन्द था। हमारे कम्युनिस्ट दोस्त भी उस वक्त हमारे साथ जेल में बन्द थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट साथियों के साथ हम लोग योजनायें बना रहे थे कि देश को किस तरह से आजाद करना चाहिये, लेकिन जब वह योजनायें बन रही थीं तब एक दिन मालूम हुआ, यह खबर आई कि रूस ने वार डिक्लेयर कर दी तो इन्होंने अंग्रेजों का पक्ष ग्रहण कर लिया। उसके बाद जब भी हमने इन दोस्तों से बातें कीं तो उनका रवैया बिलकुल बदला हुआ मिला।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी में एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की नहीं है जो कि मैकमोहन लाइन को ही स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे? क्या श्री डांगे ने जो आवाज उठाई थी वह कांग्रेस और सत्ता दल की नीति के विरुद्ध नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने जो यह वातावरण पैदा कर लिया है उससे कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ने में दिक्कत और कठिनाई नहीं होगी? मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे मित्र हैं, जिनमें देश भक्ति की भावना है, क्योंकि इनके संशोधन में यह भी है कि अगर परिस्थिति आयेगी तो वह साथ रहेंगे और मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन क्या कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे भी लोगों की काफी तादाद नहीं है जोकि देश की एकता और स्वाधीनता के मामले में भी अपने को बेचने को तैयार हैं? कम्युनिस्ट पार्टी इस समय हमको शान्ति का पाठ पढ़ाती है जब कि हमारी छाती पर चीन बैठा हुआ है। इस समय हमसे शान्ति और अहिंसा की बातें कहने के क्या मतलब होते हैं? यह शिक्षा चीन को क्यों नहीं दी जाती है कि नेगोशिएशन्स से बातें तय की जायं? चीन के दोस्त, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जोकि चीन में गये इसलिये कि इस मामले को, सीमा के मामले को सही तौर से सुलझाया जाय, मैं पूछना चाहता हूं कि उनके उस प्रयत्न का क्या नतीजा निकला?

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, हिन्दुस्तान पर आक्रमण होने से एक गम्भीर प्रश्न हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ है। यह प्रश्न इसलिये और भी गम्भीर हो जाता है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर हमारी सरकार का रुख बहुत ही उदासीनता का रहा है। कहने के लिये तो सरकार बार-बार कहती रहती है कि भारत की एक इंच भूमि पर भी अगर हमला हुआ तो हम उसका मुकाबला करेंगे लेकिन दूसरी तरफ यह भी तथ्य है कि हमारी दो हजार मील सीमा पर कब्जा हो चुका है लेकिन उसको बहुत दिनों तक बताया भी न गया। कभी भी सरकार की तरफ से उसका प्रतिकार या प्रतिरोध नहीं हुआ। जब हम अपनी सरकार की उदासीनता देखते हैं तो यह प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी ६५–७० करोड़ की हो और उसने हमारे ऊपर हमला किया हो तो उसके साथ लड़ाई होना आसान बात नहीं है।

हमारे देश के उत्तरी भाग की सीमा बताई जाती है मैकमोहन रेखा लेकिन जब हम उसकी पोजीशन को देखते हैं तो एक बहुत ही गम्भीर बात हो जाती है। इसमें सब से पहले तो हमें सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि हम चाहे किसी वर्ग के हों, एक साथ मिलकर जो आक्रमण हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। इसके अतिरिक्त परिस्थिति क्या है, इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिये। कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की सीमा पर हिमालय पर्वत बहुत दिनों से हमारी रक्षा करता चला आया है। लेकिन लार्ड कर्जन ने अपनी पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि हिमालय पहाड़ ने कभी भी सीमा का काम अच्छे ढंग से नहीं किया। बाहर से आक्रमण करने वाले हमेशा आते रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह उन्होंने बताया है कि हिमालय को कुछ स्थानों से पार करना इसलिये कठिन है कि बीच में ५०–६० मील का एक ग्लेशियर है। लेकिन कर्जन ने हिन्दुस्तान की रक्षा के बारे में साफ कहा है कि यह ठीक है कि हम पहाड़ की चोटी पर अधिकार रखें लेकिन उसके साथ ही साथ पड़ोस में रहने वाला मुल्क हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिये। इसीलिये अंग्रेजों की हमेशा से यही नीति रही कि तिब्बत में ऐसी किसी सरकार का अधिकार न होना चाहिये जो हिन्दुस्तान की दुश्मन हो। मैकमोहन रेखा उन्होंने यह समझ कर नहीं बनायी कि उस लाइन से हमारी रक्षा हो सकती है। उन्होंने यह ध्यान रखा था कि मैकमोहन रेखा हमारी एक रेखा होगी और उसके उत्तर में तिब्बत हमारा एक दोस्त और कमजोर मुल्क होगा जिससे कभी आक्रमण की सम्भावना नहीं है।

श्रीमन्, सरकार जब इस रेखा को सीमा रेखा मानती है तो एक गलती तो यह हो जाती है और ऐसा लगता है कि वह अंग्रेजों की एक साम्राज्यवादी रेखा है और चीन इस प्रकार का प्रचार भी करता है और हम पर इल्जाम लगाता है। इस लाइन को मानने से हमारा काम भी नहीं चल सकता। एक ऊंचा मकान हो और हमारा दुश्मन उसकी छत पर बैठ जाय और नीचे से हम कहें कि इस लाइन से हमारी सीमा है। क्या कहना है आपकी सीमा का? लद्दाख में यही तो हुआ है कि चीनी लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़े हुए थे और हमारे सैनिक नीचे मैदानों में थे। नतीजा वही हुआ जो होने वाला था। नीचे रहने वाला हमेशा हार जायगा। इसलिये सरकार से हमारी प्रार्थना है कि जो हिन्दुस्तान की सीमा रेखा है उसको मानना होगा। यह चीन ठीक कहता है कि पहाड़ियों से डिमार्केशन हो नहीं सकता। सीमा ऐसी होनी चाहिये जो प्राकृतिक हो। हमारी सीमा रेखा वह होनी चाहिये जहां से पूर्व को ब्रह्मपुत्र चली है। जब से हमने अपनी उस सीमा रेखा को त्यागा है उस दिन से ही हमने एक बड़ी भारी गलती की है। इसलिये मैंने बताया कि अगर हमारी सरकार को अपने देश की रक्षा करनी है और कर्जन की पालिसी को नहीं मानना है कि तिब्बत हमारे हाथ में रहे तो कम से कम अपनी उस स्वाभाविक सीमा तक जहां जाकर अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, हमको जाना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं वह यह है कि देश के बारे में हमारी नीति बहुत साफ नहीं रखी गयी है। लद्दाख में सड़क बन गयी, ४, ५ वर्ष पहले से बन रही थी लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि कम से कम अपने देश को बता तो दें कि चीन बगल में अपनी सड़क बना रहा है। यह भी बता देते कि हमारा वह दोस्त है और भाई चारे के रूप में सड़क बना रहा है तो भी हमको उसका कुछ ज्ञान तो रहता। लेकिन ऐसा न करके उसे छिपाया गया। मुझे यह भी शक है कि कहीं दिमाग में यह तो नहीं था कि पाकिस्तान में अमेरिका सड़क बना रहा है इसलिये उसके मुकाबले में चीन को इधर लाकर बैठा दिया जाय? मैं समझता हूं कि ऐसी नीति उनकी होनी नहीं चाहिये। लेकिन देखने से साफ मालूम होता है कि इधर अमेरिका बना रहा है तो दूसरी तरफ चीन बना रहा है। हम जानते हैं कि पंडित जी की नीति यह है कि ४, ५ वर्ष तक अमेरिका उनका भाई रहता है और ४, ५ वर्ष तक चीन उनका भाई रहता है। दोनों सड़कें इस प्रकार से बनायी गयी हैं जिससे मालूम होता है कि दोस्त और भाइयों ने ही इनको बनाया है। अगर सरकार की ऐसी ही नीति है तो मैं उससे अनुरोध करता हूं कि वह फिर सोचे कि न तो अमेरिका उसका दोस्त हो सकता है न चीन दोस्त हो सकता है। यह तो उसी प्रकार से है कि दुश्मन को अपने घर में बुला लेना है। हम यह बात सरकार से जरूर कहते हैं कि वह दो तरह की बातें न कहा करे। एक तरफ तो यह आवाज उठती है कि चीन सदियों से शान्तिप्रिय देश रहा है और दो हजार वर्षों में उसका कभी इस देश पर हमला नहीं हुआ है और दूसरी तरफ जवाब देते हुए यह तर्क दिया जाता है कि चीन का तो इतिहास ही बतलाता है कि वह हमेशा हमलावर रहा है, हमला करता रहा है। इसलिये सरकार को अपनी नीति स्पष्ट कर लेनी चाहिये कि उसकी नीति चीन और पड़ोसियों के साथ क्या होगी।

एक बात मैं और बतला दूं कि चीन का मुकाबला करना जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था, हथियारों से सम्भव नहीं है। यों तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं,

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

कुछ ज्योतिषी भी हैं, कुछ वैज्ञानिक और विद्वान भी हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि हमारा कोई दोस्त दुनिया में ऐसा है जो मौका पड़ने पर हमें एटम बम दे देगा। लेकिन चीन के पास उसके ऐसे दोस्त हैं जो जरूरत पड़ने पर उसे ऐसी चीज सप्लाई कर सकते हैं। इस लिये हमको खूब सोच समझ कर आगे चलना चाहिये। चीन स्वयं या दूसरों की सहायता से हमारे ऊपर हमला न करे इसकी तैयारी हमको करनी है, लेकिन इतना मैं आपको बतला दूं कि इसके लिये मैं हथियारों और एटम बम आदि में विश्वास नहीं करता हूं। हमें तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिये और चीन का मुकाबला करने की तैयारी पर्वतीय प्रदेशों में होनी चाहिये।

आज चीन खुलेआम पर्वतीय प्रदेशों में यह प्रचार कर रहा है कि पहाड़ी लोग तो चीनी हैं, उनकी नाक चपटी है, उनके मुंह गोल हैं, इस तरह के वे प्रमाण देते हैं। वे यहां तक प्रचार कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान के लोग उन पर सल्तनत कर रहे हैं, लेकिन असल में वे चीनी ही हैं। लेकिन इसका जवाब सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता। आप इसका यही तो जवाब दे सकते हैं कि नागाओं पर जाकर गोली चलाते हैं, और इस तरह से वे मारे जाते हैं या उनको पकड़ कर जेल भेज दिया जाता है या १०, १२ मील दूर ले जाकर उनको फेंक दिया जाता है? अगर आपका यही जवाब है तो मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। आज सांस्कृतिक प्रोग्राम का बड़ा प्रचार किया जाता है और उसका सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन आपको ो पहाड़ियों के इलाके में प्रचार के लिये भेजना चाहिये कि वे वहां जाकर पहाड़ियों को यह समझावें कि जो इस तरह का प्रचार करते हैं कि तुम चीनी हो, यह गलत है, बल्कि तुम हिन्दुस्तानी हो। मैं समझता हूं कि यह हमारी बुनियादी कमजोरी है जिसको दूर करना चाहिये। हमारे पहाड़ी इलाके उन्नत होने चाहिये और उनका जल्द से जल्द विकास होना चाहिये, क्योंकि कमजोर और निर्धन लोग ही कम्युनिज्म के जल्द शिकार होते हैं, चीनी गोलियों और बन्दूकों का तो मुकाबला हो सकता है लेकिन उस निर्धन को जिसे रोटी नहीं मिलती, जो गरीब है उसे तो कम्युनिज्म मनमोहक ही लगता है। तो हमें कम्युनिज्म का मुकाबला लड़ाई की तैयारी से नहीं करना है बल्कि अपने पहाड़ी इलाके को विकसित करके करना है ताकि वहां गरीबी, भुखमरी न रहे और वे स्वयं ही लड़ सकें और फौज की जरूरत ही न रहे। इसलिये मैं विनय करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि चीनियों का मुकाबला ठीक तरह से होना चाहिये और हमारी वैदेशिक नीति अब साफ हो जानी चाहिये। अब ढीलमढाल नीति से काम नहीं चलेगा, न उनके साथ न इनके साथ, न इन के दोस्त न उनके दुश्मन। हमें अपनी नीति साफ करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये। यदि हम स्पष्ट नीति से खड़े होंगे तो हमें बल मिलेगा। क्या अच्छा होता कि हम ने तिब्बत के लिये कहा होता कि वह स्वतंत्र रहा है और वह हमारी बगल का देश है। अगर उस को गुलामी की जंजीरों में बांधा जाता है तो यह इस बात का दावतनामा है कि आज तुम ने तिब्बत पर आक्रमण किया है, कल हमारे ऊपर करना।

अंग्रेज हमेशा अपने पड़ोसी देश को स्वतंत्र रखना चाहते थे और उन्होंने उसको स्वतंत्र रखा। उन्होंने तिब्बत के दो भाग किये थे--एक पश्चिमी तिब्बत और दूसरा पूर्वी तिब्बत। उन्होंने पूर्वी पर तो चीन का अधिकार माना था लेकिन पश्चिमी पर नहीं माना। लेकिन हमारे पंडित जी ने पूरा तिब्बत दे दिया और यह नहीं समझा कि यह एलीमेंटरी चीज मानना चाहिये थी कि तिब्बत हमेशा स्वतंत्र रहा है, कम से कम वह तिब्बत को देते वक्त देश की बाउन्डरी ही चाउ-एन-लाई से मनवा लेते। लेकिन वह सौंप दिया गया बगैर किसी चीज को साफ किये हुये। अब उस का असर हम पर पड़ रहा है। यदि हमें चीन का मुकाबला करना है तो हमें यहां के करोड़ों रहने वालों का सहयोग प्राप्त करना होगा। मैं मानता हूं कि हमारे यहां एक ऐसी पार्टी भी मौजूद है कि जो चीन के आक्रमण से एक ऐसा रुख अपनाये है कि जो कहते नहीं बनता। उस पार्टी ने इस मसले को लेकर अपने को दो भागों में बांट लिया है। देश की पूरी पार्टी कहती हैं कि हम तैयार हैं देश की और राष्ट्र की रक्षा के लिये और अगर चीन ने हमला किया तो हम अपनी जान लड़ा देंगे, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वह कहता है कि जो पहाड़ी हिस्सों में लोग बसते हैं वह

कहते हैं कि अगर चीन मुक्ति सेना आती है और वह सोशलिज्म का प्रचार करेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे, वह साम्राज्यवादी नहीं हैं उन्हें आने देना चाहिये। वह तो सोशलिज्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही आ रहे हैं। यह एक विचित्र परिस्थिति है, उसके विषय में मैं नहीं कहना चाहता कि क्या बात है। मैं देश द्रोही तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वह अभी भूल में हों कि बाहर के लोगों से सोशलिज्म का प्रचार होगा। अगर ऐसा है तो वह गलत खयाल है। हो सकता है कि वह समझते हों कि केरल में उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उस जबरदस्ती का बदला इस तरह से देश के साथ गद्दारी करके नहीं लिया जा सकता। वह हमारे भाई हैं, मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह जरा फिर सोचें, अपनी नीति को बदलें, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। पार्टी को ही दो भागों में बांट कर दो, जबान बोलना भी ठीक नहीं है।

एक बात और मुझे पहले ही कहनी चाहिये थी, वह छूट गई कि देश को तैयार करने के लिये सरकार को पहले कदम उठाना चाहिये। देश अगर आज गर्मी से भी आगे बढ़ रहा हो तो उसे पानी छोड़ कर शान्त करने की जरूरत नहीं है या यह कह कर कि लड़ाई पर जाना नहीं है, गर्म स्पीचेज से तुम शान्त हो जाओगे, कहीं लड़ाई पर जाना नहीं है यह कहना नहीं है। यह कह देना कि चीन ने जितने देश पर आक्रमण किया है उसमें कुछ पैदा नहीं होता और वह उजाड़ है, कोई उत्तर नहीं है। जब आप इस बात को मानते हैं कि एक-एक इंच जमीन की रक्षा होगी तो जिस ढंग से उसकी रक्षा हो सके उसे करनी चाहिए। अभी आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम फौज भेजें और लड़ाई लड़ें। चीन अपनी ताकत को जानता है। चीन अपने हांगकांग और फारमोसा पर, जो उसके अपने बगल के आइलैंड हैं, उन पर, कब्जा नहीं कर सकता तो वह हिन्दुस्तान पर कब्जा कर सकता है, इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इस बात को भी हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि आइजनहावर का स्वागत करके चीन को डराया जा सकता है। चीनियों का मुकाबला अगर हम कर सकते हैं तो अपनी ताकत से कर सकते हैं, देशवासियों की ताकत से कर सकते हैं और कोई दूसरी ताकत से नहीं कर सकते।

एक चीज और है। चीन का जब से मसला उठा है तब से हमारी सरकार अहिंसा और गांधी जी का नाम बहुत तेजी से ले रही है। इस संबंध में इतना तो मैं कह दूं कि भाखड़ा नांगल और पंचशील एक साथ बाढ़ में बह गये थे। पंचशील का व्यवहार अगर आप हैदराबाद के साथ नहीं कर सके, पाकिस्तान के साथ नहीं कर सके या अपने अपने घर के लोगों के साथ नहीं कर सके, कानपुर और इलाहाबाद में नहीं कर सके, अपनी स्त्री और बच्चों के साथ नहीं कर सके तो अहिंसा का बर्ताव जब एक बड़े दुश्मन के साथ करते हैं या कहते हैं तो आपकी बहादुरी पर शक होता है, आपकी हिम्मत पर शक होता है। घर पर अहिंसक बनने के बाद ही बाहर अहिंसक बनना चाहिए। जो बाहर अहिंसक बने और घर पर शेर रहे उसको हम बहुत अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि अगर उसकी शक्ति में हो तो कह दे कि जब बाहरी आक्रमण हो तो अहिंसा का लफ्ज इस्तेमाल न किया जाय। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि बाहरी आक्रमण का मुकाबला होना चाहिए। अगर आप सत्याग्रह करके मुकाबला नहीं कर सकते तो बुजदिलों की तरह से अहिंसा का नाम बदनाम न किया जाय। या तो आप जान देकर लड़िये और अगर यह नहीं करते तो हथियार उठा लेना भी अहिंसा का धर्म होगा।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के उन माननीय सदस्यों को बधाई दूंगा जिन्होंने इस प्रस्ताव को इस सदन के समक्ष पेश किया। मैं माननीय देवीप्रसाद जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मसले के संबंध में हमारी अहिंसा की नीति का प्रश्न ही नहीं उठता है। निश्चित ही जब हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं तो हम उस अहिंसा के रूप का जो श्री देवीप्रसाद जी के मन में है, बहिष्कार करते हैं। हम निश्चित रूप से युद्धस्तरीय तैयारी चाहते हैं। हमारा निश्चित मत है कि यह सदन सरकार को यह मत देता है कि हमारा इस समय का प्रत्येक कार्य युद्ध स्तर

[श्री मदनमोहन]

पर हो । हमारी तैयारियां युद्धस्तर पर हों, चाहे वे तैयारियां सामाजिक क्षेत्र में हों, उद्योग के क्षेत्र में हों, युवक समाज के गठन के लिय हों, विकास के क्षेत्र में हों, जहां भी हों, हमारी तैयारियां युद्धस्तर पर होनी चाहिये । मुझे इस बात का दुख है कि हमारे सामने माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो संशोधन रखा है उसमें मुख्य स्थान उन्होंने शान्तिमय समझौते को दिया है । श्रीमन्, शान्तिमय समझौता किन परिस्थितियों में होता है उसको हमें समझ लेना चाहिये । माननीय गोविन्दसहाय जी ने यह कहा कि इसमें भी शक है कि आक्रमण चीनियों ने किया या नहीं किया । हो सकता है कि यह केवल सीमा विवाद हो । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अगर उनका यह खयाल है कि यह सीमा विवाद है तो उनको भ्रम है । सीमा विवाद तो उसको कहा जा सकता है जैसा कि पाकिस्तान से था । उनका कहना यह था कि हमारी निर्धारित स्वीकृत विभाजन रेखा अमुक-अमुक स्थान पर है और उसी आधार पर हमें अधिकार दिया जाय कि हम उसके अन्तर्गत भूमि को लें । यहां पर उस सीमा को माना ही नहीं जाता जो परम्परा से हमारी सीमा चली आयी है, जिसको विभिन्न संधियों द्वारा पुष्ट किया जा चुका है । उसी सीमा को आज चीन मानने के लिये तैयार नहीं है । जहां पर सीमा नहीं मानी जाती, जहां पर यह कहा जाता है कि यह सीमा जो पहले निश्चित की गई थी वह तो एक विदेशी राजसत्ता ने हमारे ऊपर आरोपित की थी और अब हम उस निर्धारित सीमा को मानने के लिये तैयार नहीं है, उसका मतलब यह होता है कि केवल सीमा विवाद का प्रश्न नहीं है । अपितु यहां प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हमारे और तुम्हारे देश की सीमा फिर से निश्चित की जाये । जहां यह विवाद हो, जिस भूमि पर भारत इतने समय से काबिज है, जो भूमि उसके हिस्से की मानी गई है उस भूमि पर आज चीन राजसत्ता जमा लेना चाहता है, यह विवाद सीमा-विवाद का प्रश्न नहीं है । यह तो आक्रमण का प्रश्न उत्पन्न कर देता है और इसी वजह से प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि यह केवल सीमा विवाद नहीं है, यह उससे गहरी चीज है । समझौते का प्रश्न भी हमारे सामने बार-बार आता है । मेरा कहना है कि समझौता हो लेकिन समझौते की बात प्रायः हमारे समस्त कार्य व्यापार को, परिश्रम को शिथिल कर दिया करती है । समझौते की जब बातचीत होने लगती है तो प्रायः जो समझौते की बात करते हैं उनके कार्य शिथिल हो जाते हैं । वे मुख्य उद्देश्य पर ध्यान नहीं रख पाते हैं । जहां शिथिलता हो जाती है वहां यह असम्भव है कि हम उस युद्धस्तर पर काम करें जिस पर काम करके हमें सफलता मिल सकती है । श्रीमन्, जहां तक समझौते का प्रश्न है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि हमें इतिहास के पृष्ठ जो सबक दे गये हैं उनको ध्यान में रखना चाहिये । हमें मालूम है कि पिछले महायुद्ध के पूर्व म्यूनिख में जाकर चैम्बरलेन ने समझौते का प्रयत्न किया, हिटलर से प्रयत्न करते रहे । एक तरफ जर्मनी सक्रिय रूप से युद्ध के लिये तैयार रहा और दूसरी तरफ समझौते की बातें होती रहीं । परिणाम यह हुआ कि जिस वक्त युद्ध छिड़ा उस वक्त इंग्लैंड और फ्रांस तैयार नहीं थे और जर्मनी पूरा सन्नद्ध लड़ाई के लिये था । कहीं ऐसा न हो कि समझौते की बातचीत में हम उसी परस्थिति में आ जायं कि हमारी युद्ध के लिये तैयारियां शिथिल पड़ जायं और हम समझौते के पीछे पड़े रहें ।

श्रीमन्, समझौते के सम्बन्ध में मेरा ऐसा मत है कि हिटलर से बढ़कर हमें कम्युनिस्टों से सावधान रहना चाहिये । जरा ख्याल फरमाइये कि हमने कम्युनिस्ट देशों से सदैव मित्रता का बर्ताव किया, हंगरी के सम्बन्ध में भारत ने अपनी जबान नहीं खोली, फारमोसा पर जब गोलेबारी हुई तो हम मौन रहे और १२ वर्ष तक हम चीन के लिये राष्ट्र संघ में लड़ते रहे, समय-समय पर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते रहे । हमने चीन को एक महान देश घोषित किया और यह सब होते हुए भी हमने यह देखा कि जिस समय तिब्बत के ऊपर आक्रमण हुआ उस पर भी हमारी सरकार ने बड़े संयम से काम लिया

यद्यपि सारा देश उस वक्त उत्तेजित था। लेकिन हमने मित्रता के नाते हिमालय के उस पार झांका तक नहीं, यह देखने के लिये कि चीन क्या कर रहा है। एक तरफ हमारी मित्रता का भाव और दूसरी तरफ एक कपटी, कहना नहीं चाहिये, लेकिन बगैर कहे रहा नहीं जाता, एक आस्तीन के सांप का सा बर्ताव! हमने भाई भाई की श्रद्धा व विश्वास में कभी उनकी तरफ सन्देह से नहीं देखा लेकिन उसका जो उत्तर हमें मिला है उसको देखते हुए प्रश्न यह उठता है क्या समझौते का कोई वातावरण है ?

श्रीमन्, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस सदन में हम यह घोषित कर दें और प्रधान मंत्री व केन्द्रीय सरकार को यह सूचित कर दें कि यद्यपि हम समझौते के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हमारा समझौता बहादुरों जैसा होगा और तब होगा जब समझौते का वातावरण उत्पन्न होगा। वह वातावरण उसी समय उत्पन्न हो सकता है जब चीनी अपना आक्रमण छोड़ दें। ४२ हजार वर्ग मील भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के बाद हमसे यह कहा जाय कि तुम समझौते की वार्ता करो तो यह असंभव है, और अगर यह असंभव है तो फिर आज इस सम्बन्ध में समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम चाहते हैं कि युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां हों और जब तैयारियां कर लें तो उनसे कह दें कि हम समझौता करना चाहते हैं, लेकिन तुम उसके लिये वातावरण उत्पन्न करो और नहीं तो समरांगण में समझौता होगा। जब युद्ध की यहां बात होती है तो कितनी ही विकराल स्थितियों का चित्र हमारे सामने आ जाता है, लेकिन जहां हम युद्ध की विकरालता से भयभीत होते हैं वहां उसका एक दूसरा पहलू भी है और वह यह है कि युद्ध निवारण से जिस सुख व शान्ति को दृढ़ करने के लिये हमारे हृदय में भावना उत्पन्न होती है वह सुख और शान्ति ऐसी विरोधी प्रवृत्तियों से जो आज चीन दिखला रहा है कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। वही शान्ति और सुख कष्टमय हो जाता है, अगर हम एसी कुप्रवृत्तियों को सहन करके उसके सामने सिर झुकायें। हमें आज निश्चित ही तैयार होना पड़ेगा ताकि अगर युद्ध भी हो तो भी उस कुप्रवृत्ति का मुकाबला कर सकें।

श्रीमन्, इस सदन में बहुत सी जोश की बातें कही गईं। माननीय नारायणदत्त जी ने एक बात कही कि ७ दिन के अन्दर चीन लखनऊ आना चाहे तो आ सकता है। मुझे खेद है कि इसका उत्तर माननीय नेगी जी ने जिस इत्मीनान से दिया उससे यह भय उत्पन्न होता है कि कहीं जो इतिहास अभी हाल में हुआ है, दोबारा तो वैसा ही नहीं होगा। यह इत्मीनान कि हम चार जिले के आदमी उनसे लड़ लेंगे, हम में इतनी ताकत है कि हम उनका मुकाबला कर लेंगे, यह सब बातें उस समाचार की याद दिलाती हैं जो अभी पाकिस्तान में एक सज्जन ने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान अगर लाल किले के पास लघुशंका कर दें तो लाल किला बह जायगा। यह गलत खयाल है कि नारायणदत्त जी घबराते हैं, यह गलत खयाल है कि सदन का कोई भी व्यक्ति लड़ाई से घबराता है, यह गलत है कि हम चीन से डरते हैं, लेकिन यह अवश्य है कि तैयार होना चाहते हैं, खामोश नहीं बैठना चाहते। मुझे फिर दुःख होता है उनके मुंह से यह सुनकर कि अगर लड़ाई होगी तो अमरीका आ जायगा, वह हमारी सहायता करेगा। अमरीका की सहायता के ऊपर अपने आप को सचेत न करना कोई अक्लमन्दी नहीं है। हमें भी अपने बाहुबल पर रहना है। दुनिया में कोई आदमी निर्बल का सहायक नहीं होता है, सहायक अगर होता है तो सबल का होता है। तो अमरीका के ऊपर विश्वास करके इत्मीनान से बैठने की घड़ी यह नहीं है। यह घड़ी वह है जब कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हम यह निवेदन करें कि हम आज यह निश्चित करते हैं कि हम अपने आप को बलशाली बनायेंगे और युद्ध स्तर पर अपने सारे कार्य करेंगे ताकि हमारा सामाजिक गठन हो, हमारे समस्त विकास कार्य का संगठन उस रूप से हो। यही मुझे निवेदन करना है।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार प्रकट किया जा रहा है, उसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमारे दल के एक पूर्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

वक्ता ने यह कहा था कि अगर चीन चाहे तो ७ दिनों में लखनऊ आ सकता है । किस रेफरेंस में उन्होंने यह कहा मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी वही लोग उनकी आलोचना कर रहे थे । उन्होंने यह कहा था कि वह दर्रे और उनकी स्ट्रेटजी ऐसी है, जो युद्ध की दृष्टि से इतने महत्व के हैं कि अगर हम उन पर अपना आधिपत्य नहीं रखते हैं तो फिर चीन के लिये यह सम्भव होगा कि जल्दी से जल्दी हमारी भूमि पर कब्जा कर ले । तो किस पृष्ठभूमि में कौन सी बात कही गई इसको देखने की चेष्टा नहीं की गई और उल्टे बात का बतंगड़ बनाने की चेष्टा की गई । आज इस पुनीत अवसर पर भी जो लोग अपने को दलबंदी से ऊपर नहीं उठा सकते हैं उन्होंने इस पवित्र विचार को भी तोड़ मरोड़ कर सदन के समक्ष रखने का प्रयास किया है । मुझे इसका बड़ा दुःख है । मैं यह चाहता था कि खुले दिल से इसके ऊपर उन तमाम लोगों की ओर से, जो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे देश के ऊपर एक विपत्ति आई हुई है या हमारे देश पर विपत्ति के बादल छाये हुये हैं, वह लोग कुछ रचनात्मक सुझाव रखते जिससे सचमुच आज सदन की समाप्ति के बाद हम एक ऐसी प्रेरणा लेकर जाते या ऐसा कार्यक्रम लेकर जाते या एक ऐसी सफाई लेकर जाते जिससे वास्तव में उस जनसमाज में जिसके लिये कहा जाता है कि कम्युनिस्ट भाई उसी के बल पर यह नारा बनाने की हिमाकत कर सके कि यह फौज मुक्ति फौज है जो निजात दिलाने के लिये आ रही है, इस जन-समाज में जिसके बल पर अभी हाल में हमारी सीमा की तरफ आसाम में चुनाव में कामयाबी हासिल कर सके हैं तो उस जन-समाज में जिस प्रेरणा को लेकर हमें जाना चाहिये था उसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की गई है । इसके लिये आवश्यक था कि हम खुले दिल से वस्तुस्थिति पर विचार करते और सच्चाई के साथ जो पहले भूलें हुई हैं उनको कबूल करते ।

मान्यवर, आज से दो दिन पहले एक पार्टी के बड़े नेता से बातचीत चल रही थी । उन्होंने बड़े दर्प के साथ कहा कि कोई बात नहीं है । राजनीति में अपमान तो होता रहता है । लेकिन आप स्मरण रखिये कि अंतिम विजय हमारी ही होगी । चाहे यह संशोधन किसी रूप में रखा गया हो लेकिन क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि उन्हें अपने ढंग के ऊपर इतना भरोसा है कि वे समझते हैं कि अंत में विजय उनकी ही होगी ? एक तरफ इतना इत्मीनान है और दूसरी तरफ उलझे हुये विचार हैं । मैं फिलोसफी का विद्यार्थी रहा हूं और मैं जानता हूं कि "जिसके मन में अटक है वही अटक रहा" । इस अवसर पर आप रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं, देश की रक्षा का कार्य नहीं कर सकते हैं ।

आज जो भाई इस बात की कामना करते हैं या जो लोग सोचते हैं कि हमें इस देश को, जो बुद्ध और गांधी जी का देश है, आततायियों से बचाना है तो उन्हें यह सोचना चाहिये कि आखिर यह कम्युनिस्ट टेक्निक क्या है या जो आक्रमण हुआ है वह क्या है ? पहली बात हमें यह विचार करनी है । इसके संबंध में मैं अधिक नहीं कहूंगा और मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि जो भाई यह समझते हैं कि सदन में उनके लिये बुरे भले शब्द कह देने से काम चल जायगा वह गलतफहमी में हैं । बड़े जोरदार शब्द मैं भी कह सकता हूं लेकिन सोचना तो यह है कि उनके टेक्निक क्या हैं ? आज भी वह हिम्मत बांधे पड़े हैं कि केरल में जो चुनाव होने वाला है उसमें उनकी शानदार जीत होगी और अन्य राज्यों में बाई-इलेक्शन होते हैं उनमें भी उनकी ही जीत होगी चाहे मुख्य मंत्री जी या राजनारायण जी कुछ भी कहें । उनका जो यह घमण्ड है उसका आधार क्या है ? इसका आधार जनता में छाई हुई निराशा है । आज हमारे विश्वविद्यालय बन्द हैं, आज हमारी पुलिस इस बात के लिए इस्तेमाल की जाती है कि किसान अपने गन्ने का ठीक दाम मांगता है, आज अफसर इस बात के लिए परेशान हैं कि उनको कैसे तरक्की मिले, आज हमारी शासक पार्टी के लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि पी० ए० सी० पर कब्जा उनका होता है या दूसरों का होता है । यह वस्तुस्थिति है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । इस वस्तुस्थिति को लेकर आप सोच सकते हैं कि आप उन लोगों का मुकाबला कर सकेंगे जो लोग कि ओवरनाइट अपनी नीति बदल सकते हैं और एक

सिपाही उनका नहीं टूटता है। मुझे याद है, मैं उन दिनों जेल में था जिस समय जर्मनी से उनका समझौता हुआ युद्ध के समय। उसी दिन रात को गाना बनाया,---'बड़ी-बड़ी तोपें वह जरमन की जिनकी मार सही ना जाय।' श्रीमन्,ऐसे हैं यह लोग। हजार समझाइये लेकिन वह बदल नहीं सकते। हमारे गोविन्दसहाय जी हजार सद्भावना के विचार प्रकट करें लेकिन उनको याद रखना चाहिए, उन्होंने लेनिन के आज उस लेसन को भुला दिया जो उसने फिनलैंड के हमले के बाद दिया था---पीपुल डू नाट वांट आर्म्ड मिशनरी (people do not want armed missionary)। यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि जिस स्टेलिन की उन्होंने पूजा की उसका उसके मरने के बाद पोस्टमार्टम किया। वही लोग क्या गांधी और बुद्ध के मार्ग पर चल सकते हैं? उनका हृदय परिवर्तित होगा ? नहीं होगा। ट्राट्स्की से लेकर बेरिया तक का इतिहास क्या उनका चरित्र स्पष्ट करने के लिए काफी नहीं है ? पिछले दिनों में हमारा एक सम्मेलन बम्बई में हो रहा था। उस सम्मेलन में देश विदेश से प्रतिनिधि आये हुए थे। उस अवसर पर मैंने वहां की जनता में जो जीवन देखा, वहां दो लाख जनता बम्बई की सड़कों पर उस डांगे के लिए, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट कहा जाता है, कहा कि डांगे चीनी कम्युनिस्ट कुत्ता है। यह नारा बम्बई की सड़कों पर दो लाख जनता द्वारा लगाया जा रहा था। लेकिन यहां आया तो देखता हूं---औरों की बात क्या करूं, शासक पार्टी में बैठ कर आज उन लोगों के लिए नरम नरम बातें की जाती हैं। क्या उन छोटे-छोटे झगड़ों में हम उलझे रहेंगे, क्या इन घरौंदों में हम अपने को बन्द रखेंगे ? या इन छोटे-छोटे झगड़ों को भुला देंगे ? (व्यवधान) जैसा कि एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है, "सुनना हराम है, न सुनाना हराम है, सुनने के बाद तैश में आना हराम है"। हमारे कम्युनिस्ट भाई तैश में आ रहे हैं। मैं उनसे अर्ज कर दूं। अगर हमने डेमोक्रेसी को न माना होता तो क्या आप की यह हिम्मत होती कि आप इस पवित्र सदन में बैठ कर इस चीन के हमले पर अपने ऐसे विचार रखते ? इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो कुछ आपने कहा है, उसका जवाब सुनते जाइये।

(इस समय ४ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जो लोग यह समझते हैं कि आप केवल जयचन्द और मीरजाफर हैं वह भूल रहे हैं। आप जयचन्द और मीरजाफर नहीं हैं आप उनके खरीदे हुए गुलाम हैं। आपके अन्दर कोई अपनापन नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह जो शब्द "आप, आप" इस्तेमाल हो रहा है यह कहीं सभापति या स्पीकर के लिए न हो ?

श्री रामायणराय---क्या बताऊं.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिए। शब्द "जयचन्द" के साथ "आप" शब्द मत कहिए।

श्री रामायणराय---श्रीमन्, आप बीच में आ गए। मैं तो आपके इस हुक्म के पहले ही जैसे कनपटी-मार से लोग डरते हैं वैसे ही डर गया था। मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसी कौन सी भूल हो गई। मैं अपने टूटे-फूटे शब्दों में कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग यहां इस सदन में बैठे हैं.....

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी भी आपको इजाजत नहीं दूंगा कि किसी कम्युनिस्ट सदस्य को भी आप यहां जयचन्द कहें।

श्री रामायणराय---एक पृष्ठभूमि की बात हो रही थी, श्रीमन्। यह हमसे कहते हैं, हमें पाठ पढ़ाते हैं कि आप शान्ति का मार्ग अख्तियार कीजिए। मैं तो समझता हूं, श्रीमन्, इनके दो रूप हैं, साफ साफ दो रूप हैं। माननीय सदस्यों ने देखा होगा किन्हीं जगहों में तमाशा दिखाया जाता है जिसमें एक ही आदमी एक तरफ से देखिए तो नारी है दूसरी तरफ से देखिए

[श्री रामायणराय]

तो नर है, बिलकुल ठीक उसी तरह से इनके भी दो रूप हैं। केरल में कहते हैं कि विद्यार्थियों को अपना संगठन बनाने का कोई हक नहीं है, अध्यापकों को अपना संगठन बनाने का कोई हक नहीं है, और आज के इन उपद्रवों को ठीक ढंग से देखा जाय कि इनमें कौन लोग हैं, किनको सबसे ज्यादा बेचैनी है कि उनके उस संगठन को बदनाम करें। जिस संगठन ने कि माओ का चित्र उठाकर फेंक दिया, सुना नहीं है आपने कि लखनऊ यूनियन के हाल से वह चित्र उठाकर फेंक दिया गया, सुना नहीं है आपने कि अपने खून से हस्ताक्षर करके उन्होंने भेजा था राष्ट्रपति के पास कि अगर राष्ट्र पर संकट आयेगा तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपना बलिदान करेंगे, तो उनको कौन बदनाम करता है? तो इनके दो रूप हैं। जहां यह कब्जा कर लेते हैं वहां दूसरी शक्ल आती है.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस तरह से बहस नहीं होनी चाहिए। आम तौर से किसी पार्टी के बहुत से भिन्न कामों के बारे में यहां जिक्र नहीं होगा। अगर इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई चीज हो, इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया हो तो उसकी टीका आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी भिन्न बातों का इस तरह से मैं समझता हूं कि जिक्र नहीं होना चाहिए।

श्री रामायणराय—मान्यवर, आक्षेप किया गया था इसलिए मैंने उचित समझा कि उसका थोड़ा सा उत्तर दे दूं।

श्री अध्यक्ष—तो अब आप विषय पर आ जायं।

श्री रामायणराय—मेरे विचार से, जहां तक इस हमले का सम्बन्ध है, उस हमले के सही स्वरूप को समझने के लिए, हम में से हर एक को क्रुश्चेव महोदय ने अपने यहां बीसवीं कांफ्रेंस में जो रिपोर्ट पेश की थी उसको देखना चाहिए। उसके पेश होने के बाद ही इनकी सारी रीति-नीति बदल गई। उस रिपोर्ट में उन्होंने यह मान लिया था कि पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था के जो देश हैं उनमें और ढंगों से भी, शान्तिमय तरीकों से भी, वोट से भी, परिवर्तन हो सकता है। यह जो हिमालय की चोटी पर से, जिस हिमालय की चोटी की गाथा न जाने कितने कवियों ने गायी होगी, वेदों से लेकर आज तक जिस हिमालय को प्रहरी के रूप में देखा गया था उसके शिखर पर चढ़ कर जो आप अपना चमत्कार दिखाना चाहते हैं और उससे आप ऐसा समझते हैं कि वहां से भय का सृजन आप करेंगे, उस भय से जैसा कि उन्होंने कहा कि वार न्यूरोसिस पैदा हो जायगी,—अरे भाई! न्यूरोसिस समझने की कोशिश करो, न्यूरोसिस का प्रभाव किसके ऊपर होता है, यह रोग उन्हीं में उत्पन्न होता है जिनमें मानसिक विकार पहले से विद्यमान रहता है। स्वस्थ भारतीयों के मन पर उससे कोई न्यूरोसिस पैदा होने वाली नहीं है, उनमें कोई विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है।

हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आपने जो हमला किया है और आपका जो षडयंत्र है उसका मुकाबिला करने के लिए हममें से हर भारतीय तैयार है और जिस तरह से सन् ४२ में अंग्रेजों की हुकूमत को हमने दूर कर दिया, अंग्रेजों की फौज का मुकाबला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि सूर्य उदय से अस्त तक राज्य है, जिसकी फौजें आसमान में उड़ने वाली थीं, पृथ्वी पर दौड़ने वाली थीं, उसका हमने मुकाबला किया तो आप याद रखिए आपकी वह फौजें जो आज से कुछ दिन पहले अफीम खाकर सोती रहती थी, जिसको सबसे पहले हमारे महापुरुष अशोक ने जगाया था, उस फौज का हम मुकाबला करेंगे और उनको याद रखना होगा कि उन्होंने हिन्दुस्तान के उन लोगों से मुकाबला करने की कोशिश की थी जिनका इतिहास गौरव का इतिहास, वीरता का इतिहास, बलिदान का इतिहास रहा है। आखिर में मुझको यह भी कहना पड़ेगा, मजबूर होकर, कि यह भारत है, तिब्बत नहीं है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी सौभाग्य से आ गये हैं। उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर न देखें। जो भी इसके लिये

जरूरी हो वह किया जाय। अगर आपने इसको ठीक से देखा होता तो हमारे साथी प्रताप सिंह जी ने सन् १९५७ में आपको चिट्ठी लिखी थी, २९ जून, १९५९ को लिखी थी, ५ अगस्त, १९५९ को लिखी थी और २४ नवम्बर को लिखी थी उसका जवाब जरूर देते। पं० जवाहर लाल ने तो जवाब उसका देने की जहमत गवारा की लेकिन आपको उसका जवाब देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। आज भी सदन में श्रीमन्, कांग्रेस दल की तरफ से ऐसे लोग हमारे सामने आये हैं कि जिन लोगों के विचारों को सुनकर हमें बड़ी परेशानी हुई। हम लोगों को ऐसा लगा कि अभी उनको यह फैसला करना है कि कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं या नहीं। हम जानते हैं कि जो हमला हुआ है उसका सब से बड़ा कारण हमारी वैदेशिक नीति है जो टेढ़ी खड़ी रही है। अगर हमारी वैदेशिक नीति सीधी खड़ी होती, अगर हमारा सुरक्षा की तरफ सबसे पहले ध्यान.....

श्री अध्यक्ष—भारत सरकार की वैदेशिक नीति पर चर्चा नहीं होगी।

श्री रामायणराय—आखिर में इस हमले के बाद भी मैं तो चाहता था कि आपके द्वारा अपने मनोभाव व्यक्त कर दूं क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं.....

श्री अध्यक्ष—जब आप लोक सभा के सदस्य हो जायं तब लोक सभा में यह बात कहियेगा।

श्री रामायणराय—अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जनता का सहयोग जरूर मिलेगा। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सम्मुख आज इस सदन में है मैं उसकी भावनाओं का समर्थन करता हूं। मैं ऐसे प्रदेश से आया हूं जिसके सम्बन्ध में हम इस सदन में कल से चर्चा सुन रहे हैं और उसकी चर्चा कल भी होगी। इस माह की ११ तारीख तक मैंने इस प्रदेश का भ्रमण किया है लेकिन जितनी गर्मी इस मामले के बारे में लखनऊ और दिल्ली में है उतनी ही ठंड मैंने उधर महसूस की। वहां पर मैंने यह देखा कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के इलाके में जो कि बार्डर से मिलते हैं वहां पर कोई ऐसी सरगर्मी लोगों में नहीं है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार इस ओर पूर्ण सचेष्ट है। वहां पर इस प्रकार की जो धारणा फैलाई जा रही है उसका कारण भी लखनऊ ही है।

यदि मेरे पत्रकार भाई मुझे माफ करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त चाइनीज एम्बेसी ने हमारे लखनऊ और हिन्दुस्तान के कुछ पत्रकारों को इसलिए रुपया देकर अपनी तरफ किया है कि इस प्रकार की न्यूज छापने के लिये दें जिससे वहां पर कुछ आतंक फैले। अभी थोड़ी देर पहले मैं बड़े लच्छेदार भाषण सुन रहा था जो दोनों तरफ से हो रहे थे। मैंने देखा कि हमारे दोस्त राजनारायण जी ने यह कहा कि चश्मा पहने हुये मंत्री क्या देश की रक्षा करेंगे, लेकिन मैं भाई साहब को याद दिलाऊं कि अगर आप लड़ाई के मैदान में गये तो आप दिक्कत में पड़ जायंगे। बगैर चश्मे के उस ऊंचाई पर लड़ाई नहीं हो सकती। चश्मा आपको पहनना पड़ेगा। (व्यवधान) जिस चश्मे के बारे में आप कह रहे हैं मैं उसी की बात कह रहा हूं। आप उस चश्मे के बगैर, वहां लड़ाई करना तो दूर जिन्दा भी नहीं रह सकते।

जहां तक वहां की स्थिति और दिक्कतों का सवाल है उसके लिये इधर के और उधर के सदस्य बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर जो हमारी मिलिटरी या पी० ए० सी० है वह जो खबरें वहां से भेजती है उस पर यहां यथाशीघ्र कार्यवाही नहीं होती। यह हमारी शिकायत है और मैं समझता हूं कि इस ओर सरकार को आगे बढ़ना चाहिये।

[श्री सूरतचन्द रमोला]

जहां तक दर्रों का सवाल है, मैं जानता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो सब से नीचा दर्रा है वह निलंग का दर्रा है और वह १८,००० फीट की ऊंचाई पर है। जब वहां से हमारी पी० ए० सी० वापस आयी तो मैंने देखा कि कुछ तिब्बती उस पी० ए० सी० के वापस आने के पहले ही किसी दूसरे रास्ते से हमारे जिले में पहुंच गये और आज कल भी वह वहां रह रहे हैं। जब उधर जाने का कोई रास्ता नहीं रहा और बरफ पड़ गयी इसलिए हमारी सरकार ने उनको वहां रहने की इजाजत दे दी। मैं जानता हूं कि वह किसी विचारधारा को फैलाने की दृष्टि से नहीं आये क्योंकि इसके पहले दो, तीन वर्षों तक जो तिब्बती व्यापार के लिये यहां आया करते थे उनको किसी पास आदि की जरूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि जितने पासेज हमारे कागजात में दर्ज हैं उनके अलावा भी वहां पर रास्ते हैं जिनसे होकर लोग इधर से उधर आ जा सकते हैं। इसके लिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां का एक सर्वे होना चाहिये ताकि हम उन सब निश्चित स्थानों का पता लगा सकें और यह जान सकें कि कहां कहां से इंफिल्ट्रेशन हो सकता है। तिब्बती वहां पर हैं उनसे हमने बातचीत भी की कि वे किस रास्ते से इधर आ गये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उन स्थानों का एक प्रकार से सर्वे होने की बहुत जरूरत है और सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि हम इस इंफिल्ट्रेशन को रोक सकें। अब मेरे दोस्त जो जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बार्डर के पास कोई खतरा है या नहीं? खतरा तो जरूर है मगर हमें इस चीज पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। आज हमें देखना तो यह है कि अगर हम उस हिस्से को अपने प्रदेश का ही एक हिस्सा मानते हैं तो उस हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है या नहीं? वहां दर्रों के किनारे का जो हिस्सा है वहां पर जरूर खतरा है और खतरा हर वक्त मौजूद है, और जैसा कि हर तरफ से कहा गया है हमें हर खतरे का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये। पहाड़ की चोटी पर पल्ली तरफ का जो मैदानी पठारी इलाका है, उस हिस्से को अगर हम हिन्दुस्तान का हिस्सा मानते हैं, जैसा कि हमारा पुराना इतिहास भी बताता है, और जिस बेसिस पर हम अपना क्लेम मानते हैं, तो जब तक उन मार्गों पर पहुंचने के लिये हम उचित मार्गों का निर्माण नहीं कर लेते और वहां आवागमन के साधन नहीं हो जाते, तब तक उनकी सुरक्षा करने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन मार्गों का बनना बहुत ही जरूरी है। ऐसा करके ही हम खतरों का सामना कर सकते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और इस बात की ओर हमने कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है कि वहां पर मैदानी इलाका है, वहां पर व्यापार वगैरा सब खत्म हो गये हैं और लोगों के खाने-पीने तक के कोई उचित साधन नहीं रह गये हैं। आज फिर मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर उचित कार्यवाही करनी चाहिये, यह बहुत जरूरी है। इसके न होने से कहीं ऐसा न हो कि परिस्थिति बिगड़ जाय और यह लोग डिमारेलाइज हो जायं।

श्री शिवप्रसाद नागर—चीनियों ने कब्जा कर लिया है या नहीं, यह तो बताइये।

श्री सूरतचन्द रमोला—तीन, चार साल पहले बाराहोती पर चीनियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। उस इलाके में चीनी घुस आये थे लेकिन हमारी फौजें वहां गयीं और उन्होंने उनको वहां आने से रोक दिया इस समय वहां पर हमारा कब्जा है। कुमायूं रीजन के जो दर्रे हैं, वे किसी प्रकार भी उनके कब्जे में नहीं हैं। मैं अपने साथियों को बता दूं कि इस समय कोई भी हिस्सा उनके कब्जे में नहीं है। लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जिन्हें चीन ने अपने नक्शे में दिखाया है और वे हमारी हैं। जिन हमारी जगहों को उन्होंने अपने नक्शों में दिखा रखा है उनकी रक्षा हमें यथा सम्भव करनी है और करना चाहिये ताकि आइन्दा कोई दिक्कत पैदा न हो सके।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्द अपने एरिया के बारे में और कहना चाहता हूं कि वहां पर काटेज इन्डस्ट्रीज खोली जायं और सरकार उनको कोआपरेशन दे

कर चालू करे। आज वहां लोगों के पास कोई व्यापार नहीं रह गया है। वहां पर रेजिन और टर्पेन्टाइन जैसी इन्डस्ट्रीज कायम की जा सकती हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे जिले का जो रेजिन है वह किसी भी प्रकार आई० टी० आर० के पास नहीं जा सकता और न सरकार का कोई ऐग्रीमेंट आई० टी० आर० के साथ है। उससे और सरकार उस रेजिन को इंडस्ट्रीज के द्वारा वहीं पर इस्तेमाल कर सकती है और उन इंडस्ट्रीज में वहां के लोग काम कर सकते हैं।

दूसरे जो ऊन इंडस्ट्री है उसमें जो विलेज के डिस्प्लेस्ड लोग हैं और जिनके पास कोई काम नहीं रह गया है उनको लगाया जा सकता है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि उस इलाके में आने-जाने के साधनों की बहुत कठिनाई है। अगर स्नोबाउन्ड एरियाज में, फूटहिल्स में कोई रास्ते बना दें, भटवारी से बूढ़ाकेदार या बद्रीनाथ तक एक रास्ता बन जाय तो वहां के लोगों के लिये भी लाभदायक होगा और सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत फायदेमन्द होगा। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो प्रस्तुत है इस पर बहुत से विचार सुनने को मिले। अभी मुझसे पहले जो महाशय बोल रहे थे उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वहां कुछ हुआ ही नहीं, यानी सारी बातें ही हवा में उड़ गयीं और जो कुछ था वह सब खत्म हो गया। मगर अखबारों से और रोजाना अपने प्रधान मंत्री के वक्तव्यों से तो यह नहीं माना जा सकता कि यह मामला इतना मामूली है कि जिसको इस ढंग से टाल दिया जा सके। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खतरा बड़ा जबरदस्त है। कुछ ने कहा मामूली है। मगर असली हालत मालूम यह पड़ती है कि खतरा है और ऐसे लोगों से मुकाबला है, जिसके लिये जैसा रामायण राय जी ने बतलाया, कि उनका दोरुखा मामला है, देखने में कुछ और करने में कुछ। उनका सिद्धान्त, उनका वजूद इसी से कायम है कि वह हमेशा दोरुखा काम करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। माननीय नेगी जी ने कहा था कि हम कमजोर नहीं हैं, मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। किन्हीं के द्वारा हमें कमजोर बतलाया जाता है, शायद इसलिये ऐसा कहा जाता है कि हम अपने को कमजोर महसूस करके कमजोर हो जायें, यह भी उनकी पालिसी है। हमें डिमारेलाइज करने के लिये ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और उनके पास सब कुछ है। जो कल तक अफीम खाकर सो रहे थे वह आज आकर हमारे सिर पर गर्जना करके चटनी की तरह से चाट जाना चाहते हैं और उनके एजेन्ट यहां कहते हैं कि मुक्ति सेना आ रही है, रामचन्द्र की सेना आ रही है। वे अपने को विभीषण बतलाते हैं और कहते हैं कि इस देश में जो रावण राज्य कायम हो गया है इसको समाप्त करने के लिये जो मुक्ति सेना आ रही है उसका हम सब को स्वागत करना चाहिये। ऐसे लोग इस देश में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में भी यह सोचा जाय कि हमारी सारी बातें सुरक्षित रहेंगी और हम बैठकर यहां स्पष्ट बातें करेंगे तो क्या यह अच्छा होगा? मैं तो निवेदन करूंगा कि अगर साफ बातें करनी हैं, असलियत जाननी है तो सीक्रेट सेशन किया जाय जिसमें चुने हुये लोग हों वह बैठकर बात करें वर्ना इस प्रकार से खुले हाउस में बातें करना खतरे से खाली नहीं है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन को खबरें दे रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं। यहां एक ऐसी पार्टी बनी हुई है जो कि २४ घं० इस फेर में है कि किस तरीके से देश के अन्दर हड़बंग मचा दिया जाय, लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया जाय जिससे देश डिमारेलाइज हो जाय। ऐसी हालत में खुलासा बातें करना मेरी समझ से ठीक नहीं होगा।

कुछ लोगों ने नेगी जी की बातों को कहा कि उन्होंने गलत कहा कि हम इतने ताकतवर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष की यह परम्परा रही है कि हम अपने दुश्मन का भी हमेशा भला चाहते हैं। रामायण में देखा जाय कि जिस समय रामचन्द्र जी ने लंका पर हमला किया तो रावण के पास उन्होंने अनेकों बार दूत भेजा और यह चाहा कि रावण अपनी

[कुंवर श्रीपालसिंह]

हरकतों से बाज आवे और लड़ाई न हो, लेकिन अन्त में जब रावण ने अंगद से कहा कि अगर तुम्हारे मालिक इतने बहादुर हैं तो क्यों बार-बार दूत भेजते हैं, युद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं आ जाते, तब उसका फिर जो नतीजा हुआ वह सभी लोग जानते हैं कि रावण के दस सिर और २० भुजायें लाखों मर्तबे कटकर गिरीं और उसके प्राण पखेरू ले लिये गये। इसी तरह से भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र जी ने शिशुपाल की १०० गालियां सहीं लेकिन जब १०१ गाली निकली तो उनके चक्र सुदर्शन ने उसके मुकुट मंडित मस्तक को धराशायी कर दिया। तो यह हमारी परम्परा रही है कि हम कभी भी बढ़कर बातें नहीं करते हैं, अपनी शक्ति को कभी बढ़कर नहीं दिखलाते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कमजोर हैं।

कुछ लोगों ने कहा कि चीन को रूस से एटम बम मिल जायंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं कि एटम बम भी वही आदमी छोड़ सकता है जिसके अन्दर हिम्मत होगी, जिसके अन्दर चरित्र होगा, जिसक अन्दर आध्यात्मिक बल होगा, नहीं तो एटम बम धरा पर धरा का धरा रह जायगा। हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम दुश्मन की अंतड़ियां निकाल लेंगे इन्हीं नाखूनों से, और दांतों से। हम उस सभ्यता और उस देश के रहने वाले हैं जहां कभी किसी की लाल लाल आंखें नहीं देखीं और न कोई लाल आंखें दिखलाने वाला संसार में पैदा ही हुआ है। जिसने हमें लाल आंखें दिखाईं हमने नाखूनों से ही उसकी आंखें निकाल ली हैं। हम शान्ति प्रिय अवश्य हैं और चाहते हैं कि झगड़ा न हो लेकिन फिर भी हमें सिखलाया जाय कि आप शांत रहिये, लड़ाई की बात न कीजिये, मैं उन सिखाने वालों से पूछना चाहता हूं कि लड़ाई की बात कौन कह रहा है? हमसे यह कहा जा रहा है कि लड़ाई बड़ी बुरी चीज है, हम उसमें फंसकर तबाह हो जावेंगे, ताकि हम उससे डर जायं। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़ाई कौन करने जा रहा है? क्या भारतवर्ष ने कभी भी किसी की एक इंच भूमि भी ली है? क्या भारतवर्ष ने कभी भी किसी को लड़ाई के लिये ललकारा है? लेकिन उसके साथ ही साथ अगर कोई हमें लड़ाई के लिये ललकारेगा तो फिर हम उसकी ललकार को सहर्ष स्वीकार करेंगे। हमारी हमेशा से यह सभ्यता, संस्कृति और परम्परा रही है कि हम किसी की ललकार से भागते नहीं।

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हो गया। आप अपना भाषण कल जारी रखें।

गन्ना उत्पादकों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५३ के अन्तर्गत श्री गेंदासिंह, श्री नारायणदत्त तिवारी तथा श्री प्रतापसिंह की सूचना पर विवाद होगा। अब मैं इसमें समय नियुक्त कर देता हूं। जो विवाद प्रारम्भ करेंगे उनको मैं १५ मिनट देता हूं और उसके बाद मुख्य मंत्री या जो मंत्री चार्ज में होंगे उनके लिये १५, २० मिनट का समय रखता हूं, और लोगों के लिये १० मिनट से अधिक समय नहीं होगा।

श्री राजनारायण—हमारा भी प्रस्ताव है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—लेकिन मैंने गेंदासिंह जी का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

श्री राजनारायण—प्रस्ताव पहले हमारा आया था लेकिन आपकी उदारता की नजर उन्हीं पर पड़ गई है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनका प्रस्ताव ज्यादा व्यापक समझा, इसलिये स्वीकार किया।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम ५३ के अन्तर्गत गन्ने के दामों के सम्बन्ध में निम्न विषय पर चर्चा उठाना चाहता हूं। व्याख्यात्मक टिप्पणी भी प्रस्ताव में निहित है। प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल जिसमें १८ में से १५ लाख के लगभग उत्पादकों ने भाग लिया। चीनी उत्पादकों को गहरा धक्का लगा है। सरकार ने सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा अन्य अनेक प्रकार के अपने कर्त्तव्यों को पूरा न करना तथा किसानों के अपने उचित हक का मिल-मालिकों के हित के सामने बलिदान करने के लिये विवश करना है। राज्य सरकार के ऐसे दोषों के उदाहरण अनेक हैं परन्तु इस सदन के निश्चित आदेशों के विरुद्ध आचरण करना, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव केन यूनियन फैडेरेशन को स्वतंत्रतापूर्वक गन्ना उत्पादकों की हित रक्षा करने से रोक रखना, शान्तिपूर्ण हड़ताल को असफल करने के लिये अपने अधिकारियों का खुल्लमखुल्ला गैर-कानूनी काम करके मिलों को गन्ना पहुंचाना तथा व्यापक रूप से अशान्ति तथा उपद्रव कराने की अधिकारियों द्वारा चेष्टा करना प्रमुख तथा प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। सदन के माननीय उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी एक अभूतपूर्व घटना इस सिलसिले में है। आज भी प्रदेश के बड़े भूभाग में असन्तोष तथा बेचैनी का वातावरण फैला हुआ है। अतः यह सदन इस निश्चित महत्वपूर्ण तथा अत्यन्त आवश्यक विषय पर संस्तुति करता है कि गन्ना उत्पादकों की मुख्य मांग के अनुसार गन्ने का मूल्य २ रु० मन अविलम्ब निश्चित किया जाय तथा गिरफ्तार कार्यकर्त्ताओं को बिना शर्त रिहा किया जावे।

श्रीमन्, यह बात ऐसी है जिस पर काफी चर्चा भी हो चुकी है लेकिन मैं कुछ खास बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् ५१–५२ तक गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आने मन रही और एक ही कीमत समूचे प्रदेश के लिये रही। ३० रुपये ८ आने मन चीनी का भाव भी निर्धारित था। लेकिन गन्ने की कीमत कम इसलिये की गई कि २७ रुपये फी मन पर चीनी बिकेगी। एक वर्ड आफ आनर मिल-मालिकों की ओर से इस बात का दिया गया था और भारत सरकार ने इस वर्ड आफ आनर पर गन्ने की कीमत घटाकर १ रुपया ५ आने और १ रुपया ७ आने मन नियत कर दी। लेकिन जो चीनी पहले से बनी कारखानों में थी उसके लिये मिल-मालिकों ने कहा कि उसे भी हम २७ रुपये मन में बेंचेंगे। इसलिये ५२–५३ में २ आने मन और कटौती गन्ने की कीमत से हुई और ४ करोड़ रुपये के करीब जो जमा हुआ वह मिल-मालिकों को दिया गया कि वे चीनी २७ रुपये मन उपभोक्ताओं को बेचें। लेकिन कभी भी किसी मिल-मालिक ने २७ रुपये मन पर चीनी नहीं बेची। उस साल यह कहा गया था कि भारत सरकार को विदेश को भी चीनी भेजनी होगी। लेकिन बगैर ऐसा किये हुये देश में चीनी की कमी पड़ गई। बनावटी तौर पर मिल-मालिकों ने जो कमी दिखाई उसका परिणाम यह हुआ कि १ अरब रुपये की चीनी सरकार को बाहर से मंगानी पड़ी और ३० रुपये मन से नीचे चीनी का भाव कभी नहीं आया।

मैं श्री के० के० बिड़लाजी की कही हुई बात बम्बई के "कामर्स" अखबार से, जो वहां का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने दिसम्बर महीने के 'कामर्स' में कहा है, सफा ९८४ पर, कि "The production of sugar would increase, resulting in the smashing of the black market where sugar is selling at prices ranging between Rs. 60 and Rs. 100 per maund." यह बिड़ला साहब फरमा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में वह चर्चा कर रहे हैं। नेगी जी यहां इस समय नहीं हैं। उनको मैंने एक पत्र लिखा था और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कबूल किया है कि चीनी की कीमत प्रदेश के बाजारों में,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

हापुड़, कानपुर और मेरठ में—४६ से ४८ रुपये मन तक है और उन्होंने कहा कि इस समय कुछ घट कर ४४–४५ रुपये मन तक हो गई है। सरकार ने कीमत निर्धारित की है ३७.८५ रुपये मन। नेगी जी ने काउन्सिल में कहा था कि चीनी का खर्चा ३३.९७ रुपये फी मन पूर्वी जिलों में है और ३३.३४ रुपये मन खर्चा पश्चिमी जिलों में पड़ता है। अब हमारी मांग बिलकुल साफ है कि २ रुपये मन गन्ने की कीमत होनी चाहिये। यह अकेले हम ही नहीं चाहते हैं। यह क्यों नहीं होनी चाहिये, इसका दूसरी ओर से कोई जबाव ही नहीं है। हम तो ६० और १०० रुपये मन चीनी बिकने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो बिलकुल साफ हूं कि १ रुपये सेर से अधिक चीनी नहीं बिकनी चाहिये और जितनी चीनी की उपभोक्ताओं को आवश्यकता हो उतनी उनको मिले। उत्तर प्रदेश ऐसा कर सकता है और तब भी गन्ने की कीमत २ रुपये मन दी जा सकती है। इस पर विचार के लिये जो सामग्री हमारे पास है उसे यहां रख कर मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। शुगर टैक्नालाजिस्टस एसोसियेशन की तरफ से प्रकाशित बुलेटिन मेरे पास है कि बम्बई की चिलबन्डी शुगर फैक्ट्री की रिकवरी १० मन की है १०० मन गन्ने में से और स्टेट ने ५२ रुपये फी टन कीमत मुकर्रर कराई। पिछले साल १८ दिसम्बर को जो जैन साहब ने कहा था कि यह मिनिमम प्राइस फिक्स की है, उससे ज्यादा कीमत भी किसान को मिल सकती है बशर्ते कि रिकवरी ऊंची हो और ड्यूरेशन आफ सीजन लम्बा हो। यू० पी० में ड्यूरेशन भी ज्यादा है और रिकवरी भी ज्यादा है और चीनी भी ऊंची कीमत पर बिक गई।

पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब ने काउन्सिल में फरमाया था और वायदा किया था कि हम कुछ न कुछ करेंगे। यह कार्यवाही में अंकित है। क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है उसे ही मैं यहां डिसकस करना चाहता हूं। मैं भारत सरकार की जिम्मेदारी को छोड़ देता हूं। जैन साहब ने १८ दिसम्बर के भाषण में यह कहा था कि ४ करोड़, ३१ लाख, ९५ हजार रुपया दूसरे प्रदेशों के काश्तकारों को बोनस की शक्ल में मिला है। लेकिन देश की चीनी का आधा पैदा करते हैं हम उत्तर प्रदेश वाले, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को कितना पैसा दिलाया? जब ५२ और ५६ रुपये टन चीनी बम्बई की सरकार दिला सकती है और उसे भारत सरकार देश के विरुद्ध बगावत नहीं समझती तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में किसानों की मददगार होनी तो दूर रही, परन्तु जब कभी किसानों ने आवाज उठायी, किसानों के ऊपर जुल्म किया गया।

मैं जुल्म करने की बात इसलिये करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई कानून ऐसे बना रखे हैं जिनमें गन्ना देने के लिये उत्तर प्रदेश के किसान को बिलकुल बांध रखा है, सोलहों आने अपने हाथ में रखा है। सरकार ही उनके अनुसार गन्ने के ग्राहकों को तय करेगी, रिजर्व किये हुए इलाके में ज्यादा कीमत पर भी कोई किसान अपना गन्ना नहीं बेच सकता। खांडसारी और कोल्हुओं से ज्यादा दाम उनको मिल जाता था, वह भी नहीं ले सकते, उस पर भी सरकार ने प्रतिबंध अभी लगा दिया है। सरकार ने केन कोआपरेटिव फेडरेशन कायम की है और उसका चेयरमैन केन कमिश्नर को बना दिया है। वह केन कमिश्नर के हाथ में सोलहो आना है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कोआपरेटिव केन यूनियन फेडरेशन को गन्ने की कीमत के सिलसिले में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वे १८–२० लाख गन्ने के उत्पादकों को अपनी बातचीत और गन्ने के लिये सौदाबाजी करने का कौन सा रास्ता आप बताते हैं।

जब हम चाहते हैं कि हम अपना गन्ना मिलों को न दें तो उसको बगावत कहा जाता है और जो लोग इसको आर्गनाइज करते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे कसूर करते हैं। उग्रसेन जी का मामला हमारे सामने है, मैं खुद इसको भुगत चुका हूं, कोई भी सरकारी अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझता, मनमानी करते हैं। माननीय नारायणदत्त तिवारी यहां हैं, उनको गिरफ्तार करने में, उनको बंद कर देने में किसी कानून का पालन नहीं किया गया। कानून के खिलाफ कोई भी बात करने में सरकार को

शर्म नहीं आती और न मारने पीटने में आती है। एक कानून पर्ची सप्लाई करने का बना हुआ है। यह सब जानते हैं कि एक-एक पर्ची को प्राप्त करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हजारों पर्चियां उस कानून को तोड़ कर दी जाती हैं। हड़ताल को तोड़ने के लिये जो नहीं करना चाहिये वह किया जाता है। फिर अब आप ही बताइये कि काश्तकार को क्या रास्ता अख्तियार करने के लिये रह जाता है ? विधान सभा एक ऐसी जगह है जिस जगह पर हम अपनी दिक्कतों का कुछ इलाज ढूंढ सकते हैं। इसी विधान सभा से १ रुपये १२ आने मन गन्ने की कीमत का प्रस्ताव पास हुआ। जैन साहब ने जो अपने भाषण में कहा है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के पूरे मशवरे के मुवाफिक ही यह कीमत मुकर्रर की है। उन्होंने कहा है कि जो कीमत मुकर्रर की गयी है वह यू० पी० गवर्नमेंट के बिलकुल खिलाफ नहीं की है, मुआफिक की है।

एक रुपया बारह आने मन का प्रस्ताव इसी विधान सभा ने पास किया था। केवल एक कमी रह गयी थी। इस बात को मैं पांइंटेडली कहना चाहता हूं कि उस वक्त आप चेयर पर नहीं थे, मैं चेयर पर था। अगर इस वजह से उसकी वकत कम हो जाय तो दूसरी बात है। जब मैं वहां मौजूद था तो मुख्य मंत्री जी यहीं मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में १ रु० १२ आने का प्रस्ताव पास हुआ। मैं समझता हूं प्रजातंत्र पद्धति में, प्रजातंत्र के ढंग में और लोगों से मुख्य मंत्री जी का विश्वास अधिक होना चाहिये क्योंकि सबसे बड़ा सुख और ओहदा उनके नीचे है। मैं समझता हूं उस प्रस्ताव का आदर नहीं किया गया। शुगर केन बोर्ड ने जिन फैसलों को किया उनका भी आदर नहीं किया गया। सरकार जिन आश्वासनों को देती है उनको भी सरकारी अधिकारी और खुद सरकार पूर्ण करती नहीं है फिर कैसे काम चलेगा और फिर किसानों के लिये कौन-सा रास्ता रह जाता है। कन्ज्यूमर को ३०-३२ रुपया पर चीनी मिले इसके लिये १९५० में टैरिफ बोर्ड बैठा। उसने इस बात को कहा कि चीनी का दाम २४ रु० १२ आना मन होना चाहिये और उस समय १ रु० ७ आना मन गन्ने का दाम हो। अगर उससे कम गन्ने का दाम होगा तो किसानों को नुकसान होगा क्योंकि वह तो कास्ट आफ प्रोडक्शन है। फिर बताइये किसानों के लिये क्या रास्ता रह जाता है ? मैं बहुत बदनाम हूं कि बार-बार गन्ने की बात उठाता रहता हूं। मैं क्या करूं ? लाखों किसानों का संबंध इस गन्ने से है। जवाहर लाल जी से जाकर मैंने इस बात को कहा। उनका गन्ने के किसानों से क्या संबंध था कि उनको मैं गोरखपुर ले गया ? उन्होंने गोरखपुर जाकर पूरा दिन किसानों के लिये दिया। क्या पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जो कि आज हमारे होम मिनिस्टर हैं वे गन्ना काश्तकारों की मदद नहीं करते हैं, क्या गांधी जी गन्ना काश्तकारों की मदद नहीं करते थे, क्या राजेन्द्र बाबू गन्ना किसानों की मदद नहीं करते हैं ?

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि विवाद के समाप्त होने पर इस बात पर कोई वोटिंग तो नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रस्ताव नहीं है, मैंने इस पर लिखा है कि इस सम्बन्ध में चर्चा होगी। यह नीचे जो "संस्तुति करता है" शब्द छपा है वह गलत छप गया है। यह कट जाना चाहिये।

"इसलिये इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम ५३ के अनुसार चर्चा उठाने की अनुमति दी जाय" ये शब्द रहेंगे। जो नियम दिया हुआ है उसमें भी यह लिखा हुआ है। इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, आपने अभी कहा कि इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष--इसमें दिया हुआ है--"There shall be no formal motion before the House, nor voting."

५५--"सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा।" इस तरह से नियम तो बना हुआ है। नियम ५३ के अनुसार यहां "प्रस्ताव" शब्द नहीं आ सकता। यह लपस एक्सप्रेशन है।

श्री राजनारायण---जब नियम में लिखा हुआ है तो फिर स्पष्टीकरण की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री अध्यक्ष--उनके लिये जरूरत पड़ी क्योंकि "प्रस्ताव" शब्द जो कह दिया है। उसको निकाल दिया जाय।

इसके ऊपर पहले माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे उसके बाद मैं किसी का नाम लूंगा। क्योंकि पहले किसी को बोलने के लिये इजाजत देने पर फिर कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं तो हम बहस किस बात की करें। जवाब पहले मंत्री जी को देना चाहिये। इसलिये मैं यही तरीका रखता हूं ताकि बहस व्यवस्थित ढंग से हो सके।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को माननीय गेंदासिंह जी ने उपस्थित किया, वह जरूर महत्व का है। उन्होंने जो कागज पढ़ा उसमें तो बहुत सी बातों का जिक्र है लेकिन विशेष शिकायत उनको गवर्नमेंट से और मुझसे यह है कि इस सदन में जो निश्चय हुआ था गन्ने की कीमत की बाबत कि १ रु० १२ आ० मन भाव किया जाय, उस का हमने साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो कीमत रखी वह हमारी राय से रखी। आज से कुछ दिन पहले भी सदन में यह बात कही गयी थी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि इस वक्त जो कीमत रखी गयी है वह स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट कर के रखी गई है। मुझे याद पड़ता है कि सदन के बाहर भी इस किस्म के बयान दिये गये हैं। यहां पर एक माननीय सदस्य मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न ला रहे थे, इस वजह से कि उनकी समझ में मैंने सदन के निश्चय का विरोध किया और सदन ने जो कुछ कहा था उसके विरुद्ध गवर्नमेंट आफ इंडिया को राय दी। श्रीमन् को याद होगा कि मेरा बराबर यह खयाल रहा है और बराबर इस रास्ते पर चलता रहा हूं कि हमसे और भारत सरकार से जो खतोकिताबत हो उसको गोपनीय रखा जाय, उसका जिक्र न किया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मामला है कि आज मुझे अपने इस दस्तूर से कुछ थोड़ा-सा हटना चाहिये। इसकी वजह यह है कि एक तो हमारे माननीय गेंदासिंह जी ने जैन साहब के किसी वक्तव्य का हवाला दिया कि उन्होंने यह लिखा है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट का फुल कन्सलटेशन किया। अभी हाल में लोक सभा में जो गन्ने की कीमत की बात चली और उसका जिक्र हुआ तो वहां भी गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से डिप्टी मिनिस्टर मिस्टर टामस ने भी कहा था कि "प्राइस हैज बीन फिक्सड आफ्टर कन्सलटिंग दि टू स्टेट गवर्नमेंट्स। (Price has been fixed after consulting the two State Governments)" अब 'कन्सलटेशन' का क्या अर्थ होता है इसे यहां बताने की जरूरत नहीं है। राय का पूछना ही राय का मानना नहीं होता। फिर भी मेरा खयाल है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये था, ऐसी बात भ्रामक हो सकती है और लोगों के मन में इसको सुनने के बाद यह खयाल हो सकता है कि शायद स्टेट गवर्नमेंट ने ही राय दी हो कि १ रुपया ७ आना मन कीमत ही ठीक है। मेरी राय है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये था। जब गवर्नमेंट आफ इंडिया केन की प्राइस फिक्स करती है तो उसकी जिम्मेदारी उनको लेना चाहिये, लेकिन चूंकि एक भ्रामक बात कह दी गई है इसलिये सफाई के लिये मजबूर होकर मैं एक खत पढ़ना चाहता हूं जो हमारी तरफ से केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था। यह श्री पाटिल के नाम है और १९ सितम्बर का है। मैं उसे पढ़े देता हूं:

"In this letter I wish to draw your attention to a very important question connected with the sugar industry. As you know, the ex-factory price of sugar is controlled in Northern India but not in the South. This has always been a source of dissatisfaction to manufacturers in the north. Another and a more important question is the price to be paid for sugarcane. The Government of India fixes the price one year in advance. The State Governments are consulted no doubt, but how far their opinions weigh with the Centre is really problematic. There has been a persistent pressure from cane growers that the price fixed for the last two or three years, namely Rs. 1/7/- per maund is hopelessly inadequate. It is supposed to be related to the ex-factory price of Rs. 36/- per maund for sugar. Everyone knows that as a matter of fact sugar has been fetching much higher price. Manufacturers plead that so far as they are concerned they get only Rs. 36/-, the benefit of the higher market price goes to the middleman. In theory this is correct, but it is a well known fact that the middlemen, at least most of them are really the agents of the manufacturers under a transparent disguise. In most cases, the factory sells the sugar to itself under a different name at Rs. 36/- and then sells it in the market at a higher price in which the cane-grower gets absolutely no share. It seems highly unfair to pin the producer down to a figure which bears no actual relation to reality. Last year, both the Uttar Pradesh and the Bihar Legislatures passed resolutions for raising the price to Rs.1/12/- per md. You know that there is a Joint Sugar Control Board for Uttar Pradesh and Bihar in which the two governments as well as the cane-growers and manufacturers are represented. A meeting of this Board was held in Patna this year on the 16th instant and the Board has unanimously passed a resolution to the effect that notwithstanding the fact that the Central Government announced last year that the price of cane for the 1959-60 season would be Rs.1/7/- it should be requested to revise this figure and raise it to Rs. 1/12/- The representatives of the manufacturers also expressed themselves in favour of this proposal, although they said that if it is accepted they would find it difficult to earn any profit at the fixed rate of Rs.36/-. I feel that the recommendation of the two legislatures and of the Joint Sugar Control Board should be accepted by the Central Govt. Last year there was an agitation for an increase in the sugar price which resulted in the disturbance of the law and order situation. Several people had to be sent to jail and firing had to be resorted to at least in one place. The agitation would have been intensified but for the fact that the cane-growers knew that the State Govt.—I am referring to Uttar Pradesh—was sympathetic towards their demand but found itself helpless in the matter. I would request you may strongly to reconsider last years decision & announce reasonable price much before the crushing season starts in November next.

मैं समझता हूं कि इसके बाद अब किसी को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लेजिस्लेचर की इच्छा के खिलाफ या शुगर कंट्रोल बोर्ड की इच्छा के खिलाफ कोई बात कही ।

मैं समझता हूं सब लोग समझ गये होंगे । मैं इसका हिन्दी में सारांश बताए देता हूं. . . .

श्री राजनारायण—यह पूरा लेटर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पत्र में और भी कई विषय हैं । इस संबंध में जो था वह मैंने पढ़कर सुनाया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके यह भी बता दें कि उन्होंने राय को न मानने के क्या कारण उत्तर में बतलाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन्होंने उत्तर में लिखा है कि हमने अपने एक्सपर्ट्स से राय ली। उन्होंने बतलाया कि गल्ले वगैरह की कीमतों पर इसका बुरा असर पड़ेगा लिहाजा हम मजबूर हैं कि आपकी राय नहीं मान सकते।

श्री राजनारायण---माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण आरम्भ करने के पूर्व सही में यह बात कही थी कि उनके ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया गया था और वह किसी दूसरे ने प्रस्तुत नहीं किया था बल्कि सोशलिस्ट पार्टी की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था। श्री रामस्वरूप वर्मा, हमारी पार्टी के उपनेता ने प्रस्तुत किया था और उसमें हम सब की सहमति थी, वह हमारा था। मगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अब स्पष्टीकरण किया है आप स्वतः समझ सकते हैं कि इसका दोष हमारे ऊपर नहीं था बल्कि मुख्य मंत्री जी पर था जिन्होंने अब तक इस पत्र को छिपाये रखा था। अगर यह पत्र पहले ही प्रकट हो गया होता तो हमको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करने की क्यों आवश्यकता होती? तो अब तक मुख्य मंत्री जी ने गोपनीय बनाकर रहस्यमय ढंग से इस सदन में अपने भाव को कई बार प्रकट किया था वही कारण था कि इसका सारा दोष माननीय मुख्य मंत्री जी पर आया। जो पत्र अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा उससे इस बात को जान कर हमें प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इस सदन के भाव को और बोर्ड के भाव को सही-सही तरीके से केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखा था। मगर मुख्य मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि इनकी एक बात जो कि सही थी और जो सदन ने पास की थी, जब उसको केन्द्रीय सरकार ने नहीं माना तो उसके बाद जो इधर के कदम प्रदेश की सरकार की ओर से उठे उसके लिये क्या कहा जाय? किसको दोषी बनाया जाय? मैं कहना चाहता हूं इस सदन की राय की जो उपेक्षा सरकार ने की उसकी जितनी भर्त्सना यह सदन करना चाहता है हम उसके लिये तैयार हैं। वहां के उपमंत्री ने जो अनुचित ढंग से केन्द्रीय सरकार को लांछित किया है उसके लिये हम उनकी भर्त्सना करने को तैयार हैं और चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने जो किसानों के हित की उपेक्षा की है और अनावश्यक ढंग से वाद-विवाद हुआ है उसका सारा का सारा दोष केन्द्रीय सरकार पर जाना चाहिये और मैं चाहता हूं मुख्य मंत्री जी हमारी अगुवाई करें और हम उनके साथ हैं और अगर वे असमर्थ हैं तो जहां मौलिक प्रश्न आता है वहां उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिये। मुख्य मंत्री जी हैं, बहुत से लोग कह सकते हैं विश्व माने भारत, भारत माने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश माने काशी, अरे मैं भूल गया वाराणसी...

श्री अध्यक्ष---इससे तो आपका भी गौरव बढ़ जाता है।

श्री राजनारायण---वाराणसी शब्द जो है इससे मुख्य मंत्री जी अच्छी तरह से सहमत नहीं थे। जैसा मुझे मालूम है वे जोर काशी पर दे रहे थे इस पर जवाहर लाल जी का इनसे विवाद भी हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बहुत मौकों पर अपने दोस्तों से सराहना भी करता हूं। इधर की स्थिति में मैं देखता हूं कि कभी-कभी मुख्य मंत्री जी का जवाहरलाल नेहरू जी समर्थन करने लगते हैं तो मैं कहता हूं अपने दोस्तों से जवाहर लाल जी जो समर्थन कर रहे हैं वे अपनी स्थिति को कायम रखने के लिये कर रहे हैं, न कि उनकी स्थिति.....

श्री अध्यक्ष---अब आप विषय पर आ जाइये।

श्री राजनारायण---इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उसका दोष मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार पर डाल दिया और हम भी डालने को तैयार हैं। मगर प्रश्न यह है कि इधर जो अध्यादेश जारी हुए यह तो प्रदेश की सरकार ने किये हैं। इधर जो ४ आने तक सेस बढ़ाने का हुआ, सीजन शुरू होने से पहले जितनी चीनी मिल-मालिक बनायेंगे उनको ५ रुपये तक छूट देने के लिये अध्यादेश तो प्रदेश की सरकार ने ही जारी किये हैं और जो गन्ना पेरा जायगा उस गन्ने पर भी कुछ छूट देने की बात बाद में की गई थी वह ५ आने मन किसने की? उसकी भी प्रान्तीय सरकार ने ही छूट दी। तो अगर सारा हिसाब जोड़ा जाय कि सीजन शुरू होने से पहले मिलों के जरिये कितना गन्ना पेरा गया और कितनी चीनी बनी, उस पर

मिल-मालिक को कितनी छूट हुई और गन्ने पर ५ आना मन के हिसाब से कुल कितनी छूट हुई तो माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहिये था कि इस समय जो हम छूट दे रहे हैं यह छूट आखिर जायगी कहां से? तो क्यों नहीं २ रुपये किसानों की मांग को मान लिया जाता? मैं यहां पर मुख्य मंत्री जी को दोषी पाता हूं जैसे कोई निर्बल वकील हो, वह कह तो दे कि यह हमारे तर्क हैं लेकिन उन तर्कों को वह मजबूती के साथ न कहे। उसका दोषारोपण माननीय मुख्य मंत्री जी पर आता है। सारे तर्कों को सामने रखते हुए उनको कहना चाहिये था कि जो गन्ना पहले पेरा जायगा तो ५ आने क्यों उधर छूट दें और जब चीनी बन जायगी तो उधर ५ आने मिल मालिक को क्यों छूट दें। इसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार पर दोषारोपण किया जाय तो सही होगा।

३६ रुपये चीनी की प्राइस क्यों फ़िक्स की गयी इसी बात को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सफ़ाई पेश की। इस उद्योग को लेकर उन्हें कहना चाहिये था कि उत्तर प्रदेश में ६७–६८ चीनी मिलें हैं और सारे देश में १३२ चीनी मिलें हैं। सारे देश में जब आधी चीनी हम पैदा करें तो हमारी राय की अवहेलना क्यों हो और हमारे किसानों के हकों की हिफ़ाजत क्यों न हो। जो पत्र सरकार ने भेजा था मैं कह सकता हूं कि वह लचर था।

पारसाल हड़ताल हुई, इस साल हड़ताल हुई। पारसाल गोली चली छबेला में। कई आदमी मर गये और इस साल कई लोग गिरफ्तार हुये। वह मामला सदन में उठा। राम सेवक यादव, एम० पी० गिरफ्तार हुए। ये सारी बातें हो रही हैं। इन चीजों को जरा देखा जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी भी किसानों के उतने ही शुभचिन्तक हैं जितने हम हैं लेकिन हमारे और उनके रास्ते में भिन्नता है। हम क्रियात्मक रूप से किसानों का हित चाहते हैं लेकिन वे मौखिक रूप से किसानों के शुभचिन्तक हैं और व्यावहारिक रूप से मिल मालिकों का फ़ायदा करायेंगे। १९४७ से लेकर १९५२ तक चीनी का क्या भाव था और गन्ने का क्या भाव था? १ रुपये १० आने मन, १ रुपये १२ आने मन और २ रुपये मन गन्ने की कीमत रही और उसी के अनुपात में क्रमशः चीनी का भाव २७ रुपये मन, साढ़े ३० रुपये मन और ३४ रुपये मन था। सरकार ने इन तथ्यों को क्यों नहीं पेश किया? उस समय हमारे यहां इस तरह से चीनी की कीमत में तथा गन्ने की कीमत में संतुलन चल रहा था। लेकिन आज १ रुपये ५ आने और ७ आने मन जब गन्ना है तो चीनी की कीमत ३६ रुपये मन रखी गई। अगर अतिरिक्त लूट नहीं करते मिल मालिक तब भी कीमत चीनी की ज्यादा थी बनिस्बत गन्ने की कीमत से एक ओर तो सरकार कहती है कि वह पैरिटी के सिद्धान्त को स्वीकार करती है लेकिन सरकार इस बात की सफ़ाई करे इस बात को देख कर कि जो खेत से पैदा होने वाली वस्तुएं हैं और जो कल कारखानों से पैदा होने वाली वस्तुएं हैं, उनमें क्या उसने संतुलन की नीति रखी है? संतुलन की नीति न रख कर उसने लूट की नीति रखी है और मिल मालिक व सरकार की साजिश से यह हो रहा है और इस साजिश में उपभोक्ता पीटे जायं और उत्पादक पीटा जाय।

मैं आज इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि सरकार को २ रुपये मन गन्ने व ३२ रुपये मन चीनी का भाव रखना चाहिये। जब २ रुपये मन में गन्ने की बात कहता हूं तो ३२ रुपये चीनी की कीमत हम संतुलन को ध्यान में रखकर ही कहते हैं और इस मांग को माननीय मुख्य मंत्री जी मजबूती के साथ करें, कमजोरी के साथ कमजोर वकील की तरह शब्द की व्याख्या न करें।

श्री आरखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन आज कर दिया। अगर यह रहस्योद्घाटन कुछ दिनों पहले हुआ होता तो इससे प्रदेश के गन्ना उत्पादकों का और उनके बीच में काम करने वालों का, सभी लोगों का बड़ा लाभ हुआ होता। खैर, देर ही सही,

[श्री झारखंडे राय]

लेकिन आज उन्होंने इस चीज को साफ किया। कम से कम हमारी अब कोई शिकायत मुख्य मंत्री जी से या उनकी सरकार से नहीं है।

(इस समय ५ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुए।)

उन्होंने इस आदरणीय सदन द्वारा पारित प्रस्ताव का आदर किया और समुचित आदर किया और यह प्रजातांत्रिक भावना उचित ही थी। हम सब को यह बात मालूम है कि गन्ने का दाम घटता ही गया। इसकी चर्चा अभी कुछ दिन पहले यहां दो बार विस्तार से हो चुकी है और आज भी हमारे पहले के वक्ताओं ने इस पर रोशनी डाली है। इसके विपरीत चीनी का दाम बराबर बढ़ता गया। इस दोतरफा लूट से हमारे प्रदेश के कुछ चीनी मिल मालिकों का ही फायदा हुआ और इस सदन में माननीय भीखालाल जी द्वारा प्रस्तावित जो प्रस्ताव था, जिसको इस सदन ने कृपा करके स्वीकार किया था, उसके बाद यह और जरूरी हो गया था कि हमारे प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता की इस भावना को केन्द्रीय सरकार स्वीकार करती। हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार में भी काफी चीनी मिलें हैं और वह भी हमारे देश का एक प्रमुख चीनी उत्पादक केन्द्र है। वहां की असेम्बली ने भी इस प्रकार के प्रस्ताव को पास किया था। दो प्रदेशों की असेम्बली में प्रस्ताव पास होने के बाद स्पष्ट है कि हमारे देश की करीब-करीब ९ करोड़ से भी ऊपर जनता की यह भावना थी कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाय। उस समय गन्ने का दाम बढ़ाने की बात पौने दो रुपये तक ही थी और बिहार सरकार के बारे में हमें नहीं मालूम कि वहां की सरकार ने किस सिफारिश के साथ उस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने ९ करोड़ जनता की आवाज को ठुकराया। यह उसकी एक विशेष पूंजीवादी चरित्र का ही परिचायक है।

लाखों गन्ना उत्पादकों की जेब काट कर कुछ चीनी मिल मालिकों की जेब भरना यह किसी प्रकार से भी जनहित की बात न कही जा सकती है, न सोची जा सकती है। मैं चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा है कि, हमारा कोई झगड़ा अब मुख्य मंत्री जी से या उनकी सरकार से इस विषय में नहीं है। अब हमको वह रास्ता निकालना है कि अगर २ रुपये नहीं तो पौने दो रुपये मन का प्रस्ताव जो इस सदन में पास हुआ था और जिसकी सिफारिश माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी की है, उसको कैसे मनवाया जाय। मैं इसका स्पष्ट जवाब चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से स्वयं, और इसको मनवाने के लिये वह जो भी कदम उचित समझते हों भारत के संविधान के अनुसार, क्योंकि हमारा प्रदेश कोई आजाद देश नहीं है कि वह केन्द्रीय सरकार से अलग कोई अपना ऐसा कदम उठायेगा जो संविधान के विरुद्ध हो, लेकिन फिर भी संवैधानिक मान्यताओं के अन्दर, उनकी जो परिसीमायें हैं उनके भीतर वह कौन सा कदम उठाना चाहते हैं अपनी इस सिफारिश के अलावा, हम समझते हैं कि अगर वह यह बता दें, तो हमारे लिये बड़ी आसानी होगी और इस संबंध में वह जो भी कदम उठायेंगे उसमें हमारा पूर्ण सहयोग उनको प्राप्त होगा।

जहां तक गन्ना पैदा करने वालों का सवाल है, उनको यह बात मालूम भी नहीं थी और उनके बीच में काम करने वालों को भी इस की जानकारी नहीं थी। इस सदन में कई बार इस पर प्रश्नोत्तर भी हुए लेकिन मुख्य मंत्री जी का जवाब कुछ ऐसा गोलमोल रहा कि चीज साफ नहीं हो सकी कि उनकी सिफारिश क्या थी। अखबारों में कुछ ऐसी खबरें निकली थीं जिनसे ऐसा भ्रम हो रहा था कि वह बात तो कम से कम नहीं है जो अभी आज खुद उन्होंने कही है। बल्कि इसके उल्टे सिफारिश जान पड़ती थी। तो इस भ्रम से गन्ना उत्पादकों के पास और क्या रास्ता रह जाता है सिवाय इसके कि जब हजारों, लाखों किसानों ने भांति-भांति से प्रदर्शन किया और अपनी भावना को सरकार तक पहुंचाया। पिछले कई साल से छोटी-मोटी हड़तालें या मुठभेड़ें हुई तो गन्ना उत्पादक के सामने सिवाय इसके कि हड़तालें करा कर या जनमत के दबाव से सरकार को विवश करे कि उसकी उचित मांगों को माना जाय और कोई रास्ता रह ही नहीं

जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार इस रास्ते को उचित नहीं समझती है वरना सरकार की ओर से ऐसा कटु व्यवहार न किया गया होता, इस सदन के माननीय सदस्यों को गिरफ्तार न किया गया होता, उपाध्यक्ष महोदय को गिरफ्तार न किया गया होता और यह तमाम बातें जो पुलिस ने की हैं वह न हुई होतीं अगर सरकार हड़ताल को उचित समझती होती। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा रास्ता रह जाता है। अब सवाल और उभड़कर सामने आता है कि मुख्य मंत्री की सिफारिश के बाद भी जब केन्द्रीय सरकार नहीं मानती तो वह क्या करें। सिवाय लड़ाई के, सिवाय संघर्ष के और सिवाय आन्दोलन के मेरी समझ में और कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। लेकिन लड़ाई में हार भी होती है, जीत भी होती है और समझौता भी होता है। इन संघर्षों का, टक्करों का और आन्दोलनों का असर पड़ा जो आज दाम तीन आना बढ़ा है, हमारा प्रयास फला और हमें आगे भी सफलता मिलेगी। इस विश्वास के साथ हम चाहेंगे कि मुख्य मंत्री जी हमें रास्ता बतायें कि किस रास्ते पर वह और हम मिलकर, पूरा सदन मिल कर, अपनी बात को पूरा कराये जो इस सदन ने प्रस्ताव पारित किया था। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता---यह प्रस्ताव नहीं है। आप अपनी राय जाहिर कीजिये। यह चर्चा का विषय है।

श्री मदन पांडेय---श्रीमन्, गन्ना उत्पादकों ने इस वर्ष गन्ने के दाम में वृद्धि के लिये आन्दोलन चलाया था। जो विभाग इससे संबंधित रहा है उससे गन्ना काश्तकारों को शिकायत रही है। आज एक बड़ी शिकायत का निराकरण हुआ है। वह शिकायत थी कि इस सदन में जो प्रस्ताव किया गया था उसके संबंध में जो सिफारिश सरकार ने भेजी वह उचित नहीं भेजी, परन्तु प्रस्तुत पत्र में जो मुख्य मंत्री जी ने सिफारिश की है उसके लिये वह प्रशंसा के पात्र हैं। यह प्रजातंत्र का युग है और इसमें जितने रास्ते हमें बताये गये हैं उनका प्रयोग करने के बाद हम लोग जहां के तहां हैं और मुख्य मंत्री जी जो कर सकते थे उनकी बातों से मालूम पड़ता है वह भी उन्होंने कर लिया। अब क्या किया जाय यह सवाल पैदा होता है।

श्रीमन्, दो रुपये मन गन्ने का दाम किया जाय यह मांग गन्ना उत्पादकों की रही है। पहले सदन ने एक रुपये बारह आने मन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था, परन्तु प्रस्तुत परिस्थितियों में भाव दो रुपये मन किया जाय यह मांग गन्ना काश्तकारों ने की है। जो हड़ताल हुई है उसमें भले ही शुगर इंडस्ट्री में डेड लाक करके कागज में जानबूझ कर साबित न किया गया हो लेकिन यह सफल मतगणना रही है। इसलिये जो अन्तिम अहिन्सात्मक अस्त्र हमें प्राप्त है उससे भी इस मांग का औचित्य सिद्ध कर दिया गया है। अधिष्ठाता महोदय, अब हमारे अनशन करने से उन्हें दुख होता है, हड़ताल करने से उन्हें दुख होता है, हम सत्याग्रह करना चाहते हैं तो उन्हें दुख होता है। तो अब कौन सा अस्त्र हमारे तरकस में बाकी है, उसकी ओर वह इशारा करें? ऐसी अवस्था में हम उनको अपने नेता के रूप में मानने के लिए तैयार हैं जब कि उनकी इस संस्तुति के केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकृत हो जाने के बाद, वह हमें आगे का मार्ग प्रदर्शन करें। अगर वह हमें रास्ता नहीं बतायेंगे तो गन्ना काश्तकार केवल इस सिफारिश के बाद संतुष्ट हो कर बैठ रहेगा ऐसी आशा उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसलिये उन्हें केन्द्रीय सरकार को सलाह देनी चाहिए कि वह अगले वर्ष के लिये और इसी वर्ष के लिए जो गन्ने के दाम में वृद्धि की मांग है उस पर पुनर्विचार करे। दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में माननीय गेंदासिंह जी वगैरह का एक डेपुटेशन पाटिल जी से मिला था। ११ दिसम्बर को प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना और उनके साथियों का एक डेपुटेशन पाटिल जी से मिला था। उनका यह कहना था कि अगर हम चीनी मिल मालिकों को राजी भी कर लें तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने सेस में से कुछ त्याग करके गन्ना काश्तकारों का दाम बढ़ाने के

[श्री मदन पांडेय]

लिये तैयार होगी। यह बात जिम्मेदार लोगों से पाटिल जी ने कही है। मुझसे प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने यह बात कही है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में अपना रुख स्पष्ट करें तो अच्छा हो। मैं समझता हूं कि इससे गन्ने के दाम बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि यहां पर बहुत काफी लोगों के गिरफ्तार होने की बात कही गयी है। उन्हें बिना शर्त रिहा करने की भी मांग की गयी है। यदि सरकार की यही राय थी जो पत्र में बतायी गयी है तो मेरी समझ में नहीं आता कि शान्तिपूर्वक हड़ताल करने वाले गन्ना काश्तकारों और उनके नेताओं को गिरफ्तार करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? दो-तीन मिलों की मुझे जानकारी है। गोरखपुर में एक स्थान पर चार पांच दिन की पुरानी परचियां लिए हुए गाड़ियां खड़ी रखी गईं थीं। उनको रोक कर ट्रकों और ट्रालियों पर गन्ना लाद कर और धीरे-धीरे पेर कर बनावटी जाम बना कर दिखाया जा रहा था जिससे हड़ताल करने वालों का मारल टूटे। जब लोगों ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठायी कि यह जो ट्रकों और ट्रालियों पर गन्ना आ रहा है इससे पहले वह गन्ना तौला जाय जो चार रोज से पड़ा हुआ है तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी और प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना जैसे लोग भी थे। सिसवा बाजार में मैं स्वयं था। गोरखपुर और देवरिया के प्रमुख उद्योगपति रायबहादुर केदारनाथ की फैक्टरी के लिए ट्रालियों और ट्रकों पर गन्ना लाया जा रहा था और चार-पांच दिन से जो गाड़ियां पड़ी थीं उन्हें रोक रखा गया था। अन्याय का विरोध करने पर ८ आदमियों को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा जो और लोग प्रतिरोध कर रहे थे उन्हें पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया गया। न उनके पास भोजन था, न वस्त्र था। बीस-बीस मील घर से दूर उनको छोड़ दिया गया। यह सरकार का ऐसा काम है कि उस सिपारिश के बावजूद भी निन्दनीय है। इसके लिए इस सरकार की जितनी भर्त्सना व निन्दा की जाय वह थोड़ी है।

इस प्रस्ताव का दूसरा अंश है कि इस प्रकार गिरफ्तार किये हुए लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी भर्त्सना की जाय और उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाय। यह हड़ताल इतनी स्पान्टेनियस थी, अपने आप हुई थी, किसानों की तरफ से हुई थी कि इसमें किसी प्रकार की ज्यादती किसी हड़तालो नेता की तरफ से या और किसी की तरफ से होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए जितनी भी गिरफ्तारियां की गई हैं वह गलत की गई हैं और उनको इस सरकार को फौरन ही छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग वापस भी आ गए हैं मुचलके पर, या और तरीके से, लेकिन इस वक्त जो मुकदमें चलाये जा रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ने के विषय पर फिर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। गन्ने की कीमत का जहां सवाल आता है तो हम १९५१-५२ के सीजन को नहीं भूल सकते। वह एक ऐसा साल था जो अपना एक महत्व रखता है क्योंकि १९५१-५२ के सीजन से पहले सेंटर और गेट की कीमत एक हुआ करती थी। यह १९५१-५२ में पहली मर्तबा दो प्रकार की कीमतें हमारी केन्द्रीय सरकार ने निश्चय कीं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं इसके लिए जिस तरीके से कि उन्होंने प्रचार किया था इस सदन के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं आपके द्वारा बड़े साफ शब्दों में यह भी कहना चाहता हूं कि उस सिफारिश के करने से ही हमारी प्रान्तीय सरकार की सब जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हमको देखना पड़ेगा कि आखिर सरकार ने उसको मनवाने के लिए क्या क्या कदम उठाये, क्या क्या सरकार ने किया गन्ने के काश्तकारों के लिये, उन अठारह और बीस लाख परिवारों के लिए क्या उसने किया, जिनकी जीविका गन्ने पर निर्भर है।

मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जब केन्द्र ने उनकी बात नहीं मानी तो क्या उन्होंने यह भी कहा था कि गेट और सेंटर पर एक ही कीमत होनी चाहिए? अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो हमारे इस सदन के प्रस्ताव का यह मतलब भी था। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई और कदम उठाया इसके लिए? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं

माना है अपने पत्र में कि प्रान्त में गोलियां चलीं, प्रान्त में हर किस्म की ज्यादती किसानों के साथ हुई ? तो माननीय मुख्य मंत्री जी जब समझते थे कि हमारी मांग ठीक थी, उनको मालूम था कि किसानों की मांग ठीक थी, १ रुपया १२ आना मन मिलना चाहिए उनको, शुगर कंट्रोल बोर्ड के निश्चय के मातहत इतना उन्हें मिलना चाहिए, तो मुख्य मंत्री जी की सरकार ने क्यों उनको जेलों में बन्द किया ? मुख्य मंत्री जी के अधिकारियों ने क्यों जो पर्चियां बंटती हैं उन पर्चियों को गलत तरीके से बांटा ? क्यों मुख्य मंत्री जी के केन कमिश्नर ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ? क्यों हमको जेल में बन्द कर दिया ? क्यों उग्रसेन जी को और माननीय गेंदासिंह जी को जेल जाना पड़ा ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी की सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ज्यादा फायदा दिलाने के लिए उन मिल मालिकों से जिस तरीके से कि और प्रदेशों में ४,३१,९५,००० रुपया राज्य सरकारों ने गन्ना पैदा करने वाले किसानों को दिलवाया है। क्या हमारी सरकार इस बात का दावा कर सकती है कि उसने एक पैसा भी किसी मिल मालिक से किसी गन्ना उत्पादक को दिलाया है ? मैं जानना चाहूंगा और बतलाना चाहूंगा आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों को कि बेलमन्डी शुगर फैक्ट्री में, जिसने केवल साढ़े सात लाख मन गन्ना पेरा, रिकवरी १०.३० और वहां पर कीमत दिलाई गई ५२ रुपये टन।

हमारे प्रदेश की सरकार कोई कदम नहीं उठा सकी है। यह उनसे कह नहीं सकती है कि कुछ ज्यादा दे दो यह समझते हुए भी कि किसानों की मांग जायज है, यह समझते हुए भी कि १ रुपये ४ आने मन गन्ने पर कास्ट आफ प्रोडक्शन आ जाता है। तो फिर माननीय मुख्य मंत्री जी का एक पत्र लिख देना पाटिल साहब को, वही काफी है या नाकाफी है, यह मैं माननीय सदस्यों के ऊपर छोड़ता हूं। वह स्वयं इस बात का फैसला करें, क्या मुख्य मंत्री जी ने हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री होने के नाते अपने फरायज की पूर्ति की है या नहीं ? अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के साथ और क्या नहीं किया है ? मैं आपके द्वारा साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो हमारे पास आल्टरनेटिव मेथड थे समाप्त करने का प्रयत्न किया। जब कि हम हड़ताल की बात सोचते थे तब किसान यह सोचता था कि मिल मालिक हमको अगर ठीक पैसा नहीं देता है तो दूसरी जगह जाकर गन्ना बेच देंगे और वह ऐसा करता था। क्या उन जरियों को खत्म करने की बात इस सरकार ने नहीं की ? मैं समझता हूं कि सरकार ने उनको खत्म करने में इस बात का परिचय दिया है कि उन्हें किसानों से कोई मुहब्बत नहीं है।

सरकार को १८, २० लाख परिवारों से मुहब्बत नहीं है जैसा कि वह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार के पत्र में लिखा है कि इसलिये हड़ताल टूट गई क्योंकि किसानों की उनकी मुहब्बत का उनको अन्दाजा था और हमारी सरकार को किसानों के साथ बहुत मुहब्बत थी। मैं जानना चाहता हूं कि कई आर्डिनेंस जिस प्रकार से आल्टरनेटिव मेथड को खत्म करने के लिये निकाले गये कभी कोई आर्डिनेंस इस बात के लिये निकाला कि जो चीनी आज बाजार में खुले आम ४४, ४५ रुपये मन बिकती है वह न बिके ? क्या माननीय मुख्य मंत्री ने, जैसा कि वह अपने पत्र में कहते हैं कि फैक्टरी के आदमी मिल से चीनी ले जाकर बाजार में बेचते हैं तो उसको खत्म करने के लिये कोई प्रयत्न किया ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने कभी यह भी ध्यान रखा कि क्यों इतने अधिक दाम पर चीनी खुले खजाने बिकती है ? आज ही मैंने अखबारों में देखा कि पंजाब के एक मंत्री यह कहते हैं कि हम सिफारिश करेंगे केन्द्रीय सरकार से कि चीनी का डिकंट्रोल हो और उत्पादक को १ रुपया १४ आना मन दाम दिलाया जाय।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कीमत मुकर्रर क्यों की जाती है ? मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कीमत मुकर्रर इसलिये की जाती है कि उत्पादक को ठीक पैसा मिल जाय और साथ ही साथ जो कन्ज्यूमर है उसको ठीक कीमत पर चीनी मिल जाय। हमारे प्रदेश में क्या है ? हमारे यहां उत्पादक को ठीक पैसा नहीं मिलता है और कन्ज्यूमर को ठीक दाम पर चीनी नहीं मिलती है। जब चीनी तेज मिलती है तो क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करते हैं कि हमारे प्रदेश में भी चीनी डिकंट्रोल की जाय। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे यहां चीनी डिकंट्रोल होनी चाहिये और हमारे मुख्य मंत्री

[श्री जगवीरसिंह]

जी इस बात को सोचें। आज जिस भाव पर चीनी बिकती है उसका सारा मुनाफा हमारे मिल मालिकों की जेब में जाता है। चीनी का डिकंट्रोल हो तो कन्ज्यूमर को ज्यादा दाम पर नहीं बल्कि कम से कम दाम पर चीनी मिलेगी। मैं इन बातों का जवाब मुख्य मंत्री जी से जरूर चाहता हूं। अगर हमारे मुख्य मंत्री जी किसी तरीके से किसान को ठीक दाम दिलाने की बात सोचें तो इससे देश का लाभ होगा। आखिर क्यों नहीं मिल मालिकों पर सरकार दबाव डालती कि किसानों की हित की बात सोचें।

आज खुले बाजार ४४, ४५ रुपये मन चीनी बिकती है लेकिन किसानों के लिये जब गन्ने के दाम बढ़ाने की बात आती है तो केन्द्रीय सरकार से ज्यादा नहीं कहती? सरकार को किसानों के साथ तो बहुत हमदर्दी है। मैं एक बात यह भी कह दूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री का यही रवइया रहा, इस सरकार का यही रवइया किसानों के साथ रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब कि गांव के रहने वाले, जिनकी आमदनी घटती चली जाती है वह कोई कदम उठायेंगे। शहर के रहने वालों की आमदनी पिछले ११ वर्ष में अगर आप देखें तो आमदनी बढ़ी है घटी नहीं है, अगर किसान की हालत खराब होती चली गई तो हमारे मुख्य मंत्री जी अपने प्रदेश का बहुत अहित करेंगे। अगर सरकार गांव के रहने वाली जनता का विचार नहीं करेगी तो पता नहीं इस प्रदेश में क्या हो जाय? हम समझते हैं कि प्रदेश में भगवान् करे वह स्थिति न आवे। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं यह मांग जरूर करता हूं कि उन गन्ना उत्पादकों को, जिनको इस आन्दोलन में जो स्पोनटेनियस था जेल भेज दिया गया है, उनको तुरन्त बगैर किसी शर्त के रिहा किया जाय और किसानों को दो रुपये मन कीमत दिलाने के लिये जो तरीके हो सकें और मिल मालिकों से बात करके सरकार मनवा सके तो उस कदम के उठाने में हम मुख्य मंत्री जी को अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष वह पत्र पढ़कर सुनाया कि जिसमें उन्होंने १ रुपये १२ आने के भाव का समर्थन किया था और यहां के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए यह सिफ़ारिश की थी कि वही भाव तय किया जाय। यह सिफ़ारिश उन्होंने केन्द्रीय सरकार से की थी। उस पत्र के पढ़ने के बाद मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसा मेरे दल के नेता ने भी कहा था, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उसकी बखूबी पैरवी किये होते तो शायद यह मसला आगे बढ़ सकता था और हम इन १८ लाख गन्ना किसानों को उनका हक दिलाने में कुछ मदद कर सकते थे। यदि वह न भी होता तो भी ये किसान, ये गन्ना उत्पादक जान सकते थे कि सरकार ने हमारे हक के लिये पैरवी तो की है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जिस समय यह प्रस्ताव यहां आया था उस समय सोशलिस्ट पार्टी की ओर से २ रुपये मन गन्ना तथा ३२ रुपये मन चीनी का प्रस्ताव आया था। यही नहीं, १५ दिसम्बर से पश्चिमी जिलों में, मेरठ में बुलन्दशहर में और कुछ और जिलों में जो जबरदस्त हड़ताल हुई सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, उसने भी इन चीनी मिल मालिकों को हिला दिया। २ रुपये मन के भाव का सुझाव सोशलिस्ट पार्टी का था। सदन ने १ रुपये १२ आने मन के भाव का प्रस्ताव पास किया। ज्वाइंट बोर्ड ने भी इसी भाव का प्रस्ताव पास किया, बिहार विधान सभा ने १ रुपये १२ आने का प्रस्ताव पास किया, उसके बाद मुख्य मंत्री जी ने सिफ़ारिश भी की, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसको उलट दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं जानते कि इसी लखनऊ में ४५ रुपये से लेकर ६० रुपये तक चीनी बिकी है और चीनी उपभोक्ता लूटे गये हैं। यह पैसा किस की पाकेट में गया है? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र की भाषा में बतलाना चाहता हूं कि यह पैसा या तो चीनी मिल मालिक की पाकेट में गया है या उनके एजेन्टों की पाकेट में गया है। तो यह प्रान्तीय सरकार इस लूट को समाप्त कर सकती थी।

दूसरी चीज मैं उनके सामने यह रखना चाहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि केन सेस का २ करोड़ और ३९ या ४९ लाख रुपया अभी ४५ चीनी मिल

मालिकों पर बकाया है। १ करोड़ से ज्यादा रुपया गन्ना उत्पादकों का इन पर बकाया है। देवरिया में ऐसी चीनी मिलें हैं कि जिन पर ७, ८ लाख रुपया इन किसानों का बकाया है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी की सरकार ने उनको पूरी छूट दे रखी है। उनको आजादी है लूटने के लिये और इस प्रदेश के १८ लाख गन्ना उत्पादक लूटे जा रहे हैं और यही औचित्य है कि इस प्रदेश का गन्ना उत्पादक हर वर्ष लड़ता है। इसी संघर्ष में फ़ेकू और चन्द्र शेखर शहीद हुए और नतीजा यह है कि सरदार नगर के किसान २ रुपये के भाव के लिये लड़ रहे हैं और बहादुरी से लड़ रहे हैं और जहां एक पार्टी द्वारा आन्दोलन का नेतृत्व किया गया था वहां सरदारनगर और सरैया क्षेत्र में वह आन्दोलन एक जन आन्दोलन का रूप ले रहा है। मैं आज की बात कहता हूं और एक मिल का उदाहरण देना चाहता हूं।

इस प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को क्या लाभ है ? शायद माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र पढ़ देने से सदस्यगण समझ जायं कि यहां की सरकार द्वारा तो एक रुपये बारह आने के भाव का समर्थन किया गया, कोशिश तो की गयी, नहीं हुआ तो क्या किया जाय ? एक भटनी चीनी मिल है। वह ९ नवम्बर से चलती है और ७ दिसम्बर के अन्दर १ लाख २३ हजार मन गन्ना भटनी की केन यूनियन ने सप्लाई किया। २ लाख के करीब उसका दाम हुआ और जब मैंने उसके दफ्तर में जाकर देखा तो पाया कि ४०,००० रुपया गन्ने का दाम मिला है। १ लाख ६० हजार रुपया किसानों को नहीं मिला। उधर के जिलों में कहीं भी किसानों का रुपया नहीं मिला है और उनका पैसा मिल वालों के पास है। केन यूनियनें उसके सूद के लिये लड़ें यह कायदा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों न सरकार उनको प्रोत्साहित कर के सूद दिलावे। यह काम तो प्रादेशिक सरकार ही कर सकती है। तो हम तो देखते हैं कि प्रादेशिक सरकार की जानकारी में चीनी मिल मालिक फल फूल रहे हैं और हम लूटे जा रहे हैं चाहे उपभोक्ता के रूप में हों अथवा गन्ना काश्तकारों के रूप में और हम से कहा जाता है कि हम पुरानी बातों को भूल जायं।

एक सभा सचिव हैं हमारी सरकार के, वे गोरखपुर के रहने वाले हैं। वह सरैया क्षेत्र में गये और मोटर से घूम-घूम कर खेतों में जा जा करके गन्ना कटवा रहे थे और गन्ना उत्पादकों की हड़ताल तुड़वा रहे थे। आपके माननीय सभा सचिव वहां पर तशरीफ़ रख रहे हैं और उन्होंने हड़ताल तुड़वाने की कोशिश की। कम से कम से इस सरकार के सभा सचिव हैं, उनको, जो कुछ उन्होंने किया वह नहीं करना चाहिये था, यह बड़े ही अफ़सोस की बात है। उनको हर बात की पूरी जानकारी होती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब गन्ना उत्पादक यहां पर लूटा जायेगा तो उसके लिये जिम्मेदारी किसकी है, क्या यह सरकार उसके लिये जिम्मेदार नहीं है। अगर हम खयाल नहीं करेंगे तो फिर संघर्ष निश्चय ही होगा।

अब कीमत का सवाल जो है, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कीमत को फिक्स करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है, और प्रदेशीय सरकार उसके लिये कोशिश करती है भाव को बढ़ाने के लिये और केन्द्रीय सरकार उसको नहीं मानती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे गेंदासिंह जी के साथ चलने के लिये तैयार हैं, क्या वे हम जो कार्य उसके लिये करें उसमें हमारा साथ देने के लिये तैयार हैं ? क्या माननीय मंत्री जी हमारे साथ संघर्ष करने के लिये तैयार हैं ? अगर प्रदेशीय सरकार यह समझती है कि दो रुपये मन का भाव होना चाहिये और यह उचित है तो कोई वजह नहीं है कि वह उसको केन्द्रीय सरकार से न दिला सके। अगर वह नहीं दिला पाती है तो हमारा साथ दे। हमें उसके लिये स्ट्राइक करने दे। हमको यह अधिकार दे कि हम उसको मनवाने के लिये उचित कदम उठायें। आप देखें, श्रीमन्, कि हर तरह से गन्ना किसान को ही नुकसान पहुंचती है। क्या जब थापर अपनी चीनी भेजता है बिरला के पास, कलकत्ते में, तो ढुलाई का दाम थापर को नहीं देना पड़ता है, उसका दाम बिरला को ही देना पड़ता है ? इसके विपरीत यहां पर क्या होता है ? यहां पर जब किसान अपना गन्ना लेकर जाता है तो कांटे पर भाव कुछ रहता है और मिल गेट पर भाव कुछ रहता है और फिर यह कहा जाता है कि ढुलाई का दाम भी वही किसान दे। उसका भी बोझ उसी पर पड़ता है। सरकार कहती है उसकी

[श्री उग्रसेन]

ढुलाई भी दे दो। अजीब तमाशा सा होता है। वह किसान बेचारा अपना मुर्दा फूंकने के लिये श्मशान पर ले जाये, तो उसी को श्मशान का कर भी चुकाना पड़े, क्योंकि न दे तो उसको मुर्दा नहीं फूंकने देंगे। तो इस तरह से हम कफ़न का दाम भी देते रहें और श्मशान का कर भी। यह कहां का न्याय है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और विचार करना चाहिये

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे एक मिनट और दिया जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। श्रीमन्, जब इसके लिये संघर्ष हुआ तो सरकार ने खंडसारी तथा ७ बैलों द्वारा चालित कोल्हुओं पर टैक्स लगाने के लिये एक आर्डिनेंस ईशू कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर पूर्व वालों का गन्ना कोल्हुओं की तरफ़ डाइवर्ट कर दिया जाय तो इतनी परेशानी ही न रहे।

मैं, श्रीमन्, एक ही बात और कहना चाहता हूं। वह बात यह है कि जिस समय मेरी गिरफ्तारी की गया था, मेरे साथ और भी ५ सदस्य थे। २० तारीख को १२ बजे हमको पकड़ा जाता है; इसके लिये एक चिट्ठी सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल को एस० डी० एम० सलीमपुर ने लिखी कि "They have been taken into custody in connection with the cane agitation. Please admit them in the Jail." तो बिना वारन्ट के हम लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। हमको २२ तारीख को १२ बजे पकड़ कर जेल भेजा जाता है, जेल के फाटक पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां कहा जाता है कि वारन्ट नहीं है, हम नहीं लेंगे। फिर वहां फाटक खोल दिया जाता है और हम फाटक के अन्दर चले जाते हैं। २२ तारीख को जब जिलाधीश आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमको बिना वारन्ट गिरफ्तार कर लिया गया है। तब २२ तारीख को अपरान्ह में वारन्ट ईशू किया जाता है। २०, २१ और २२ तारीख को हम जेल में रहते हैं। बिना वारन्ट के जेल में रहना पड़ता है और गिरफ्तारियां हो जाती हैं। हम लोगों को पकड़ कर जेल भेजा जाता है, गन्ने की गाड़ियां पकड़ कर जब उनका गन्ना ले लिया जाता है तो फिर लोगों को छोड़ दिया जाता है। इस तरह की बातें होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम इन बातों की जांच कराने की कोशिश करें। उनका गन्ना कटवाया गया। जब गन्ने की हड़ताल खत्म हुई तब उनको छोड़ दिया। सरकार ने ऐसा क्यों किया, यह मैं जानना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इधर जो अफसरों ने अवैधानिक कार्य किये हैं उसकी जांच करावें और मुझे उम्मीद है कि अगर जांच करावेंगे तो उनको सारी बातें अपने आप मालूम हो जायेंगी। जहां तक गन्ना किसान का सम्बन्ध है, वह तो जब तक २ रुपये मन गन्ने का भाव और ३२ रुपये मन चीनी का दाम नहीं पावेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। इस दफा तो जैसी लड़ाई हुई है, हुई ही है लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगली लड़ाई बहुत घनघोर रहेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। इन शब्दों के साथ, मैं जो नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा हुई उसका समर्थन करते हुए इसकी अहमियत की तरफ मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदासिंह ने नियम दफा ५३ के अन्दर जो चर्चा उठाने का विषय रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जहां तक गन्ने का दाम बढ़ाने की बात है, इस सदन ने १ रुपये १२ आने मन का जो प्रस्ताव पास किया था उस पर मुख्य मंत्री जी ने जो केन्द्रीय सरकार को लिखा है उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और यदि उन्होंने यह बात पहले स्पष्ट कह दी होती तो शायद आज इस प्रस्ताव को इस ढंग से लाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ

जब गन्ना-किसान गन्ने का दाम बढ़ाने की बात कहता है और कहता है कि हम उस वक्त तक गन्ना मिलों पर नहीं ले जायेंगे जब तक गन्ने का दाम २ रु० मन नहीं हो जाता, तो इस सरकार के अधिकारी और सरकार के जिम्मेदार लोग हड़ताल तुड़वाते हैं। इसका क्या कारण है? एक तरफ तो सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है और दूसरी तरफ जब गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की जाती है तो हड़ताल को सरकार की ओर से तुड़वाया जाता है, और उसको तुड़वाने के लिये क्या-क्या हथकंडे नहीं इस्तेमाल किये जाते हैं? केन यूनियनों का सहारा लिया जाता है और उन पर अंकुश लगाया जाता है, जिससे केन यूनियनें मजबूर होकर हड़ताल तोड़ने के लिए सभी उपाय इस्तेमाल कर डालती हैं और साथ ही इतनी तादाद में पुरजियां काटी जाती हैं जिससे हड़ताल न चलने पावे। इतना ही नहीं, वे पुरजियां इतनी तादाद में कट जाती हैं कि १५, १५ दिन तक पेरने के लिए गन्ना जमा हो जाता है, जैसा कि आज भी जाकर देखा जाय तो उतनी तादाद में गन्ने की गाड़ियां इकट्ठी हो गई हैं कि मिलों के गेट्स पर जाम लगा हुआ है। इतनी काफी पुर्जियां दे दी गयी हैं, जितनी पहले कभी नहीं दी गई थीं। पहले तो यह नियम रखा गया था कि पहले पकने वाला गन्ना पहले लिया जायगा और बाद में पकने वाला गन्ना बाद को लिया जायेगा, लेकिन जब हड़ताल हुई तो जो पहले पकने वाले गन्ने न थे उनकी भी पुर्जी दे दी गई कि वह गन्ना लिया जायगा और जब हड़ताल खत्म हुई तो कहा गया कि यह गन्ना नहीं लिया जायगा। इसके बाद इतना ही नहीं, मिल अधिकारी गांवों में जाकर गन्ना किसानों से यह कहने लगे कि अब हड़ताल टूट गई, अब तुम लोग बाद में पकने वाला गन्ना न लाओ और मिल पर जो गन्ना देने के लिए लाये हो उस अपने गन्ने को वापस ले जाओ, तुम्हारा गन्ना अब नहीं लिया जावेगा। तब फिर किसानों ने इस ईशू पर हड़ताल की कि हमारा पीछे पकने वाला गन्ना भी लिया जाना चाहिये और जब तक उनका गन्ना नहीं लिया गया तब तक हड़ताल चलती रही। इस तरह से एक तरफ तो उनको कहा जाता है कि गन्ना लाओ और जब वह गन्ना लाता है तो उसे कह दिया जाता है कि अब इस किस्म का गन्ना नहीं लिया जायगा। इतना ही नहीं, हड़ताल के वक्त इनके सारे नियम समाप्त हो जाते हैं।

अभी इसी सदन में माननीय उग्रसेन जी ने बताया कि सरकारी पक्ष के एक जिम्मेदार जो सभा सचिव हैं उन्होंने गन्ना हड़ताल तुड़वाने के लिए काफी दौरे भी किये। वह हमारे यहां से ही आते हैं। मुझे अफसोस है कि मैं भी उनके सम्बन्ध में कुछ कह रहा हूं। मगर मजबूरी है, कहना नहीं चाहता था क्योंकि वह हमारे दोस्त हैं, लेकिन मजबूर होकर कह रहा हूं कि जिस वक्त वह मेरे यहां यानी वह घुघली पहुंचे तो पहले सीधे मिल में गये और फिर उन्होंने गांव-गांव में दौरा किया। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ और माननीय सदस्य भी थे। तो एक तरफ यह भी होता है कि सरकार के जिम्मेदार आदमी गांव-गांव दौड़ते हैं और गलत प्रचार करते हैं कि गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा, तुम हड़ताल क्यों करते हो, तुम्हारा गन्ना सूख जायेगा। दूसरी तरफ जो गिरफ्तारियां की गईं उनके सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह गिरफ्तारियां वैधानिक तरीके से नहीं की गईं। यह तो किसानों का आन्दोलन था और उन्होंने अपनी मांगों के लिये हड़ताल की। उसमें किसी नेता की अपनी कोई साजिश नहीं थी और न किसी नियम का उल्लंघन ही किया गया था जिसकी बेसिस पर गिरफ्तारियां की गईं। जहां तक मेरी गिरफ्तारी का संबंध है, मैं भी घुघली से गिरफ्तार किया गया था। मुझे एक सब-इन्सपेक्टर ने गिरफ्तार करना चाहा, उन्होंने मुझ से कहा कि मैं आपको गिरफ्तार करता हूं तो मैंने कहा कि तुम पहले वारन्ट दिखलाओ नहीं तो तुम खुद फंस जावोगे। इस पर वह चला गया और जाकर एस० डी० एम० को टेलीफोन किया। एस० डी० एम० ने कहा कि मैं आऊंगा तब गिरफ्तारी होगी। जहां तक मेरी जानकारी है, एस० डी० एम० साहब आये और वह डाकखाने में बैठे रहे और शाम को ६ बजे जाकर मुझे गिरफ्तार किया गया और जो किसान गाड़ी नहीं ले जा रहे थे उनको धमका कर जबरदस्ती गाड़ी ले जाकर मिल में

[श्री अमरनाथ]

हड़ताल तुड़वाने की कोशिश की गई। मुझे गिरफ्तार करके जिला जेल भेजा गया; रिमान्ड की और पेशी की डेट रखी गई लेकिन उस डेट पर हमको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया और इल्लीगल डिटेन्शन में रखा गया, इसके हमारे पास सबूत भी हैं। जब हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो फिर और लोगों के साथ क्या व्यवहार होता होगा, इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। यहां पर के हमारे और भाइयों के साथ जो बातें हुई हैं उनको भी उन्होंने साफ तरीके से कहा है।

जहां तक किसानों के हित का सवाल है, गन्ने का दाम बढ़ाने का सवाल है, मैं मानता हूं कि सरकार ने सिफारिश की दाम बढ़ाने के लिये; लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि यहां पर ५ आने मन छूट दी गई, एक्साइज ड्यूटी छोड़ी गई तो क्यों सरकार ने उसका विरोध नहीं किया और यह कोशिश क्यों नहीं की कि गन्ने का दाम भी बढ़ना चाहिये और उसी हिसाब से बढ़ना चाहिये? अगले साल ३६ रुपये मन चीनी बेचने का सरकारी रेट था लेकिन ५० रुपये मन चीनी क्यों बिकी और इसको सरकार ने क्यों नहीं रोका, इस सम्बन्ध में सरकार क्यों चुप बैठी रही? क्या प्रादेशिक सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी? एक ओर तो हड़ताल तुड़वाने के लिये मिल मालिकों के हित की ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब किसान अपने गन्ने का उचित दाम मांगता है तो उसको जेल भेजा जाता है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि सदन का जो १ रु० १२ आने का प्रस्ताव था उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री ने एक पत्र लिखा, लेकिन अगर वह १ रु० १२ आने मन करना चाहते और केन्द्रीय सरकार को मजबूर करते तो मजबूरन उनको यह दाम मानने पड़ते।

जहां तक पाटिल साहब के कहने के बात है, जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि गन्ने का दाम न बढ़े; बजाय इसके वह लोग चाहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में छूट मिले, रिबेट दी जाय गन्ने के दाम पर तब फिर जा कर के चीनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। उनकी दलील थी कि चीनी की कमी हो गई है इसी से चीनी ज्यादा बनने लगेगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीनी के दाम बढ़ गये। एक दलील तो यह है, और दूसरी तरफ जब किसानों की ओर से कहा जाता है कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाय तो गन्ना मिलों को ज्यादा मिलेगा, और चीनी ज्यादा बन सकेगी तो ध्यान नहीं दिया जाता। बल्कि सरकार दूसरी तरफ मिल मालिकों का हित करने के लिये गुड़ और राब पर प्रतिबन्ध लगाती है और लाइसेंस की व्यवस्था करने जा रही है और गन्ना उपकर मांगा जा रहा है ताकि गुड़ और राब न बन सके। मैं तो कहता हूं इसके बजाय अगर गन्ने का दाम बढ़ाया जाय और चीनी का दाम घटाया जाय तो निश्चित है कि काफी तादाद में किसान गुड़ और राब न बनायेंगे और अपना गन्ना मिल को देंगे। यही वजह है कि जब किसान को पूरी कीमत नहीं मिलेगी तो वह अपना गन्ना मिल को नहीं देगा।

हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं जहां पर हमेशा किसान सूखा और बाढ़ से तबाह रहता है। वहां पर गन्ने की एक ऐसी फसल होती है जिससे किसानों की सारी जरूरतें पूरी होती हैं, उनको कर्जा देना होता है, तकावी देनी होती है, सरकार की मालगुजारी देनी होती है, खाने कपड़े का प्रबन्ध करना होता है। उनके पास गन्ना ही एक ऐसी चीज है जिस बेच कर अपनी तमाम जरूरतों को रफा कर सकते हैं। इसलिये अगर सरकार किसानों की हमदर्द है और उनकी भलाई चाहती है तो उसे गन्ने का दाम बढ़ाने के लिये तत्काल कोशिश करनी चाहिये और १ रुपये १२ आने का जो इस सदन का प्रस्ताव था कम से कम उसे मंजूर कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रयत्न करना चाहिये और साथ ही अगर बन पड़े तो २ रु० मन दिलाने की भी कोशिश करनी चाहिये। इन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और श्री गेंदासिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण--अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के ऊपर २ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है। यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भी हो जाता है और एक पब्लिक कैरेक्टर की भांति भी सदन में वह डिसकस हो सकता है। वह इस समय यहां बैठे हुए हैं आप उनसे स्पष्टीकरण करा लें कि क्या उन्होंने हड़ताल तुड़वाने में वे अनियमिततायें बरतीं, जिनका कि माननीय सदस्यों ने जिक्र किया।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है। अगर वह एक्सप्लेनेशन स्वयं देना चाहें तो दे सकते हैं।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो गन्ने के दाम बढ़ाने के विषय में चर्चा प्रस्तुत की है मैं उस संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद सरकार की पैनी गिद्ध-दृष्टि उन लोगों पर पहुंच गयी जो खांडसारी के लिये गन्ना देते थे। अब तक जो चक्कर केन फेडरेशन का पर्चियों के लिये चलता था वह वहां भी चलेगा। जो काम हड़ताल तुड़वाने में केन डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से किया गया वह वहां भी किया जायगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री पुराने समाजवादी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। मालूम नहीं उनका समाजवाद कहां चला गया? चीनी का व्यवसाय इतना महत्व का है जिससे १८ लाख किसान परिवारों का ताल्लुक है। वह अपने खून पसीने से गन्ना पैदा करते हैं। उनको क्या-क्या कठिनाई आती है, यह उनको मालूम होना चाहिये। लेकिन जब-जब यह प्रश्न सदन के सामने आया तब तब सरकार की ओर से उसकी अवहेलना की गयी। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं लेकिन मैं तो उस चिट्ठी का मतलब केवल यही समझता हूं कि शुरू में तो उन्होंने सभी कुछ लिखा लकिन बाद में लिख दिया कि आप साल भर पीछे दाम निश्चित करते हैं, चाहें तो इस समय रहने दीजिये, अगले साल हो जायगा। इस तरह से इस सदन की अवहेलना ही की गयी।

यह सही है कि पहले की अपेक्षा गन्ने का उत्पादन व्यय भी बढ़ा है। जो २।। से ४ रुपये मन था वह १० से १२ रुपये मन तक हो गया है लेकिन गन्ने का दाम ज्यों का त्यों है। गन्ने का दाम १ रु० ७ आ० मन जब आता है तो चीनी का दाम ३६ रुपया मन था। अब आपने ३ आना मन गन्ने का दाम बढ़ा दिया और चीनी का दाम १.८७ रु० मन बढ़ा दिया। इस प्रकार से गन्ने के दामों में वास्तविक रूप में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। यह निर्णय केवल मिल मालिकों के ही पक्ष में किया गया है, न कि किसानों के पक्ष में। मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो केन्द्रीय खाद्य मंत्री, श्री पाटिल, ने दिया था कि जो प्रोत्साहन हम मिल मालिकों को उत्पादन छूट देकर दे रहे हैं, उसका प्रभाव गन्ने के दामों पर भी पड़ेगा और जो दाम किसानों को मिल रहा है उससे अधिक पैसे उनको मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण दिया जाय कि किस प्रकार से जो दाम निर्धारित हो गया है उससे अधिक दाम किसानों को मिलेगा।

एक बार मैंने प्रश्न किया था और उसके जवाब में यह बताया गया था कि सरकारी फार्म में १.१५ रुपया उत्पादन खर्च होता है जो कि एक एकड़ में ५०० मन गन्ना पैदा करते हैं। किसान उससे कम ही गन्ना पैदा करता है। १ रु० ४ आना से कम उसका परता किसी भी तरह से नहीं पड़ता। इसलिये जो टक्स आप लगाते हैं उसको मिलाकर १ रु० ५ आने से कम प्रति मन उसको नहीं पड़ता। १ रु० ५ आने मन सरकार गन्ने के उत्पादन पर गन्ने के व्यवसाय पर टैक्स लगावे और गन्ना किसान इस तरह की कीमत पावें तो किसानों की रीढ़ सीधी नहीं रह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

सकती है। यह निश्चित है कि सरकार की इस नीति से और पूंजीपतियों के इस रवैये से समाज तबाह होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा लेकिन देवरिया जिले के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं कि देवरिया जिले को सालाना ४० लाख रु० केवल सरकार को टैक्स देना पड़ता है। साढ़े १२ साल के लगान के बराबर सवा ५ करोड़ से अधिक टैक्स देते हैं गन्ना व्यवसाय पर; और आज गन्ना उत्पादकों के प्रति जो सरकार का रुख है वह जाहिर है। जैसा कि उग्रसेन जी ने कहा कि जो गन्ना उत्पादक हैं, वे अपने हक के लिये लड़ेंगे सरकारी नियन्त्रण के बावजूद, हमारे इस सदन के मेम्बरों के बावजूद, और इन गन्ना सोसाइटियों के पर्चियां बांटने के बावजूद, क्योंकि वे भी धीरे-धीरे सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ सरकार किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि यह सरकार गन्ना उत्पादकों को अपनी सही सन्तान मानने में हिचकती है और उनके साथ मैंमाऊत पुत्र की तरह से व्यवहार करती है और मिल मालिकों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आखिरकार जब चीनी के दाम में बढ़ोत्तरी हुई तो उसी अनुपात में गन्ने का दाम भी बढ़ना चाहिये था।

हमारे यहां गन्ने का रेट १ रु० ७ आ० और १ रु० १० आ० मन है। फिर जब उस गन्ने से चीनी बनती है वह अधिक रेट पर बिके और उपभोक्ताओं को अधिक पैसे देकर खरीदना पड़े तो इस प्रकार से जो आर्थिक स्थिति का ह्रास होता है वह गन्ना उत्पादकों के लिये उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आखिर आपके सामने नक्शा क्या है। हम तो चाहते हैं कि चीनी का व्यवसाय जिन्दा रहे, गन्ना उत्पादक भी जिन्दा रहें। मिल मालिकों का जो हौवा हमारे सामने खड़ा किया जाता है कि वे यह कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर नियन्त्रण सरकार लादती जायगी तो हम अपने मिल को हटाकर दूसरे क्षेत्र में चले जायंगे, मैं कह सकता हूं कि अगर वे चले जायेंगे, सरकार चली जायगी तो भी गन्ना उत्पादक रहेंगे, गन्ना व्यवसाय रहेगा, चीनी व्यवसाय रहेगा। ऐसा मेरा विश्वास है। यह ऐसा व्यवसाय है जो खत्म होने वाला नहीं है।

मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि गन्ने का दाम ३ आने फी मन बढ़ा तो उसी अनुपात में चीनी का दाम बढ़े। इसके लिये आप एक अनुपात तय कर दें। जब पुराने तरीके से कोल्हुओं के जरिये गन्ना पेरा जाता था तब किसानों को १०० रु० में २६ रु० तो भाड़े के रूप में देना पड़ता था और ७४ रु० उसे प्राप्त होता था, जबकि मिल में गन्ना देने पर किसानों को १०० रु० में ३३ रु० ही मिलता है और ६६, ६७ रु० भाड़ा, टैक्स आदि के रूप में दे देना पड़ता है। इसलिये मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि इसका कोई न कोई अनुपात तय हो जाना चाहिये जिसके आधार पर इनका दाम तय हो। मेरी तो यह मांग है कि कम से कम किसान को ५० फी सदी तो मिलना ही चाहिये, उससे कम उसे किसी हालत में भी न मिले।

साथ ही सरकार से मुझे यह भी निवेदन करना है कि पारसाल गन्ने का दाम १ रु० ७ आ० मन था और रिकवरी भी ज्यादा थी तथा ज्यादा अवधि तक मिलें भी चलीं तो उसका जो बोनस है वह किसानों को भी मिलना चाहिये। आप इस बात को याद रखें कि कोई भी फैक्टरी १२० दिन से कम नहीं चली है। बल्कि ज्यादा दिनों तक ही चली है और साढ़े ९ फी सदी से ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो ऐसी हालत में किसानों का जो पुराना रुपया है वह मिलना चाहिये और मैं चाहता हूं कि सरकार बतलावें कि वह किस तरह से उनको वह रुपया दिलाना चाहती है। यही मेरा निवेदन है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर विचार करें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो विषय प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पत्र पढ़कर सुनाया है उससे हमें खुशी तो बहुत हुई है और यह जानकर कि जो भावना हम कई सालों से सदन में रखते चले आये हैं उस भावना को हमारे

मुख्य मंत्री जी भी मन में रखते हैं लेकिन यह आश्चर्य होता है कि जब हम देखते हैं कि भाव को बढ़ाने की जायज मांग लेकर काश्तकार तैयार होता है तो सरकारी पक्ष की तरफ से और उसके कर्मचारियों और उसके अधिकारियों की तरफ से अव्यवहारिक व्यवहार होने लग जाता है, यह देख कर हमें आश्चर्य और दुख होता है। अगर दिल से माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह मांग की गई है तो यह पोल कहां है कि उसी चीज की माननीय मुख्य मंत्री जी मांग करते हैं सेन्टर से और वही मांग काश्तकार सेन्टर से करता है ? तो काश्तकार के प्रति ऐसा दुरव्यवहार क्यों होने लगता है ? मुझे लगता है कि सरकार के उच्च अधिकारियों ने माननीय मुख्य मंत्री जी की भावना को जानकर पत्र तो ऐसा भिजवा दिया लेकिन उनकी इच्छा ऐसी नहीं थी। अगर इच्छा होती तो दुनिया की कोई ताकत भाव को बढ़ाने से नहीं रोक सकती थी, यहां की और बिहार की विधान सभाओं ने प्रस्ताव पास किये और चीनी बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका समर्थन किया, तो सेन्टर की क्या हस्ती थी कि वह इन सब बातों को अवहेलित करे ?

एक दो किसान की बात नहीं थी, यह २० लाख गन्ना किसानों का मामला था, अगर सरकार उनकी उपेक्षा करे तो यह बहुत ही दुख की बात है। इस तरह से किसानों की मांग को ठुकराया जाता है और मिल मालिकों की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कराई जा रही हो, यह बात हमारे दिल को दुखाती है। मैं भी फरेंदा मिल में था और १८ तारीख को माननीय डिप्टी स्पीकर साहब भी वहां थे और श्री शिब्बन लाल जी सक्सेना भी वहां थे, हम लोग १२ बजे मिल में पहुंचे थे। हमने देखा कि कांटे पर गन्ना की गाड़ियां नहीं तुल रही थीं और वहां के क्लर्क कुर्सियां जमाये बाहर बैठे थे, उनसे पूछा तो बताया गया कि बोगियां व ट्रक तुल रही हैं और डोंगे खाली नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकारी कानून है कि दस घंटे से ज्यादा गन्ने वालों को नहीं रोका जा सकता लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि सरकार की संगोनों के नीचे गन्ने की गाड़ियां रोकी जाती हैं। क्या यह शर्म का विषय नहीं है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए १४ तारीख से २० तारीख तक के कार्यों की ओर ले जाना चाहता हूं यदि वह इसकी जांच करावें तो वस्तुस्थिति का सही पता चल जाए। मिलों में गन्ना किसानों को १४ से २० तारीख तक बराबर स्पेशल पुर्जी दी गई हैं। क्या कोई जांच केन कमिश्नर द्वारा C. D. O. विभाग की कराई गई कि ऐसा क्यों हुआ ? न मालूम कितना पेट्रोल इस विभाग द्वारा फूंका गया। पुरन्दरपुर पुलिस स्टेशन के थानेदार ५ दिन तक बराबर आनन्दपुर नगर शुगर मिल में अपने दोनों नायबों के साथ पड़े रहे; उनकी डायरी देखी जा सकती है कि वह उन दिनों थाने को खाली छोड़कर वहीं पर मौजूद रहे हैं। जनता चाहे उनके पीछे लुटती या उनका कुछ भी होता।

ए० सी० डी० ओ० की रात दिन मोटरें दौड़ी हैं और किसानों को गन्ना हड़ताल तुड़वाने के लिए बराबर बहकाया जाता रहा है कि गन्ने का भाव बढ़ेगा, तो जैसे पहले आपको दिलाया गया था उसी तरह से अब भी दिलाया जायगा। कहीं कहीं-कहा गया कि गन्ना ले चलो, भाव २ रुपए का हो गया, जब सब को मिलेगा तो तुम को भी मिल जायगा। इस तरह से निरीह और भोले किसानों के साथ खिलवाड़ की गई। श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह पत्र जरूर गया लेकिन मेरा हृदय कहता है कि कहीं न कहीं इसमें पोल है जरूर। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पता चलायें कि हड़ताल तुड़वाने में यह गैरकानूनी कार्यवाही क्यों की गई। मैं इसे जेल के अन्दर की बताऊं या मिल के अन्दर की बात बताऊं ? वह मिल एक जेल बना हुआ था। चारों तरफ पुलिस का पहरा था। हम लोग अन्दर गये। गाड़ी वालों ने पुर्जियां दिखाईं। तहसीलदार को बुलाकर हमने कहा कि गाड़ियां क्यों रुकी हैं। किसानों ने उस एक बोगी को जो डोंगे पर गिराई जा रही थी उसे ठेलकर बाहर निकाल दिया और गाड़ियां तुलनी शुरू हुईं। १२ बजे दिन से २ बजे रात तक हमने गाड़ियां तुलवाईं। ६०० गाड़ियां तुलवाई गईं।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

श्रीमन्, चार बजे दिन को हमारा वारंट बन चुका था, तीनों आदमियों के, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमें दिन को गिरफ्तार करें क्योंकि हजारों काश्तकार वहां थे, उन्हें डर था कि झगड़ा होगा। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब सो रहे थे, एम० पी० साहब सो रहे थे। मेरे पास बिस्तर नहीं था इसलिये बाहर दुकान पर सोया हुआ था। तीन बजे रात को वे लोग गिरफ्तार कर लिये गये। मैं सुबह उठा तो तहसीलदार ने कहा कि तुम्हारे साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया, तुम्हारा भी वारन्ट है। मैंने कहा कि मुझे भी भेज दो। पता नहीं कि डी० एम० का १२ बजे फ़ोन आया या क्या हुआ कि हमारा वारन्ट रद्द किया गया। फिर हम लोगों को हटाया जाता है, बोगियां तोली जाती हैं और बैलगाड़ियों का तोलना रोक दिया जाता है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो काश्तकार और कार्यकर्ता गिरफ्तार करके बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस मील पर ले जाकर छोड़े गये उनके बारे में क्यों नहीं जांच कराते हैं। कौन सा कानून था जिसके मुताबिक मोटरों पर ले जाकर उन्हें दूर छोड़ा गया? क्यों वैगन तोले जाते थे और गाड़ियां नहीं तोली जाती थी? क्यों इतनी-इतनी देर तक गाड़ियां रोकी जा सकती हैं? जिन्होंने ये सब गलतियां की हैं उन्हें सजा दी जाय। तब साबित होगा कि मुख्य मंत्री जी किसानों से हमदर्दी रखते हैं और गन्ना का भाव बढ़ाना चाहते हैं। वह बतावें कि कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करें कि भाव बढ़ाए जायं। हमारी सर्वसम्मति से पास की हुई चीज को सेन्टर ने नहीं माना। मुख्य मंत्री जी के लिखने पर भी उन्होंने नहीं माना और वहां के मंत्रिगण अखबारों में कहते हैं कि हम लोग प्रान्तीय सरकार से पूछकर करते हैं। तो यह मामला क्या है? मैं बड़ी नम्रता के साथ मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं है। २० लाख किसानों का इससे संबंध है। किसान अपना गन्ना खंडसारी में दे देते थे और कोल्हू पर ले जाते थे; उस पर भी सरकार ने प्रतिबन्ध लगाना शुरू कर दिया है। मैं यही कहूंगा कि उन्हें बांधा जाता है। आज तैयाल की गाड़ियों के लिये मिल वाले दो आने और तीन आने मन दाम ज्यादा देते हैं और उन्हें लेते हैं; तो हमारे किसानों ने क्या खता की है? महज यही कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर उन्हें सत्ता सौंप दी है? मान्यवर, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर बड़े ध्यान से सोचें और गन्ने का भाव बढ़ावें एवं इस संबंध में जितनी गिरफ्तारियां नाजायज तरीके से हुई हैं उनकी जांच करायें, अधिकारियों को सजा दें और जो मुकदमें चल रहे हैं उनको खत्म करें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, बहुत उठक बैठक के बाद बड़ी मेहरबानी हुई कि आपकी नजर मुझ पर पड़ी . . . .

श्री अधिष्ठाता—दो घंटे में डिबेट खत्म होनी है। इसलिये आप पांच मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, सुबह की बात याद आती है। चीनी कम्युनिस्ट सरकार आक्रान्ता है हिन्दुस्तान पर और चीनी मिल मालिक आक्रान्ता है किसान पर। कुछ ऐसी बात हो गई कि वह आक्रान्ता है और यह भी आक्रान्ता है। इन्हें हम किसी आक्रान्ता से कम नहीं समझते हैं। इनके हमले पर हमले सदा से होते चले आये हैं और किसान का ही कलेजा है जो सह रहा है। मुख्य मंत्री जी ने अभी जो चिट्ठी पढ़ी जो चाहता है कि हम उनको बधाई दें और धन्यवाद भी। मगर कुछ तबियत में संकोच पैदा होता है इसलिये कि हम जब देखते हैं कि सारे देश की ५२ प्रतिशत चीनी पैदा करते हैं और दाम पाते हैं १ रु० १० आना मन गेट पर, आउट स्टेशन पर तो १ रु० ८ आने मन ही मिलता है, लेकिन बम्बई में तो ऐसी बात है कि वहां के मुख्य मंत्री हमारे यहां के मुख्य मंत्री से ज्यादा तन्दुरुस्त हैं इसलिये उनकी बात केन्द्र मान लेता है, वहां गन्ना का दाम

५२ रुपया से ५६ रुपया टन तक मिलता है, यानी २ रु० मन से भी अधिक । फिर यहां क्यों नहीं मिलता जब कि चीनी भी ज्यादा पैदा करें तथा देश की १/५ जनता का प्रतिनिधित्व भी करें, यानी यहां की जन-संख्या भी ज्यादा हो और प्रदेशों के मुकाबले इसलिये ऐसा मालूम होता है कि सिफारिश लिखी कई मगर कुछ जोर कम लगाया गया । यह कहते हैं कि केन्द्र हमारी बात भाव के बारे में नहीं मानता । मगर यह कैसे मान लिया कि ४ नवम्बर से जो फ़ैक्ट्री चलायी जायंगी उनको ४ आना मन का रिबेट मिल जायगा ? गन्ने का दाम किसान को पूरा मिलेगा मगर सरकार अपनी पाकेट से मिल वालों को रिबेट दे देगी । मजे की बात यह है कि शुगर मिल्स और खंडसारी की जब बात आती है उस समय हम देखते हैं कि सारे प्रदेश में खंडसारी वाले वह दाम देते हैं कि मिल के कांटे खाली पड़े रहते है और खंडसारी शुगर फ़ैक्टरियों पर गन्ने के ढेर लगे रहते हैं । आखिर क्या बात है ? ऐसी परिस्थिति शायद केन्द्र को बतायी नहीं गई ।.....

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, कुछ समय मुझे भी मिल जाय ।

श्री अधिष्ठाता---अब समय नहीं है । आप दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री शिवप्रसाद नागर---हम जब गन्ना बोते हैं तो हर एकड़ में ६० मन पक्का गन्ना बोते है, पैदा चाहे जितना हो । मगर मिल वाले जब १० मन गन्ना पेरते है तो उनकी १ मन चीनी पक्की है । हम तो भगवान भरोसे हैं, कहीं सूखा, कहीं रेडराट, कहीं गुजिया लगा करती है । आपको बताऊं कि १० एकड़ गन्ना क्वार में बोया लेकिन सिंचाई के साधन न होने से सूख रहा है और जब फ़ार्म का गन्ना देखते हैं तो खुद खड़े सूख जाते है और उनकी रिकवरी में कमी नहीं आती, हमारी पैदावार घटती चली जा रही है, दाम भी बढ़ रहे हैं । एक बात और कहूं कि शुगर टैरिफ़ बोर्ड यह कहता है कि गन्ने के दाम १ रुपये ४ आने मन उत्पादन में लगते है और जब गन्ने वाला अपनी गाड़ी में भर कांटे पर ले जाता है तो ३ आने मन उसको देने पड़ते हैं । तो इस तरह से लेने के बांट और हैं और देने के बांट दूसरे हैं । गन्ना खरीदते वक्त गन्ना पहुंचाने की जिम्मेदारी उत्पादक पर है और उसके लिये उसके दाम कट जाते हैं लेकिन जब शकर बन कर मिल से निकलती है तो शकर मिल गेट पर और रेट पर, स्टेशन पर और रेट पर और ज्यादा इंटीरियर तक पहुंचाने में और रेट पर बिकती है । यानी मिल मालिक ढुलाई का जिम्मेदार नहीं है । लखीमपुर तक आयेगी तो रेलवे फ्रैट लगाकर चीनी का दाम और बढ़ जायगा ।

हड़ताल के बारे में जिक्र कर दूं । हड़ताल के बारे में कांग्रेसियों ने कोशिश की कि हड़ताल न हो और यह भरसक कोशिश की कि हड़ताल के संबंध में नागर जी को गिरफ्तार न कर लिया जाय । पहले तो सातों सीटें हार गये । कहीं अब के गिरफ्तार कर लिया तो अब तक तो उत्तर प्रदेश की असेम्बली में पहुंचे हैं, फिर दिल्ली पहुंच गये तो बड़ा गजब हो जायगा, यह हमारा भट्ठा बैठाल देगा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अधिष्ठाता महोदय, गन्ने और शक्कर के व्यवसाय के संबंध में जितनी बातें यहां कही गयीं उन सबका जवाब देने के लिये बहुत ज्यादा वक्त चाहिये । अच्छा होता जिन माननीय सदस्यों ने इन बातों का जिक्र किया इस विषय का और थोड़ा अध्ययन कर लिये होते तो एक आध बात उनकी समझ में आ जाती । मसलन यह कि अगर उन्होंने इस बात पर खयाल किया होता कि दक्षिण भारत में शुगर के ऊपर कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है इस वजह से वहां के मैन्यूफेक्चरर्स जितनी कीमत दे सकते हैं गन्ने की उतनी कीमत उत्तर प्रदेश के मैन्यूफ़ेक्चर्स कभी नहीं दे सकते चाहे कितनी ईमानदारी से काम करें तब भी । दक्षिण भारत में २२-२३ रुपये कास्ट आफ़ प्रोडक्शन पड़ता है लेकिन पूरी कीमत ३६ रुपये में नहीं बेचते जबकि उत्तर प्रदेश में ३६ रुपये में बेचना होता है । अब अगर किसी को

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

२२–२३ रुपये कीमत पड़ती है और ३६ में बेचता है तो वह ज्यादा मुनाफा करता है और दूसरों को ज्यादा दे सकता है।

मैंने एक खत पढ़ा था, उसका बहुत जिक्र किया गया। मैं सदन का बहुत ज्यादा ख्याल करता हूं, इसलिये जिक्र किया उसका जिक्र न करता, शिकायत सुनता रहता, गाली खाता रहता लेकिन मैंने उस खत को पढ़ा एक वजह से। केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से कुछ लोग बार-बार यह गलत लफ़्ज का इस्तेमाल करते हैं कंसल्ट का जिसमें खामख्वाह भ्रम पैदा होता है। इसलिये मैंने उचित समझा कि जो सत्य जाने बिना लोगों को भ्रम पैदा हो गया है वह भ्रम दूर कर दिया जाय। वक्त होता तो मैं इन बातों का जिक्र करता कि जो उन्होंने मिल मालिकों को छूट दी है उसके संबंध में हमारी क्या राय थी, क्या हमने लिखा था। इसकी बाबत भी अगर वक्त होता तो मैं जिक्र करता कि पिछले साल ५३–५४ और ५४–५५ में मिल मालिकों को जो मुनाफ़ा हुआ है उस मुनाफ़े में गन्ने के प्रोड्यूसर्स को क्या हिस्सा मिलना चाहिये, किस तरीके से मिलना चाहिये, क्या उसका तरीका होना चाहिये, इन बातों के संबंध में क्या हमारा रुख था, इन बातों का मैं जिक्र करता लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं और वक्त भी नहीं।

एक सवाल यह हुआ कि जब प्रादेशिक सरकार को गन्ने के उत्पादकों के साथ सहानुभूति है तो फ़िर यह हड़ताल वगैरह जो हुई उसके संबंध में अमुक-अमुक प्रकार की बातें क्यों की गयीं। जो बातें की गयीं या नहीं की गयीं, उनकी बाबत यहां बहस नहीं हो सकती। कुछ सज्जन यहां ऐसे हैं जो स्वयं गिरफ्तार हुए थे। उनसे कहीं बड़ी संख्या उन लोगों की है जो गिरफ्तार हुए लेकिन सदन के अन्दर नहीं हैं। यदि एक-एक मामले का जिक्र किया जाय कि फ़लां साहब के साथ ऐसा बरताव हुआ, फ़लां के साथ ऐसा हुआ तो अगर ५–६ आदमियों के साथ बरताव की बाबत जिक्र किया जाय तो जो सौ, सवा सौ आदमी बाहर हैं उनके साथ जो बरताव हुआ उसका भी जिक्र करना चाहिये। अदालत में मामला चल रहा है, वहां सब बातें साफ़ हो जायंगी कि किसके साथ अन्याय हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ।

एक बात जरूर है। यह कहा गया कि जब आपको सहानुभूति थी तो फिर हड़ताल के लिये रोकथाम की बात क्यों हुई। जो माननीय सदस्य यहां हैं उनको कुछ बातों की छूट ज्यादा है, उतनी हमको नहीं है, वे कोई राय रख सकते हैं, उनकी राय किसी गवर्नमेन्ट को न पसन्द हो तो वे हड़ताल कर सकते हैं और भी जो चाहे कर सकते हैं। मगर हम तो किन्हीं कायदे कानूनों से बंधे हुए हैं। गवर्नमेन्ट हड़ताल नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेन्ट की समझ में ऐसी बात आती है कि ला एन्ड आर्डर जिसे कहते हैं, वैसे तो यह बहुत वाइड टर्म है, लेकिन ला ऐन्ड आर्डर के साधारण अर्थ सभी समझते हैं, अगर उसमें कोई बाधा पड़ती है तो चाहे उस उद्देश्य से जिस उद्देश्य से कुछ लोग काम करते हों सरकार को सहानुभूति भी हो फिर भी उसको रोकना उसका कर्तव्य होगा और उस कर्तव्य का पालन हम करेंगे। अगर किसी सभा सचिव ने या किसी और ने यह किया कि किसानों को जाकर समझाया कि तुमको हड़ताल नहीं करनी चाहिये, इस तरीके से कीमत नहीं बढ़ने वाली है तो उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बाकी हड़ताल एक और वजह से भी हमको पसन्द नहीं हो सकती। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सारे देश में जो शकर पैदा होती है उसका ५२ या ५५ प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। अब ५२, ५५ के दिन चले गये। अब वह संख्या घटकर ४५ के करीब आ गयी है और जो रास्ता है अगर ऐसा ही रहा तो शायद और भी घट जाय और अगर किन्हीं वजहों से उत्तर प्रदेश में शकर नहीं पैदा होती तो एक तरफ़ उन किसानों का नुकसान होगा जो गन्ना बोते हैं और दूसरी तरफ़ लाख, दो लाख उन आदमियों का नुकसान होगा जो शकर की मिलों में काम करते हैं और तीसरी तरफ़ सारे देश का नुकसान होगा जिस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में पैदा हुई शकर पर निर्भर करता है।

हड़ताल करना लोगों का एक कानूनी हक है। अगर लोग हड़ताल करते हैं तो हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम हड़ताल मत करो, केवल समझा सकते हैं। अब यह हड़ताल कहां तक स्पांटेनियस थी, कहां तक लोगों ने जबरदस्ती गन्ना ले जाने से रोका, कहां तक और तरीके अख्तियार किये गये, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, किसी के दिल को दुखाना भी नहीं चाहता और कोई खास फ़ायदा भी नहीं है। बहरहाल, हड़ताल के कानूनी हक को मानते हुए भी अगर हमको यह दिखाई पड़े कि गलत काम हो रहा है तो गवर्नमेन्ट का उसको रोकना कर्त्तव्य है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे कोई जरूरत नहीं है। माननीय झारखंडे राय ने यह कहा था कि आप कोई ऐसा रास्ता बतावें जिससे गन्ना काश्तकारों को हम कुछ दिला सकें, ऐसा नहीं है कि हम इसको सोचते नहीं हैं। सोचते हैं और मेरा विश्वास है कि संविधान के अन्दर रहते हुए ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे काश्तकार की उन मांगों को, जिनको हम उचित समझते हैं बहुत दूर तक मनवा सकते हैं। लेकिन जहां पर यह वातावरण हो कि अमुक लोग मिल वालों के साथ षडयंत्र करते हैं, जहां नीयत पर विश्वास न हो, वहां एक मिनट के लिये भी ऐसी राय पेश नहीं की जा सकती है जिसमें मिलकर काम करने की बात हो। मैं जानता हूं और ऐसा रास्ता निकल सकता है और जिस मामले में हम लोग और विरोधी पक्ष के लोग एक राय हों तो जरूर उसको पूरा करा सकते हैं। लेकिन अविश्वास के वातावरण में ऐसी बात का जिक्र करना बेकार है। काश्तकार के हित करने की बात दूसरी है और विज्ञापन करने की बात दूसरी है। जो हमसे बन पड़ेगा वह हम अकेले करेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२९ दिसम्बर, १९५९।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२५३ एल० ए०—१९६०—८४५।